हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

6 मार्च, 1997

खण्ड 1, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 6 मार्च, 1997

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(1)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	(1)16
तारंकित प्र ानों के लिखित उतर	
स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्शण प्रस्ताओं आदि की सूचनाएं	(1)20
गैर सरकारी प्रस्ताव–	
आगरा कैनाल का प्र ाासनिक नियंत्रण अपने अधिकार में लेने तथा हरियाणा, राज्य का पानी का हिस्सा बढ़ाने संबंधी।	(1)26

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 6 मार्च, 1997

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो0 छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान अब सवाल होंगे।

Completion of Harijan Chaupals

195. Shri Raj Dewan: Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state-

(a) whether it is fact that the Harijan Chaupals of following villages of Sonipat District are incomplete:-

(i) Sandal Kalan

(ii) Tharu Uledpur

(iii) Panana

(iv) Mahara

(v) Khirajpur Majra

(vi) Sandal Khurd

(vii) Badwasani

(b) if so, the time by which the aforesaid Chaupals are likely to be completed?

Development Minister (Shri Kanwal Singh):

(a) It is correct that Harijan Chaupals of all these villages except Sandal kalan are incomplete. The Construction of the Harijan Chaupal of Sandal Kalan has been completed.

(b) No request for funds for completion of these chaupats has been recerived from the Villages. Therefore, the time frame for their completion cannot be indicated.

श्री देव राज दीवानः अध्यक्ष महोदय मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह महसूस करते है कि उनका इस सवाल का जबाव ठीक है? क्या सदन इस सवाल के जबाव से सहमत है?

श्री अध्यक्षः आप इस बारे में मंत्री जी से पूछें।

श्री देवराज दीवानः सर, मै मंत्री जी से ही आपके माध्यम से पूछ लेता हूं कि सोनीपत जिले में कितने गांव में हरिजनों की चौपालें अधूरी पड़ी है और क्या वजह है कि अभी तक इन चौपालों को पूरा करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया?

श्री कंबल सिंहः स्पीकर सर, कितनी हरिजन चौपालें सोनीपत जिले में अधूरी हैं यह तो मैं इस समय नहीं बता पाऊंगा

लेकिन मै इनको यह अव य बताना चाहूंगा कि सोनीपत जिले में हमने 202 हरिजन चौपालों को बनवाने के लिए ग्रांटस दी है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, इन चौपालों को पक्का करने के लिए कम्पली ान करने के लिए कुछ ग्रांट्स तो सो ाल बैलफेयर डिपार्टमैंट की है और कुछ एस0 सीज0 बैलफेयर डिपार्टमैंट की है। मैं यह जानना चाहूंगा कि जो चौपालें अभी अधूरी है उनकी कम्पली ान कराने की रा ि ा अब कितनी है और क्या अब यह रा ि ा इक्रीज हो गयी है क्योंकि अब तो पहले के मुकाबले मंहगाई भी बहुत बढ़ गयी है? इसके अलावा मंत्री जी ये भी बताएं कि इनके लिए आपके जो अपने फंडज है उनको आप पूरा मानते है और क्या आपने इन हरिजन चौपालों को पूरा करवाने के लिए सो ाल वैल्फेयर डिपार्टमैंट से कोई टाईअप किया है?

श्री कंवल सिंहः अध्यक्ष महोदय, जिनके तहत इन चौपालों को पूरा करने के लिए रा ि ा दी जाती थी वह तीन स्कीम्ज है। ये है– हरिजन चौपाल सबसिडी स्कीम, हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट फंड स्कीम जो कि अभी आयी है और तीसरी स्कीम डिसक्रि ानरी ग्रांट है जिसके तहत इन चौपालों को ग्रांट दी जाती है। सो ाल वैल्फेयर डिपार्टमैंट के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके तहत इन चौपालों को पूरा करने के लिए ग्रांट दी जाती हो (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, पहले 1977 में दस हजार और पांच हजार की स्कीम थी लेकिन बाद में 1993–94 में इसको

बढ़ाकर बीस और दस हजार रूपये कर दिया गया है वह स्कीम चौपालों को बनाने व पूरा करने के लिए थी लेकिन इस सरकार ने आने के बाद 1996–97 से इस रा ि ा को बढ़ाकर सवा लाख नयी चौपलों को बनाने के लिए 50 हजार बन रही चौपालों को पूरी करने के लिए 25 हजार रूपये उनकी रिपेयर के लिए दिया है।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ): अध्यक्ष महोदय, मै इस बारे में कुछ बताना चाहूंगा। सर, नयी चौपाल बनाने के लिए सवा लाख रूपये निधारित किए गये है और जो चौपालें अधूरी है उनके लिए पचास हजार रूपये रखे गये हैं तथा इनकी रिपेयर के लिए पचीस हजार रूपये रखें है। पहले यह अमाउंट बहुत कम था जिसकी वजह से ये चौपाल पूरी नही हो पाती थी। लेकिन अब यह ग्रांट्स बढ़ा दी गयी है और अब तीन कैटेगरी की तहत इनको ग्रांट्स दी जाती है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, दोनो मंत्रियों में से किसकी बात सही माने।

श्री जगन नाथः दोनो के जबाब एक है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ इतना कहना था कि भी स्कीम डिस्ट्रिक्ट से आती है अनकम्पलीट को कम्फलीट कराने की तो उसके लिए पंचायंत डिपार्टमैंट यह कहकर इंकार कर देता है कि हमारे पास पैसा नही है। जैसा मैने बताया है कि

पैसा बैलफेयर डिपार्टमैंट के पास बहुत है। मैने यह पूछा है कि क्या आपका टाईअप है?

श्री कंवल सिंहः सो ाल वैलफेयर डिपार्टमैंट के पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो कि हरिजन चौपाल के लिए पैसा दे दे।

श्री राम पाल माजराः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राज्य में वर्श 1996–97 में कितनी नयी चौपालें बनाई गई है और कितनी चौपालों की मरम्मत की गई है?

श्री कंवल सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह सवाल केवल सोनीपत जिले के लिए है ये उसके बारे मे पूछना चाहें तो कुछ सकते है।

श्री रमे ा कुमारः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में हल्कावाइज कितनी हरिजन चौपालों के लिए ग्रान्ट दी गई कितनी अधूरी पड़ी है और कितनी चौपालों की मरम्मत की गई है उसके बारे में विवरण दें?

श्री कंवल सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यदि ब्लौकवाइज पूछना चाहें तो बता सकता हूं।

श्री रमे ा कुमारः मुढलाना ब्लौक और कथूरा ब्लौक के बारे मे बता दें।

श्री अध्यक्षः वैसे इन क्वे ाचन से यह सवाल रिलेटेड नहीं है फिर भी यदि आपके पास विवरण है तो बता दें।

श्री कंवल सिंहः सर, मेरे पास ईयर वाइज और विलेजवाइज डिटेल है वह मैं बता सकता हूं।

Canal Based Water Supply Scheme for Rewari

204. Capt. Ajay Singh Yadav: Will the Minister for public Health be pleased to state-

(a) the details of the allocated for the constrution of the Canal Based Water Supply Scheme (Village Kalaka) for Rewari City during the years 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96 and 1996-97; and

(b) the time by which the said scheme is likely to be complted?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ):

(क) रिवाड़ी भाहर के लिए नहर आधारित जल आपूर्ति योजना (गांव कालाका) के निर्माण के लिये विनिहित की गई निधियों का ब्यौरा निम्न अनुसार है:–

वर्श	विनिहित की गई रा ि ा (रूपये लाखों में)
1992–93	62.50

1993–94	85.00
1994–95	–
1995–96	30.00
1996–97	52.00
योगः	229.50

(ख) योजना का कार्य 30–6–96 का पूर्ण हो गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूगा कि यह जो स्कीम थी वह कितनी फेज मे बननी थी क्योंकि इसमें फेज–1 और फेज–2 थे और फेज 2 के तहत जो टैंक बनने थे वह बन पाए या नही? मंत्री महोदय, ने अपने जवाब में यह कहा है कि यह स्कीम पूरी हो चुकी है यह अनुचित है क्योंकि फेज–2 बकाया है। जो टैक बने हैं उनकी कितनी क्षमता है और जो बनने हैं वह कितनी क्षमता के बनने है?

श्री जगन नावः स्पीकर सर, दिनांक 8–8–89 को 3 करोड़ 47 लाख की स्कीम मंजूर हुई थी। उसमें हमने 65 लाख रूपया कम खर्च किया है। इसमें हमने ऑग्मैन्टे ान करना था और दोबारा टैंक बनाने थे। वह क्यों नही बनायें? इसके लिए मै आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहले रेवाड़ी भाहर को साहबी नदी के जारिए 27 दिन में पानी मिलता था इसलिए ज्यादा पानी इकट्ठा करने के लिए टैंको की जरूरत होती थी। लेकिन

जब यह नई सरकार बनी तो नई सरकार ने रजबाहों की सफाई करने के प चात् टेलों तक पानी पहुंचा दिया जिसके कारण 27 दिन की बजाय रेवाड़ी भाहर का 15 दिन में पानी मिलने लग गया। इसलिये जिन टैकों की पहले जरूरत थी वह अब नहीं रही और दूसरा टैक न बनाकर हमने लगभग 65 लाख रूपये की बचत कर ली है और जितनी जरूरत है उसके हिसाब से रेवाड़ी भाहर की जरूरत को पूरा कर दिया है। आज रेवाड़ी में 110 लीटर पर व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पानी मिल रहा है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैने मंत्री जी से यह प्र न किया है कि इस समय रेवाड़ी को पानी की कितनी आव यकता है और इन स्कीम के तहत कितना पानी दे रहे है और जितनी भाहर को पानी की जरूरत है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। और जो दूसरे फेज में टैंक बनना था वह क्यों नहीं बना है और मसाणी ब्रिज से या कैनाल बेसड स्कीम के तहत जी पानी मिलना था वह क्यों नहीं मिल पर रहा है?

श्री जगन नाथः अध्यक्ष महोदय, पहले रेवाड़ी भाहर को साहबी नदी से पम्पिग सिस्टम के द्वारा पानी की सप्लाई की जाती थी लेकिन 1989 के बाद वाटर वर्कस बनने के बाद 110 लीटर पर डे पर व्यक्ति वाटर वर्कस से कैनाल वेसड पानी टैकों द्वारा मिलने लगा और साहबी नदी का पानी टयूबवैल द्वारा 70 फीसदी आबादी को मिलने लग गया है जितनी रेवाड़ी भाहर की आबादी है उसमें 70 फीसदी की जो आबादी है उसमें से 110 लीटर प्रतिदिन पर

व्यक्ति को पानी मिलता है। परन्तु कुछ ऐरिया ऐसा रह गया है जहां छोटी–छोटी ढाणियां बनी हुई है जैसे आनन्द नगर, आजाद कालौनी आदि जिनकी आबादी 12 हजार के करीब है जहां पानी की कमी है उनको जल्दी ही पानी मिलने लग जाएगा क्योंकि ये कालोनियां अन अथोराईज्ड बनी हुई थी इसलिए थोड़ा टाईम लग गया। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादवः ये दूसरा फेज बंद क्यों कर दिया और रेवाड़ी भाहर को कितने पानी की रिकवायरमैंट है। भाहर को पानी क्यों नहीं मिल रहा है। इस स्कीम का पैसा जानबूझ कर क्यों काट दिया गया?

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप बैठिए मैने आपको दो बार सप्लीमैंटरी पूछने का मौका दिया फिर भी आप बीच में बोलते जा रहे है। कम से कम चेयर की इजाजत तो लेनी चाहिए। आप वैसे ही बीच में खड़े होकर बोलने लग जाते है।

श्री जगन नाथः अध्यक्ष महोदय, यह सीधी सी बात थी इनको जो पानी पहले 27 दिन में मिलता था वह अब 15 दिन में मिलने लग गया है, इसलिए दूसरे टैंक की जरूरत ही नही रही। अगर जरूरत होती तो हम जरूर बनाते हमको इनसे कोई दु मनी थोड़े ही है। कोई दुर्भाबना नही है।

Repair of the Bullding of P.H.C./C.H.C.

210. Shri Sat Narain Lather: Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the that the bulidings of PHC Shamlo Kalan and CHC Julana are in dilapidated condition; and

(b) if so, the time by which the aforesaid buildings are likely to be repaired?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा महाजन):

(क) जी, हां।

(ख) भवन की मुरम्मत वर्श 1997–98 में आरम्भ की जाएगी।

श्री सत नारायण लाठर: अध्यक्ष महोदय, अभी अभी 27 फरवरी को माननीय स्वास्थ्यमंत्री जुलाना में गए थे। वहां पर जगह की तंगी है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से माध्यम से अनुरोध है कि इसके साथ लगती सरकारी जमीन, जो बी0 डी0 पी0 ओ0 ऑफिस को ि ाश्ट करके वहां पर सी0 एच0 सी0 आई बनाई जाए। इससे बनाई जाए। इससे लोगों को सुविधा हो जाएगी।

श्री ओम प्रका ा महाजन: वैसे महोदय, जुलाना में वैसे तो पहले ही सी0 एच0 सी0 है और भाामलों कलां मे जमीन पंचायत की है। वहां पर ये फ्री ऑफ कास्ट जमीन हमें दिलवा दे तो हम यह अस्पताल वहां चालू करवा दें गे।

श्री सत नारायण लाठरः हम दिलवा तो दें लेकिन वहां पर जगह की तंगी है।

श्री ओम प्रका ा महाजनः वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि भाामलों कलां के लिए हमने 293600 रू0 एस्टिमेंट तैयार करवाया है और जुलाना के लिए 268000रू0 का एस्टिमेट तैयार करवाया है तथा अप्रैल से पहले हम वहां पर कार्य भाुरू कर देंगे।

श्री जगदी ा नैयरः अध्यक्ष महोदय, मै सप्लीमैंटरी पूछना चाहता हूं। मेरे हल्के मे बहुत से हस्पताल ऐसे है जहां पर अभी तक स्टाफ नहीं है। इस बारे में मंत्री जी क्या कार्यवाही कर रहे है?

श्री ओम प्रका ा महाजनः अध्यक्ष महोदय, मै माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हाल ही में 205 नए डाक्टरों की नियुक्ति की गई है तथा आगमी 10–15 दिन के अन्दर उनकी पोस्टिग कर दी जाएगी। जहां कही भी स्टाफ की कमी है, वह सब अप्रैल के महीने तक पूरी दी जाएगी।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मेरे हल्के में गांव भैसवाल में पी0 एच0 सी0 बनी हुई है तथा गांव रूखी में पी0 एच0 सी0 अंडर कंसीड्रे ान है। यह पी0 एच0 सी0 वहां पर कब तक चालू कर देंगे?

श्री ओम प्रका ा महाजनः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इनका प्र न उक्त तारंकित प्र न से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी मै इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम इसका सर्वेक्षण करवा रहे है और 5000 की आबादी तक एक सब सैंटर 30 हजार की आबादी तक एक पी0 एच0 सी0 और 120000 की आबादी तक एक सी0 एच0 सी0 खोलने जा रहे है।

श्री मनी रामः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में गांव गोरी वाला में एक सी0 एच0 सी0 है तथा वहां पर दो डाक्टरों की पोर्स्ट भी स्वीकृत है लेकिन ये पोस्टे एक साल में खाली पड़ी है। इस बारे में मंत्री जी क्या करने जा रहे है?

श्री ओम प्रका ा महाजनः अध्यक्ष महोदय, मै इनको बताना चाहता हूं कि अप्रैल माह के अंदर अंदर जितने भी अस्पताल या पी0 एच0 सीज वगैरह है सभी जगह जहां कही भी स्टाफ की कमी है, पूरी कर दी जाएगी।

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै एक सप्लीमैंटरी पूछना चाहता हूं। मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं। कि मेरे हल्के बादली मे पी0 एच0 सी0 का भवन बनकर तैयार हो गया है और पहले भी किन्ही कारणों से वहां पर स्टाफ ट्रांसफर नहीं किया गया, बिल्डिंग को भी हैड ओवर नहीं किया गया और पिछले करीबन डेढ़ साल से नया भवन खराब हो रहा है। बच्चों ने उसके भी ा वगैरह भी तोड़ दिए है। मै लायक मंत्री

जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इस विरोधी पक्ष की भावना से हटकर उस नए भवन में कार्य भाुरू करने की जरूरत है क्योंकि पिछले दो साल से हम देख रहे है, यह भवन बर्बाद हो रहा है।

श्री अध्यक्षः चौधरी मनी राम जी मैने अभी आपको सप्लीमैंटरी पूछने का मौका दिया था इसलिए आप इस तरह बैठे बैठे न बोले। अगर आपने कोई बात पूछनी है तो खड़े होकर आप मेरे से बोलने की इजाजत लें।

श्री ओम प्रका ा महाजनः अध्यक्ष महोदय, मैं माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की कभी भी कतई तौर पर यह नीति नही रही कि हम किसी के साथ कोई पक्षपात करें। हमारी सरकार जैनुअन काम करेगी चाहे यह विपक्ष के माननीय सदस्य का काम हो और चाहे सता पक्ष के माननीय सदस्य का काम हो। सभी के साथ बराबर इन्साफ करैंगे। हमें हमारे मुख्य मंत्री जी काा यह आदे ा है। हम भवनों के निर्माण पर 3 करोड़ 53 लाख रूपया खर्च करने जा रहे हैं जिसमैं 10 होस्पीटल, 9 सी0 एच0 सी0 और 25 पी0 एच0 सी0 की बिल्डिंग के निर्माण का काम किया जाएगा जिनमें आपकी भी भाामिल है।

श्री कृश्ण लालः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदे ा के अंदर ऐसी कितनी सी0 एच0 सी0, पी0 एच0 सी0 और आर0 डी0 है

जिनके अंदर स्टाफ सरप्लस है और जिनके अंदर स्टाफ की भाार्टेज है। मंत्री जी इसका जिलेवार ब्यौरा देने की कृपा करें।

श्री ओम प्रका ा महाजनः स्पीकर सर, इस समय मेरे पास पूरी स्टेट का ब्यौरा है वह मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं लेकिन यदि ये जिलेवार ब्यौरा जानना चाहते हैं तो इसके लिए अगल से नोटिस दे दें।

Mr. Speaker: Krishan Lal Ji this question does not relate to it.

श्री बलबीर सिंहः स्पीकर साहब, महम हल्के के गांव बलम्बा और गांव मोखरा की पी0 एच0 सीज0 कई महीनों से तैयार है लेकिन उनमें स्टाफ नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने दो बार हाऊस में आ वासन दिया था उनमें स्टाफ जल्दी भेज दिया जाएगा लेकिन उनमें आज तक स्टाफ नहीं गया है। क्या चौधरी भजन लाल जी की तरह चौधरी बंसी लाल जी भी झूठे वायदे करने लग गए हैं। उन दोनों पी0 एच0 सीज0 में स्टाफ कब तक भेज दिया जाएगा?

श्री ओम प्रका ा महाजनः अध्यक्ष महोदय, मैने पहले निवेदन कर दिया है कि हमारी सरकार किसी भी माननीय सदस्य के हल्के मे पक्षपात की दृश्टि से काम नहीं करती चाहे वह हल्का विपक्ष का हो। हमारी सरकार निश्पक्ष रूप से काम करती है किसी के साथ पक्षपात कतई तौर पर नहीं करती। बाकी रही बात बलम्बा

और भोखरा पी0 एच0 सीज0 की हम उनको भी कंसीडर कर रहे है।

श्री सिरी कृश्ण हुड्डा: स्पीकर साहब, कलोई की पी0 एच0 सी0 की बिल्डिंग पिछले 5–6 साल से टूटी पड़ी है और न वहां स्टाफ है। मै मानीनय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस पी0 एच0 सी0 की नई बिल्डिंग बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है।

श्री ओम प्रका ा महाजन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि हम 10 होस्पीटल, 9 सी0 एच0 सी0 और 25 पी0 एच0 सी0 की बिलिडंगज बनाने जा रहे है। जिस पी0 एच0 सी0 की बिल्डिंग ठीक नहीं है और जहां पर डाक्टर की कभी है वह हमें माननीय सदस्य लिख कर दे दें उस पर हम तुरंत कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 22 दिसम्बर 1995 को उस समय के मुख्यमंत्री मेरे गांव बौंद कला में गए थे और उस समय उन्होंने कहा था कि बौद कलां गांव की सी0 एच0 सी0 के लिए हमारी सरकार ने 1 करोड़ 45 लाख रूपये मंजूर कर दिए है। क्या वहां पर सी0 एच0 सी0 बनाने के बारे में आपकी कोई स्कीम है?

श्री ओम प्रका ा महाजन: अध्यक्ष महोदय, इस समय मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि उस समय की सरकार ने

उस सी. एच. सी. के लिए 1 करोड़ 45 लाख रूपये मंजूर किए थे या नही। इस बारे में मैं फाइल मंगवा कर देख लूंगा।

श्री अध्यक्षः आप फाइल देख कर सोमवार को इस बारे में बता दें।

श्री ओम प्रका ा महाजनः ठीक है जी।

श्री भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हमने बौद कलां गांव में सी0 एच0 सी0 बनाने के लिए। करोड़ 45 लाख रूपये मंजूर भी किए थे और उस गांव को सब–तहसील भी बनाया था लेकिन इन्होंने उस सब–तहसील को तोड़ दिया और उस पैसे का भी पता नहीं कहां गया।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, अगर इनका राज फिर आ जाता तो हर गांव में हर गांव का लड़का डी0 सी0 लगा हुआ मिलता। (हंसी)

Brigadier Hoshiar Singh Stadium

245 Sh. Nafe Singh Rathee: Will the Minister for Sprorts be pleased to state the time by which construction work of tate Brigadier Hoshiar Singh Stadium is likely to be completed?

खेल राज्य मंत्री (श्री राम सरूप रामा): स्वर्गीय ब्रिगोडियर होि ायार सिंह स्टेडियम, बहादुरगढ का प्रथम चरण

का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। बाकी का जो काम रह गया है वह अगले वित वर्श में पूरा कर दिया जाएगा।

श्री नफे सिंह राठी: स्वर्गीय ब्रिगेडियर होि ायार सिंह स्टेडियम, बहादुरगढ़ का प्रथम चरण पूरा होने के बारे में बताया कि वह पूरा हो चुका है। इस बारे में मै सदन की जानकारी के लिए मै बताना चाहूंगा कि वहां का पूरा कार्य नहीं हुआ है। वहां पर अभी तक सिर्फ दो कमरें बने है। सीढियां भी नही बनाई गई है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वहां पर बैठने के लिए सीढियां बनाने का कोई प्रस्ताव है और वहां पर कितनी द र्कि दीर्घा का स्टेडियम बनाया जा रहा है? साथ ही साथ भी बता दें कि वहां पर किन किन खेलों का आयोजन किया जाया करेगा।

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है उस बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस स्टेडियम का प्रथम चरण का काम पूरा किया जा चुका है। एक सवाल यह किया कि वहां पर केवल दो कमरे बनाये गए हैं। मै बताना चाहूंगा कि वहां पर कमरों के अलावा स्टेज भी बनाई गई है। सीढियों का निर्माण भी किया जाना है। वहां पर अब एम. पी. ग्रांट से 3 लाख रूपये और चन्दे के रूप में 1.92.788 रूपये आए है इसके अलावा खेल विभाग ने वहां पर 50 हजार रूपया दिया है।

Income Accrued from Commercial Taxes

229. Shri Krishan Lal: Will the Minister for Commercial Taxes be pleased to state the total income accrued to the State Government from Commercial Taxes during the years 1995-96 and 1996-97, separately?

भाहरी तथा नगर योजना मंत्री (सेठ सिरी कि ान दास): राज्य सरकार को वर्श 1995.96 तथा 1996–97 के दौरान वाणिज्यिक करों से कुल आय अलग–अलग निम्न प्रकार से प्राप्त हुई है:–

		(रूपये करोड़ो में)
1.	वर्श 1995–96 के दौरान वाणिज्यिक करों से प्राप्त कुल आया	1276.98
2.	वर्श 1995–96 के दौरान वाणिज्यिक करों से प्राप्त कुल आया	1307.97
(31 जनवरी, 1997 तक)		

श्री कृश्ण लाल: अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि वर्श 1995–96 के दौरान 1276.98 करोड़ और वर्श 1996–97 में 31 जनवरी तक 1307.97 करोड़ रूपये प्राप्त हुए बताए है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में फैसला आने के बाद कितनी रा ि ा प्राप्त हुई है और केन्द्र

सरकार द्वारा पैट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने के बाद कितनी रा ि ा प्राप्त हुई है।

सेठ सिरी कि ान दासः मेरे पास अलग–अलग फिगर्ज तो हैं कि किन किन आईटम्ज पर टैक्स घटाया बढ़ाया गया है। मै बताना चाहूंगा कि टैक्स चोरी करने वालों हमें ज्यादा पैसा वसूल हुआ है।

श्री कृश्ण लालः अध्यक्ष महोदय, पिछली सप्लीमैट्री में मैने एक साथ दो सवाल पूछे थे लेकिन मंत्री महोदय ने मेरे सवाल का सन्तोशजनक उतर नहीं दिया है। अतः आपके माध्यम से मेरी गुजारि ा है कि मंत्री जी मेरे पूछे गए प्र नों का उतर दें।

सेठ सिरी कि ान दासः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सवाल पूछा है उसका जबाव मैने दिया है। इनका सवाल यह था कुल कितनी आय हुई तो मैने इनकी आय बताया है कि 1307 लाख रूपये की आय जनवरी तक हुई है अभी दो महीने का समय भोश पड़ा है (विघ्न) अगर ये पूरी ब्रेक–अप चाहते है तो उसके लिए अलग सवाल पूछें। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक स्पैसिफिक सवाल पूछा है लेकिन उस सप्लमैंट्री के जवाब नहीं आया है (विघ्न) माननीय सदस्य का सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो पैसा वसूल हुआ है वह कितना है, इस बारे में मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है (विघ्न)

ि ाक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, मै अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि राईस भौलरों के मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पैटी ान की हुई थी उस निर्णय के अनुसार 91 करोड़ रूपये की रा ि ा सरकार के पास जमा करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राईस भौलर के मालिकों को कहा है और इसके साथ ही वह रिट खारिज हो गई है। सुंप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें पैसा सरकार के पास जमा करवाना चाहिए। राईस भौलरों के लोग माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले और लगभग 45 करोड़ रूपये उन्होंने 31 मार्च तक जमा करवाने का आ वासन भी दिया है और पैसा जमा भी करवाया है। ऐसोसिये ान के लोगों ने 50 करोड़ के लगभग रूपया 31 मार्च तक जमा करवाने तथा बाकि रकम को कि तों में जमा करवाने के लिए अनुरोध किया है और बाकि का पैसा कि तों में वे लोग जमा करवाएंगे इतनी ही आमदनी इससे हुई है। (विघ्न)

श्री धीर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो प्रभाव ाली लोग हैं उनसे एक भी पैसा जमा नहीं हुआ है (विघ्न एवं भाोर)

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रभाव ाली व्यक्ति पैसा देने से बचा है या कोई पैसा जमा नहीं हुआ है। कुछ पैसा तो वे 31 मार्च तक जमा करवा देने बाकी के पैसे की कि तें कर दी गई है। ऐसा भी नही होना चाहिए कि सरकार उनको एकमु त पैसे के लिए कहे जिससे

उनका रोजगार भी मारा जाए और सरकार का पैसा भी मारा जाए। इसी बात को मद्देनजर रख कर कि तें की गई है।

Aids

215. Dr. Virender Pal Ahlawat: Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) the details of the amount of grant. if any received by the State Govrnment for the prevention/cure of AIDS from Government of India during the year 1996-97; and

(b) whether the aforesaid grant has been fully utilised, if not the reasons thereof?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा महाजन):

(क) 80.00 लाख रूपये निम्मलिखित सारणी अनुसार प्राप्त हुये:–

(1)	दिनांक 4 जून, 1996	25.00 लाख
(2)	दिनांक 7 जून, 1996	45.00 लाख
(3)	दिनांक 29 जनवरी, 1997	10.00 लाख

(ख) माह जनवरी, 1997 तक 4561054 रूपये खर्च किये जा चुके है। भोश रा ि दिनांक 31–3–1997 तक खर्च करने की सम्भावना है।

डा0 बीरेन्द्र पाल अहलावतः अध्यक्ष महोदय, ऐड्ज का जानलेवा बीमारी है। मै आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या सिविल होस्पिटल में या मैडिकल कॉलेज में इस बीमारी के मरीजों के लिये कहीं बैड्ज का प्रावधान किया गया है, अगर हो तो उसका ब्यौरा क्या है। अध्यक्ष महोदय, यह बीमारी एक मारक बीमारी है और इसके इलाज के लिए पार्टिकुलरली एक एक्विपमैंट आता है। जिसका नाम सी डी–4 है, क्या मंत्री महोदय, यह बताएंगे कि किसी सिविल अस्पताल अथवा मैडिकल कॉलेज में यह इन्सटूमेंट है या नहीं है। इसके साथ ही मेरा सवाल यह भी है कि 45 लाख रूपये की रा ि ा जो दवाईयों पर खर्च की गई है उसमें से कितनी रा ि ा जुवेरेडीन पर, जो कि इस बीमारी के इलाज के लिये इस्तेमाल होती है, खर्च की गई है?

श्री ओम प्रका ा महाजनः माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो सवाल किया है यह एक अहम सवाल है। इस बीमारी से लाखों करोड़ो लोगों की जिन्दगी खराब हुई है, भगवान करें कि यह बीमारी न फैले। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मै इनके सवाल के जवाब के साथ–साथ इस बीमारी के बारे में विस्तार से बता देता हूं। इसकी भूमिक बता देता हूं जिन कारणों से यह बिमारी फैलती जा रही है।

श्री अध्यक्षः महाजन जी आप इनके सवालों का जवाब ब्रीफ में बता दें।

श्री ओम प्रका ा महाजनः अध्यक्ष महोदय, मै आपके जरिए से इनको यह बताना चाहूंगा कि इस बीमारी की कोई दवाई नहीं है। जब यह बिमारी लगती है तो कोई भी दवाई असर नही करती है और आज इस बीमारी को रोकने के लिये कई भी दवाई बनी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 1986 के अन्दर आज के मुख्यमंत्री ही उस समय मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त तामिलनाडू में चेनाई गांव में पहली बार एडस का पे ान्ट पाया गया और पता चला कि यह बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने रोहतक मैडिकल कॉलेज के अन्दर एडस की रोकथाम के लिये एडस को टैस्ट करने के लिए एक सैन्टर खोला। सारे भारत में 31 जनवरी 1997 तक 29 लाख 30 हजार 718र टैस्ट किये गये हैं और 49 हजार 883 पोजिटिव टैस्ट पाये गये हैं। सारे भारत में एक हजार के पिछे 17 पे ान्ट एडस से ग्रस्त पाये गये है और हरियाणा में एक हजार में एक हजार के पीछे पौने दो लोग है। हरियाणा के अन्दर जनवरी 1997 तक 1 लाख 34 हजार 145 टैस्ट किये गये हैं और 257 लोगों का टैस्ट पोजिटिव पाया गया। अध्यक्ष महोदय, यह टैस्ट दो दफा किया जाता है जब दूसरी दफा टैस्ट किया गया तो 257 लोगों का टैस्ट पोजिटिव पाया गया। अध्यक्ष महोदय, यह टैस्ट दो दफा किया जाता है जब दूसरी दफा टैस्ट किया गया तो 257 में से 231 केस ही पोजिटिव के रह गये।

डॉ0 बीरेन्द्र पाल अहलावतः अध्यक्ष महोदय, मेरे 3 सवालों में से एक का भी जबाव नही आया है। एक तो ये मेरे

सवालों का जवाब दे दें। इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब हरियाणा में भी एक हजार के पीछे 17 लोग एडस से ग्रस्त हो जाएंगे तभी ये इस बारे में कुछ ऐक ान लेंगे या अभी लेगे ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा जब इन्होंने खुद ही माना है कि इसकीह कोई दवाई नहीं है तो यह जो पैसा खर्च हुआ है वह कहां पर खर्च हुआ है।

श्री ओम प्रका ा महाजनः आपने ठीक बात पूछी है। आज लोगों को इस बारे में जागरूक करके इस बीमारी से बचाया जा सकता है। आमतौर पर एड्स कैसे फैलती है इसके मुख्यतःतीन कारण है न. 1 यौन प्रक्रिया से न. 2 एडस से ग्रस्त मां के पेट मे बच्चे को और नं0 3 किसी एड्स वाले मरीज का खून दूसरे को चढ़ाने से इसके अलावा मेरे पास सरकार का ब्यौरा है कि पैसा कहा पर खर्च होता है। हमने यह पैसा 1650 डाक्टरों, 1490 नर्सिज और 976 वर्कर्ज की ट्रैनिंग पर खर्च किया इसके अलावा प्रचार करने में भी पैसा खर्च होता है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सब बैठ जाएं।

श्री अनिज विजः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने अपना उतर देते हुये बताया कि यह बीमारी तीन कारणों से फैलती है। उन कारणों में से कारण यह बताया कि यह बीमारी बल्ड ट्रांसफयूजन से फैलती है तो क्या हरियाणा मे इसको टैस्ट करने क प्रावधान है? इसके अतिरिक्त जो प्राईवेट होस्पीटल्ज है वहां पर

जो ब्लड ट्रांसफयूजन किया जाता है वह बिना टैस्ट के किया जाता है तो क्या उनको रोकने के लिये भी सरकार ने कोई कदम उठाया है?

श्री ओम प्रका ा महाजनः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि एड्स को रोकने के लिये क्या कोई ब्लड टैस्ट सैंटर है या नही, मै इनको बताना चाहूंगा कि अगर हमारे यहां पर ये ब्लड टैस्ट सैंटर नहीं होते तो हम इतने मरीजों को कैसे ढूंढ पाते। इन मरीजों को ढूंढने का तरीका तो यही है कि उनका ब्लड टैस्ट किया जाता है। सर, इस समय हमारे यहां पर 19 जगहों पर ब्लड टैस्ट किया जाता है। 17 सैंटर तो हमारे जिलों में है और एक एक सैंटर मिलिट्री के कैम्पल में जैसे चंडी मंदिर में एव अम्बाला कैंट में है। जहां तक प्राईवेट होस्पीटल्ज में ब्लड टैस्ट करने की बात है तो हमारे ड्रग इंसपैक्टर या ड्रग कंट्रोलर समय समय पर अलग अलग इनकी चैंकिग करते रहते है और अगर इस प्रकार की बातें उनके ध्यान में आती है तो वे उसको संभाल लेते है।

डॉ0 बीरेन्द्र पाल अहलावतः सर, मेरे सवाल का जवाब नही आया। मुझे अभी एक सबमि ान और करनी है।

श्री अध्यक्षः आप अभी बैठिए।

श्री बीरेन्द्र सिहः स्पीकर सर, मंत्री महोदय, ने कहा एड्स होने के बाद उसकी कोई दवाई नहीं है जिससे इसका

इलाज किया जा सके और इसलिये प्रिवैटिव मैयर्ज ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर, यह बात इनकी सही है क्योंकि जितनी इस बारे में पब्लिक अवेयरनैस होगी उतना ही एड्स पर कंट्रोल होगा। इन्होंने इस बारे में बहुत बड़े–बड़े होर्डिग लगाए हुए है। मंत्री जी की जो बैकग्राउड है वह नैतिकता की है क्योंकि ये हमारे साथ रहे है। वैसे तो बी0 जे0 पी0 भाई भी नैतिकता से भरे हुए है। (विघ्न) सर, मै मंत्री जी को पता है या उन्होंने वह लैग्वेज पढ़ी है? क्या ये उस लैग्वेज के अलावा उन होर्डिग पर कोई दूसरी भाशा नहीं लिख सकते ताकि वह एड्स बीमारी के प्रचार के लिये इफैक्टिव लगे। इन हेर्डिग की लैग्वेज से ऐसा द र्ाया गया है कि यौन संबंध हो तो कोई बात नहीं लेकिन थोड़े करैक्टिव मैजर्य में हो।

स्थानीय भाासन मंत्री (डा0 कमला वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मै इनको बताना चाहूंगी कि हमने इस विज्ञापन के लिये भी एक कमेटी बनायी थी क्योंकि हमने सोचा था कि यह होर्डिग बदले जाने चाहिए और इनकी लैग्वेज और इनका चित्रण थोड़ा सा परिवर्तित होना चाहिए। सर, यह काम जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि हम भी यह मानते है। यह होर्डिग राश्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सैंटर से ही आते हैं लेकिन सैंटर से इनके आने के बाद मैने आयुक्त स्वास्थ्य निर्दे ान एवं मीडिया से विचार कर निर्णय किया का इनको बदला जाना चाहिए। बीरेन्द्र जी, वि वास रखें यह काम हो जाएगा।

डॉ0 बीरेन्द्र पाल अहलावता: स्पीकर सर, जैसा मंत्री जी ने बताया कि एड्स को रोकने के लिये प्रिवैटिव मैयर्ज ही ज्यादा कारगर है। मै यह जानना चाहूंगा कि इस बारे में हमे जो वर्ल्ड हैल्थ आगेनाइजे ान से या दूसरी जगह से जो ग्रांटस दी जाती है क्या वह प्रिवैटिव मैयर्ज के लिये ही दी जाती है या किसी दूसरी बातों के लिये भी दी जाती है?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, तरीका यही है जो मंत्री जी ने बताया है कि इसका कोई ईलाज तो है नहीं। इसका ईलाज तो प्रिवै ान ही है। होर्डिग के बारे में जो बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि ये बदले जाने चाहिएं तो हम इनको बदलवा देंगे और इनमें सुधार कर देगे। जहां तक प्राईवेट होस्पीटल्ज में बिना टैस्ट के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात है इसमें तो पहले ही सख्ती हो रही है लेकिन हम इस बारे में और भी सख्ती लागू कर देंगे और प्राइवेट डाक्टर्ज के ऊपर और सख्ती बरतेगे।

तारांकित प्र न संख्या 220

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री सतपाल सांगवान, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Cutting of Trees

254. Shri Randeep Singh Surjewala: Will the Minister for Public Health be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the trees standing within the area water works of the villages Dhandhlan and Barhana, District Rohtak, have been cut by the officials of the Public Health Department during the periond form August 1996 to Fcbruary, 1997; if so, the number thereof and

(b) whether the trees, as referred to in part (a) above, were auctioned; if so, the total amount realised therefrom?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ):

(क) जी हां, मास दिसम्बर 1996 में 1996 में अवैध रूप से 110 वृक्ष काटे गये।

(ख) जी नहीं।

श्री रणदीप सिंह सुजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ये जो 110 पेड़ काटे गये यह इन्वायरमैंट प्रौटेक ान ऐक्ट का उल्लघंन नहीं है इसके अलावा कर्माचारियों द्वारा मिसट्रस्ट किया गया अगर ऐसा है तो उन कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने इन्वायमैंट प्रौटैक ान एक्ट व इंडियन पीनल कोड की धाराओं के तहत मुकदमें दर्ज करे हैं या कोई प्र ाासनिक कार्यवाही उनके खिलाफ की गई है यदि नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई है?

श्री जगन नाथः स्पीकर सर, इनमें जितने वृक्ष काटे गये उनके हिसाब से 7–2–97 को इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया जो धारा 302 के तहत दर्ज किया गया।

श्री रणदीप सिंह सुजेवालाः पेड़ काटने के लिये हत्या का मुकदमा अभी दर्ज नहीं किया जाता।

श्री जगन नाथः मैने ऐसा गलती से कह दिया। धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और एस0 आई0 आर0 नं0 44/97 दर्ज कर रखी है और उनके ऐक्सीयन, एस0 डी0 ओ0, जे0 ई0 चौकीदार, पम्प ऑपरेटर्स ये सारे के सारे ससपैंड कर दिये है और पुलिस केस भी उनके खिलाफ रजिस्टर कर दिये है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर सर, मेरी जानकारी के मुताबिक इन्वायनमैंट प्रोटेक ान एक्ट के तहत कोई मुकदमा दर्ज नही करवाया गया। क्या मंत्री महोदय बताएगे कि ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्या उन आफीसर्ज का चार्ज ाीट सर्व की गई है?

श्री जगन नाथः दिनांक 7–2–97 को धारा 409, 109, 201 के तहत एस0 डी0 एम0 द्वारा केस रजिस्टर किया गया है और उसके हिसाब से 3 मार्च को ये सारे के सारे ससपैंड हो चुके है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, मेरा सवाल यह है कि इन्वायरनमैंट प्रोटेक ान एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया गया?

Mr. Speaker: You must seek permission of the Chair first. Please take your seat.

Upgradation of Government Girls Middle School, Mayna

255. Shri Balwant Singh: Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government Girls Middle School, Mayan (Rohtak) to Hingh School?

ि ाक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): वर्तमान में विद्यालय को स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नही है।

श्री बलवंत सिंह: स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मैने विधान सभा में दो इसी प्रकार के क्वे ाचन दिये और दोनों बार उनका यही जबाब मिला। मै जानना चाहूंगा कि क्या यही नार्म हैं। किन नार्म के तहत स्कूलों की अपग्रेडिंग की जाती है?

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, चौधरी बलवत सिंह जी का मायना गांव है। पिछली बार इन्होंने मेरे से कहा था उसके बाद हमने मायना विद्यालय का सर्वेक्षण करवाया। हर स्तर

की प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई और हाई से दस दमा दो विद्यालय का दर्जा बढ़ाने की प्रक्रिया है। मायना विद्यालय में केवल सात कमरे हैं कोई कार्यलय कक्ष नहीं है, कोई विज्ञान कक्ष नहीं है, कोई स्टोर नही है हालांकि मायना विद्यालय के पास दो एकड़ जमीन उपलब्ध है और 310 छात्राएं पढ़ती है। मै माननीय साथी से कहूंगा कि इस विद्यालय में कम से कम चार कमरों का प्रावधान करा दें तो हम इस पर विचार करेंगे।

श्री बलवंत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदे ा के अन्दर जितने भी स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया है क्या वह सभी नामर्स के तहत ही बढ़ाया गया है और जो स्कूल आज नामर्स पूरा करते है उनका दर्जा क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है?

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर सर, माननीय साथी ने यह ठीक सवाल किया है क्योंकि पिछले समय में कुछ ऐसे स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया जो कि नामर्स पूरा नही करते थे। परन्तु हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदे ा के 22 विद्यालयों का दर्जा नामर्स के तहत ही बढ़ाया है पहले अच्छी तरह से सर्वेक्षण कराने के बाद ही दर्जा बढ़ाया गया है।

श्री भागीरामः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो 22 स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया है वह किस–किस जिले में है और कौन–कौन से हल्कों में है।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर सर, जो 22 स्कूलों की हमारी सरकार ने दर्जा बढ़ाया है वह एक तो रोहतक जिले की झज्जर तहसील में पाटौदा है। इन गांव की आबादी दस हजार से ऊपर है और विद्यालय का भवन भी बना हुआ हैं। उसके बाद सिलाणी स्कूल का दर्जा बढ़ाया है और इसी तरह से जो भी दूसरे स्कूल हैं उनका अच्छी तरह से सर्वेक्षण करने बाद ही दर्जा बढ़ाया गया है।

श्री भागी रामः आप उन गांवो के नाम तो बता दें।

श्री रामबिलास भार्माः स्पीकर सर, मै सभी स्कूलों के नाम बता देता हूं रोहतक जिले में झज्जर तहसील में समसपुर माजरा, रैया, सिलाणी, सिलाणी ऊंटलौडा, कोहलपुर, खेतावास और पाटौदा, भिवानी जिले में अजीतपुर, सुडाणा, जैनाबवास, गोलागढ़ सिमली, बरोला, इसरवाल, पिजोखड़ा और भानगढ़ तथा महेन्द्रगढ में पाथेड़ा, बुडीन, कोथल कलां, बसी, महेन्द्रगढ़ और गुजरवास है।

श्री भानी रामः सिरसा में कितने है?

श्री राम बिलास भार्माः फिलहाल तो सिरसा में नही है। अप्रैल के बाद जो भी स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जायेगा उसमें सिरसा को भी भाामिल कर लिया जायेगा।

Industrial Growth Centre, Saha

267. Shri Anil Vij: With the Minister for Industries be pleased to State the time by which the proposed Industrial Growth Centre Saha, District Ambala is likely to be set up?

उद्योग मंत्री (श्री भाि ापाल मैहता): यदि भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाती हे तो इस केन्द्र पर विकास कार्य अप्रैल, 1998 तक आरम्भ हो जायेगा तब तक इस काम का सर्वेक्षण होने की सभांावना है। और इसके अलगे दो वर्शो में पूरा हो जाने की संभावना है।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, लगभग दस वर्श बीत गये है और यह परियोजना ऐसी ही लटकती आ रही है। वहां पर अभी तक केवल बोर्ड ही लगा हुआ है इण्डस्ट्रिल ग्रोथ सैन्टर के नाम पर कुछ भी कार्य नही हुआ है। मै मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह भारत सरकार से अप्रूवल कब तक मिल जायेगी और इस परियोजना के लिये वितीय संस्थाओं में कौन सी सस्थां है जो इस परियोजना का खर्च बहन करेगी।

श्री भाि ापाल मैहता: अध्यक्ष महोदय, 410 एकड़ जमीन को एक्वायर कर लिया है और जब भी भारत सरकार से अप्रूवल मिलेगी काम भुरू कर दिया जायेगा। इस परियोजना की लागत आज लगभग 30 करोड़ है और काम पूरा होने तक यह रा ि। लगभग 80 करोड़ तक पहुंच जायेगी।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार से अप्रूवल प्राप्त होने के

बाद इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैटर में क्या–क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी और कब तक कर दी जाएगी?

श्री भाि ापाल मैहताः अध्यक्ष महोदय, जब काम भुरू होगा उसके बाद पूरी सुविधाएं जो इंडस्ट्रियल टाउन में होती है वह सब उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे सड़के, पानी, बिजली, भौड, प्लाट, हर चीज वहां पर उलब्ध कराई जाएगी।

श्री सत नारायण लाठरः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रोथ सैंटर का जो मामला श्री अनिज विज जी ने उठाया है, यह तो हमारा हिस्सा छीना गया है। यह ग्रोथ सैटर तो पिछली सरकार ने जुलाना में स्थपित करने का निर्णय किया था। वहां से उठाकर के चौधरी भजन लाल की सरकार इसको साहा में ले आई है। मै यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके बदले में जुलाना को कुछ देने का सरकार का इरादा है?

श्री भाि ापाल मैहताः अध्यक्ष महोदय, इसके बदले मे तो ऐसी कोई चीज नही है। मै इनको बताना चाहता हूं कि इससे पिछले सत्र में इसका जबाब दिया गया था क्योंकि जुलाना रमें ज्यादा सुविधाएं नहीं है जैसे मेन रोड़, व रेलवे लाईन के पास स्थित होना इत्यादि। इसके कारण ही सैंटर से स्वीकृति मिलने में कठिनाई है। इसलिए इसको साहा में लाया गया है।

श्री सत नारायण लाठरः अध्यक्ष महोदय, क्या सभी विकास कार्य जी0 टी0 रोड पर ही होगे क्या हमारे यहां पर कुछ नही होगा?

श्री भाि ा पाल मेहताः वहां पर भी जरूर कुछ हो सकता है। वैसे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर कई तरह की सुविधाए नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से आपके हल्के के साथ ऐसा कुछ किया जा रहा है। यह पिछले सरकार ने किया था। हमने इसमें कोई नया प्रावधान नही किया है।

श्री अध्यक्षः अगर पिछली सरकार ने कुछ किया है तो क्या आपकी सरकार इसकी फिर से एग्जामिन कराएगी?

श्री भाि पाल मेहताः अध्यक्ष महोदय, हम इसको जरूर एग्जामिन कराएंगे। लेकिन वहां पर इंडस्ट्रियल हाउन के लिए कोई हिसाब–किताब नहीं बन रहा है। फिर भी वहां पर कोई छोटे–मोटा इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का यत्न करेंगे।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर में कितनी यूनिटस लगाई जाएंगी, कितने प्लाट्स इसके बनाए जाएंगे। क्या ऐसी योजना बनाई गई है?

श्री भाि ापाल मैहताः अध्यक्ष महोदय, अभी टाउन बसा नहीं है और इसकी योजना पहले ही पूछ रहे है। मै बताना चाहता

हूं कि इसके अन्दर प्लाटों की संख्या इस प्रकार होगी– 250 गज के 35 गज के 35, 500 गज के 38, एक हजार गज के 34, 2 हजार गज के 30 और एक एकड़ के 36, दो एकड़ के 3, 3 एकड़ के 5, 4 एकड़ का एक।

श्री सत नारायण लाठरः अध्यक्ष महोदय, जब हमें ही कुछ नहीं मिला रहा है, तो दूसरों को भी क्यों मिले (हंसी)

श्री भाि पाल मैहताः अध्यक्ष महोदय, इनका मतलब तो यह है कि जुलाना मे जब यह सैंटर नहीं लग रहा है तो साहा में भी न लगे (हंसी)

Imposition of Ban on State Letteries

203. Shri Ram Pal Majra: Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any proposal under comsideration of the Government to impose ban on lotteries run by Haryana Government?

वित मंत्री (श्री चरण दास): जी नही।

श्री रामपाल माजराः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार प्रतिदिन कितने ड्रा निकालती थी और आज की सरकार कितने ड्रा प्रतिदिन निकाल रही है?

श्री चरण दासः अध्यक्ष महोदय, प्रतिदिन नौ निकाल रही है। (हंसी)

श्री अध्यक्षः यह नौ कौन सा है? (हंसी)

श्री चरण दासः सर, संख्या नौ (नाइन) है।

श्री रामपाल माजराः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हर रोज 12 ड्रा निकाले जा रहे है।

श्री अध्यक्षः अब प्र न काल खत्म होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारंकित प्र नों के लिखित उतर

Opening of Government College at Badli

280. Shri Dhir Pal Singh: Will the Minister for Education be plased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a College at Badli in Rohtak District?

ि ाक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): जी, नही।

Construction of Roads

252. Shri Nafe Singh Jundle: Will the Minister for P.W.D (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govern ment to construct the following roads in district Karnal:-

(i) Barota to Jundla via Kheri-Naru;

(ii) Kheri-Naru to Jani;

(iii) Dadupur to Kheri-Naru;

(iv) Jundla to Jarifabad;

(v) Bansa to Pakakhera;

(vi) Katlaheri to Augandh

(vii) Katlaheri to Jundla;

(viii) Brass to Bastali;

(ix) Gondar to Badnara; and

(x) Picholia to Jani; and

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be constuted?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव):

(क) नही, श्री मान् जी,

(ख) उपरोक्त (क) की सम्मुख रखते हुये उपरोक्त सड़कों के निर्माण बारे कोई समय अवधि निर्धारित नही की जा सकती।

Posting of Veterinary Doctor

196. Shri Dev Raj Dewan: Will the Minister for Animal Hasbandary be pleased to state-

(a) whether the Govenment is aware of the fact that there is no Veterinary Doctor in Veterinary Dispensary of

Village Chatia Aulia District Sonipat for the last two years; and

(b) if so, the time by which the Veternary Doctor is likety to be posted in the said Dispensary?

प ाुपालन मंत्री (श्री हरमिन्दर सिंह)

(क) तथा (ख) गांव चेतिया ओलिया, जिला सोनीपत में कोई प ाु औशधालय/हस्पताल स्वीकृत नहीं किया गया है, इसलिये प ाु चिकित्सक लगाने का प्र न ही उत्पन्न नही होता।

Kheri Sheru Minor

202. Shri Ram Pal Majra: Will the Chief Minister be pleased to state

(a) whether there is nay proposal under consideration of the Government to construct Kheri Sheru Minor in District Kaithal; and

(b) if so, the time by which the aforsaid Minor is likely to me constructed?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल):

(क) तथा (ख) जी हां, जिला कैथल में खड़ी– ोरू माइनर के निर्माण की परियोजना सरकार ने वर्श 1991 में स्वीकृत की थी। भूमि अर्जन करने का कार्य भी प्रारम्भ किया गया था, परन्तु माइनर की नि ाानेदेही के बारे में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में लम्बित केस के कारण कार्य पूर्ण नही हो सका।

पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त आगमी कार्यवाही की जाएगी। इस अवस्था में इसके निर्माण की कोई निि चत तिथी नही दी जा सकती।

Construction of Fly-over Bridge in Rewari

205. Capt. Ajay Singh Yadav: Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a fly-over in Rewari City;and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मबीर यादव):

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) पुल के स्थान नियत करने तथा इसके वित संसाधन व्यवस्था बारे मामला विचारधीन है तथा रेलवे के साथ इस विशय में विचार विनियम जारी है। अतः इस पुल के निर्माण के लिए कोई समयावधि नियत नही की जा सकती।

Augmentation of Water Supply Schemes

211.Shri Sat Narain Lather: Will the Minister for Public Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to augment the water supply

schemes of Nidani, Khema Kheri and Shamlo Khurd, Rajgarh, Desh Khera. Buwana and Devrod villages of District Jind; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगननाथ):

(क) गांव निडानी, खेमा खेड़ी तथा भाामलु खुर्द की जल वितरण योजना मेें बढौतरी करने का प्रस्ताव है।

(ख) गांव निडानी, खेमा खेड़ी तथा भाामलु खुर्द की जल वितरण योजना में बढ़ौतरी, 31—12—1997 तक सम्पन्न कर दी जायेगी।

Auto-Market, Bahadurgarh

246. Shri Nafe Sinhgh Rathee: Will the Minister for Town & Country Planning be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Auto Market Bahadurgarh; if so, the time by which the aforesaid Autol Market is likely to be constructed?

भाहरी तथा नगर योजना मंत्री (सेठ सिरी कि ान दास): बहादुरगढ़ में आटो मार्किट बनाने के लिए प्रस्ताव है, जिसके स्थल के चयन के बारे निर्णय लिया जा रहा है। अतः इस अवस्था में इसके निर्माण के लिए नि चत समय अवधि नही द ार्ाई जा सकती।

Number of School upgraded in the State

225. Shri Krishan Lal: Will the Minister for Eduction be pleased to state the districtwise number of schools, if any, upgraded from primeary to Middle, Middle to High and High to Senior Secondary is the state during the year 1995-96 and 1996-97?

ि ाक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): सूचना सदन पटल पर रखी जाती है ।

सूचन

क्रम	जिले का नाम	प्राईमरी से मिडल	मिडल से हाई	हाई से सीनियर सैकेण्डरी
1.	अम्बाला/पंचकूला	16	28	15
2.	भिवानी	8	16	12
3.	फरीदाबाद	8	6	10
4.	गुड़गांवा	8	9	11
5.	हिसार	27	29	22
6.	जीन्द	7	12	10
7.	करनाल	9	6	10

8.	कैथल	7	6	7
9.	कुरूक्षेत्र	6	3	3
10.	पानीपत	5	4	4
11.	नारनौल	6	3	5
12.	रिवाड़ी	3	4	6
13.	रोहतक	11	9	10
14.	सोनीपत	13	10	12
15.	सिरसा	10	7	5
16.	यमुनानगर	6	7	7
कुल जोड़		150	159	149

वर्श 1996–97 में स्तरोन्नत होने वाले विद्यालयों की जिलावार सूची/संख्या

1.	भिवानी	8	6	–
2.	रोहतक	3	2	2
3.	महेन्द्रगढ़	–	3	3
कुल जोड़		6	11	5

Openting of Blood Bank in Private Sector

216. Shri Virender Pal Ahlawat: Will the Minister for be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for opening of Blood Banks in private sector in the State?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा महाजन): जी हॉ।

स्थगन प्रस्तावों/ध्यानकर्शण प्रस्तावों आदि की सूचनाएं

श्री ओम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हमारी एक एडजर्नमैंट मो ान है जो हमने आपको दी हुई है। वह एक बड़ा अहम मसला है। कल पंजाब विधान सभा में पंजाब के गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाशण में चण्डीगढ़ के मामले को उठाया। चण्डीगढ़ का मामला हरियाणा प्रदे ा के हितों के साथ जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आपका दिया हुआ एजर्नमैट मो ान अभी अभी 9.20 बजे मेरे पास आया है।

That is under consideration. Please take your seat.

श्री ओम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा अहम मुद्दा कोई दूसरा नहीं हो सकता। चण्डीगढ़ का मामला हरियाणा प्रदे ा के हितों के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए उस एडजर्नमैट मो ान पर हाऊस का दूसरा बिजनैस छोड़ कर डिस्क ान की जानी चाहिए।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रका ा ने जो बात कही है उनकी यह बात बिल्कुल ठीक है। हम इनकी इस बात से असहमत नही है। इस मुददे पर आज सरकार विचार करेंगी और अगले सोमबार को सारी अपोजि ान पार्टीज के लीडर्ज को बुला कर इस पर विचार करेंगे और सब की सहमति से हरियाणा प्रदे ा के हित में जो बात होगी वही करेंगे।

श्री ओम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, क्या लीडर ऑफ दि हाउस इस बात का आ वासन देगे कि इस बारे में एक मुस्तरका प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार को भेज दिया जाएगा।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, आज तो इस बारे मे विचार नही किया जा सकता लेकिन सोमवार को इस बारे में सभी पार्टीज के माननीय नेताओं को बुला कर इस बारे में बात में बात करेंगे और हरियाणा प्रदे ा के हित के बारे मे जिस बात पर सभी की सहमति होगी वही बात करेंगे। हरियाणा प्रदे ा के हितों के साथ अन्याय नहीं होने देगे।

श्री ओम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही अहम मुद्दा है इसलिए हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर हरियाणा प्रदे ा के हितों को ध्यान में रख कर सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए। क्या चौधरी बंसी लाल जी मेरी बात से सहमत होगे क्योंकि यह मामला पहले भी हाउस में आ

चुका है। इस प्रकार के मुद्दे चाहे वह कावेरी जल विवाद का हो चाहे नर्मदा का हो और चाहे बंगलौर–तामिलनाडु का मामला हो जब वे दूसरी सरकारों दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर और अपने अपने राज्य के हित को ध्यान में रखकर निर्णय ले सकती है तो क्या हरियाणा प्रदे ा की सरकार कोई निर्णय नही ले सकती। हरियाणा प्रदे ा का प्रतिनिधित्व करने वाले 90 लोग यहां हाउस में बैठे हुए है हम सभी इस बारे में एक मुस्तरका निर्णय ले और इस बारे में एक प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार को भेजें। क्या इस बात से मुख्य मंत्री जी सहमत होंगे?

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मै इनकी बातों का फोरी तौर पर जवाब दें दूगा।

श्री ओम प्रका ा चौटालाः केवल जवाब देने से ही काम नही चलता।

श्री अध्यक्षः लीडर ऑफ दी हाउस ने अ यौर कर दिया है and that must be taken seriously.

श्री अनिल विजः स्पीकर साहब, हिमाचल प्रदे ा सरकार ने निर्णय लिया है कि वह हिमाचल प्रदे ा विधान सभा की कार्यवाही दूरद र्न पर टैलीकास्ट किया करेगी। यह बात समाचार–पत्रों में आई है। मै यह जानना चाहूंगा कि क्या हमारी सरकार भी अपनी विधान सभा की कार्यवाही दूरद र्न पर टैलीकास्ट करने के बारे में कोई विचार करेगी।

श्री बंसी लालः यह मामला तो स्पीकर साहब से संबंधित है।

श्री भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर चौधरी ओम प्रका ा चौटाला के मामला उठाया है। जो मामला इन्होंने उठाया है वह बहुत ही अहम मामला है। आपने भी पढ़ा होगा कि पंजाब के गवर्नर महोदय ने अपने ऐड्रेस में यह कहा है कि चण्डीगढ़ फौरन पंजाब को दिया जाए और हरियाणा प्रदे ा में जो पंजाबी भाशी गांव है वे भी फौरन पंजाब प्रदे ा को ट्रांस्फर किए जाएं। यह कोई छोटा मसला नही है यह एक बहुत बड़ा अहम मसला है। उन्होंने पानी के बारे में भी कह दिया कि पानी में हरियाणा प्रदे ा का कोई हक नहीं है। इसलिए यह एक बड़ा अहम मसला है आप इस बारे में एक प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार को भेजें। पहले स्पीकर साहब, आप भी, चौधरी बंसीहह लाल जी और राम बिलास भार्मा जी यह कहते रहे कि इस बारे में हमें एक प्रस्ताव पास करना चाहिए। हमने इसलिए ऐसा प्रस्ताव पास करके नही भेजा कि यदि हम करते तो वे भी करते। (ाोर)

ि ाक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन में चौधरी भजन लाल, चौटाला साहब और संयोग से आप भी उसमें विराजमान थे। उस वक्त श्री भजन लाल जी मुख्य मंत्री थे। उस समय हरियाणा और पंजाब से जुड़े मुद्दो पर चौधरी बंसी लाल जी ने बी0 जे0 पी0 ने और विपक्ष के दूसरे साथियों ने हर सत्र में आग्रह किया कि हम सब को राजनीति से

ऊपर उठकर हरियाणा के हित के दूसरे, के लिए, चाहे वह राजधानी का मामला हो, चाहे वह टैरीटेरी का मामला है या पानी का मामला हो प्रस्ताव पास करना चाहिए। हम सबने कहा कि हम इस विशय पर सब भजन लाल जी के साथ है और हम आपके साथ प्रधानमंत्री के पास चलते है लेकिन इन्होंने कोई बात नही सुनी। अब इस इ ू पर हमारे माननीय नेता श्री बंसी लाल जी ने श्री ओम प्रका ा जी चौटाला के जवाब में और दूसरे साथियों के जवाब में कहा है कि 10–3–97 को हमे सभी से बातचीत करेंगे और एक सर्वम्मति से निर्णय लेकर कोई अन्तिम निर्णय लेने के बाद जो ठीक होगा, वह करेगे। आज ये कह रहे है कि हम सर्वसम्मति से कोई प्रस्ताव पास करके भारत सरकार का भेजना चाहिये। हमारे नेता ने तो वि वास दियाला है कि हम सभी इस पर मिलकर विचार करेंगे लेकिन ये तो बात सुनने के लिए तैयार नही होते थे। (विघ्न) हमने उस बार एक बार नही 3–3 बार कहा कि एक प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजना चाहिए लेकिन इन्होंने हमारी बात सुनी नही।

श्री भजन लालः आप मेरी बात सुनिये। उस वक्त पंजाब विधान सभा में ऐसी कोई बात नही आई थी, जो कल वहां पर गवर्नर महोदय के अभिभाशण में आई थी। इसलिये अब यह इ ू और महत्वपूर्ण हो गया है।

श्री राम बिलास भार्मा: अब आप कहे हैं कि उस वक्त ऐसी बात नही आई थी। हमने हर बार कहा कि कोई प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भोजना चाहिये। (ाोर)

श्री भजन लाल: मै यह कह रहा हूं कि जो बात अब वहां पर पंजाब विधान सभा में आई वह उस वक्त नही आई थी। (ाोर) अब वहां पर अकाली और बी0 जे0 पी0 का गठजोड़ है इसलिए प्रस्ताव पास नहीं करना चाहते।

श्री राम बिलास भार्मा: अकाली और बी0 जे0 पी0 का डंके की चोट का गठजोड़ है उन्होंने यानि वहां की बी0 जे0 पी0 ने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है।

श्री अध्यक्ष: मै पहले सदन को बताना चाहता हूं कि किन–किन लोगों के काल अटैं ान मो ान और एडजर्नमैंट मो ान आए है, और उस पर क्या निर्णय लिया गया है। (विघ्न) पहले मैं अपनी बात कर लूं उसके बाद फिर अपनी बात कहें।

Mr. Speaker: Please take you seat. Let me tell the fate of the motion I have received a Motion under Rule 66 from Shri Om Parkash Chautala and 15 other M.L.As regarding spreading up of Pilia disease in the District of Sirsa in Haryana. That has been converted into calling attention motion and has been admitted for 10th March, 1997. The second adjournment motion is from Sh. O.P.Chautala regarding privatistion of Haryana State Electricity Board. That is under consideration. The next calling attention motion is

from Capt. Ajay Singh and Rao Narender Singh M.L.As regarding six feet high wall on the out-let of the Massani Barrage which has been sent to the Government of comments. The next calling attention motion is also from Capt. Ajay Singh and Roa Narender Singh M.L.As regarding abolition of slab system onthe rate of power tariffs on the tubewells in the districts of Rewari and Mahindergarh which has been disallowed. The next calling attention mottion is also from Capt. Ajay Singh and Rao Narender Singh, M.L.As regarding sewerage water entered inthe villages of Naya Gaon, Dolatpur and Dabri etc. in district Rewari. It has been sent to Goverment for comments. The next calling attention motion is also from Capt. Ajay Singh and Rao Narender Singh, M.L.As regarding flow of chaemical poisonous water from Industrial Estate, Bhiwani, It has also been sent to Government for comments.

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, ट्यूबवैल्ज पर पावर टैरिफ का यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है लेकिन आपने इसको डिसअलाऊ करने का आपने कोई भी कारण नही बताया है। मेरी गुजारि ा है कि आप आप आपने फैसले पर पुनः गौर फरमाएं। (विघ्न एवं ाोर)

Mr. Speaker: Capt. Ajay Singh, you pleased take your seat. (Interruptions) Capt Sahib, that has been disallowed. You pleased take your seat. If you will speak like this, you would not be permitted (Interruption)

श्री भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जो यह मुद्दा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है (विघ्न एवं ाोर)

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, आप बैठिये। (विघ्न एवं ाोर)

Hon'ble members next is a notice of calling attention motion from Shri Dhir Pal Singh, M.L.A regarding non supply of electricity and bogus bills in Badli constituency. It is under consideration. Dhir Pal Singh Ji your second notice of calling attention motion is regarding transfer of powers of R.T.As to executive Magistrates which is also under consideration.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में मेरा भी एक कॉलिंग अटै ान मो ान था, उसका आपने कोई जिक्र नही किया है, कृपया यह बताइये कि उसका क्या फेट हुआ?

श्री अध्यक्षः वह आज ही आया है और अण्डर कंसिड्रे ान है।

श्री ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, सिरसा में फैली बीमारी के बारे में मैने एडजर्नमैंट मो ान दिया है जिसे कि आपने कालिंग अटैं ान मो ान में कन्वर्ट कर दिया है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की कृपा करें। यह मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है कयोंकि यह मामला इन्सानी जानों के साथ जुड़ा हुआ है। अभी तक इस बीमारी के कारण 19 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। यह भी आ ांका है कि यह बिमारी वहां पर भयंकर रूप ले ले और मेवात

जैसी स्थिति वहां पर भी उत्पन्न हो जाए। हमें यह अंदे ाा है कि मगर यह बीमारी अधिक फैल गई तो सरकार इसे काबू करने में विुल हो जाएगी। यह इंसानी जानी से जुड़ा हुआ मसला है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे एडजर्नमैंट मो ान के रूप मे ही लिया जाए। हम यह जानना चाहते है कि क्या सरकार के पास इस बारे में रिपोर्ट है कि यह बीमारी किस–किस गांव में फैली हुई है। इसलिए मै आपसे फिर पुरजोर अपील करूंगा कि इस मामले को कॉलिंग अटै ान मो ान की बजाए एडजर्नमैंट मो ान के रूप में लिया जाना चाहिए। कि इस मामले को कॉलिंग मो ान की बजाए एडजर्नमैंट मो ान के रूप मे लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, आपकी इस एडजर्नमैंट मो ान के बारे में मैने आपको बता दिया है कि इसे कॉलिग अटैं ान मो ान में कन्वर्ट कर दिया गया है।

Chautala Sahab, I would like to draw your attention to pege 451 of the book practice and procedure of Parliment by Kaul and Shakdher, which says it has been debate an adjourment of thanks on the President,s/Governor,s Adderss, butget discussion, motion on international situation, motion regarding a motter of public imporatce such as food policy, etc. to be held in the same session is not is order Similarly a matter which can be raised under any other procoedueat device vizcalling attention, short durationliscussion etc. cannot be taised through an adjournent motion.

श्री ओम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मै आपकी बात से सहमत हूं लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस में रल्ज और कानून का दखल नहीं होनी चाहिए क्यों का मसूला इन्सानी जानों से जुड़ा हुआ मसला है। आपका जो भी निर्णय होगा वह तो मान्य होगा हो। आपके निर्णय को न मानने का परिणाम तो मै पहले भुगत चुका हूं और आईन्दा इस प्रकार के परिणाम भुगतना नही चाहूंगा (हंसी) इसलिए आपसे निवेदन है किडस पर दोबारा से गौर फरमाए।

Chif Minister (Shri Bani Lal): Speaker, Sir the Government is fully aware of the situation and whatever stips should be taken, they are being taken by the Government and a detailed reply will be given on the motion which has been admitted by you. The Health Minister was telling me in the morning that he would be going in the area today aftemoon alogwith the team of doctors. Now I am told that a team of doctors has already been sent to the area and medicines will also be imported Orders for medicines have already been placed as the medicines were not available.

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी आप बोलना चाहते है तो बोले।

श्री ओम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम फुली अवेयर हैं। अगर यह सरकार फुली अवेयर है तो इस बारे में डिस्क ान करने में क्या हर्ज है।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, ओम प्रका ा चौटाला तो यह चाहते हैं कि रूल्ज को स्क्रैब कर दो और जिस तरह से ये कहें उसी तरह से हाउस को चलाएं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप सब बैठ जाएं।

श्री ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से भागीराम जी इस बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि यह उनके क्षेत्र से रिलेटिड मामला है।

Mr. Speaker: Chautala Ji, the adjournment motion has been converted into ralling attention motion. You will get ample oppoutunity to speak. Now the matter ends. (विघ्न) पहले भजन लाल जी को बोलने दिया जाए।

श्री भजन लालः अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ रिवाड़ी और नारनौल में ट्यूब्वैल्ज के बिजली के फ्लैवरेट एक जैसे कर दिए है। इस प्रकार ने इसके रेट दूसरे एरिए के साथ बराबर कर दिए है। जबकि वहां पर पानी बहुत नीचे है। दूसरे एरियाज में पानी दो–अढाई इंच का पाईप चलता है इन तीन एरियों में 80–90 फुट नीचे है। दूसरे एरियार्ज में एक एकड़ भूमि एक घंटे में गीली हो जाती है और इन तीन एरियाज में चार–पांच घंटे में भी जमीन एक एकड़ गीली नही होती है। इस बात को लेकर कैप्टन अजय सिंह और रणदीप सिंह ने अटे ान मो ान दिया था जोकि आपने रद्द कर दिया है। आप इस बारे में दोबारा से विचार कर लें।

श्री अध्यक्षः यह आलरेडी डिसअलाउ हो चुका है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में जी भी बात कही जानी हो या कही जाए वह आपकी इजाजत से और आपको एड्रैस करके कही जानी चाहिए। लेकिन रूलिंग पाटी के मैम्बर पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर और सांगवान जी आपकी इजाजत लिए बिना, खड़े होकर आपको एड्रैस किए बिना ही बोलने लग जाते है। अध्यक्ष महोदय, मै यह मान सकता हूं कि सांगवान जी नए आए हैं इनको इस बात का ज्ञान नही है लेकिन जो पुराने हे उनको तो इस बात का पता है (ाोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, क्या ये आपकी इजाजत के बिना सीधे बात कर सकते है। अध्यक्ष महोदय, कल भी आपने गौर से देखा होगा जब मै राज्यपाल अभिाशण का प्रोटैस्ट करते हुए बोल रहा था तो सांगवान जी राज्यपाल जी को खड़े होकर सलाह दे रहे थे। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सांगवान जी आप बैठ जाएं। कैप्टन साहब आप बैठ जाएं। (ाोर एवं व्यवधान) आप सब बैठ जाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरी एडजर्नमैंट मो ान थी मै उस बारे में बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः मैने उस बारे में बता दिया है आपने सुना नहीं है आप अपने कान खुले रखें।

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रका ा चौटाला जी ने बोलते हुए मेरा नाम लिया कि पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर बीच में बोलने के लिए खड़े हो जाते है। अध्यक्ष महोदय, सदन में अभी सदस्यो का फर्ज है कि वह सदन में नियमों की पालना करें। अध्यक्ष महोदय, कल से आपकी अध्यक्षता में यह सदन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आप जब भी कोई रूलिंग देते है तो ओम प्रका ा जी उसको न मानते हुए अपनी बात कहनी भाुरू कर देते है यह देखकर हमें बहुत दुःख होता है। अध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी मुख्यमंत्री भी रहे है और इन्होंने कोई नोटिस नही दिया है फिर भी बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि ये आदरणीय सदस्य है इसलिए इनको सदन की गरिमा को मानना चाहिए और जो नियमों में लिखा हुआ है उसके अनुसार ही इनको अपनी बात कहनी चाहिए।

श्री ओम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मै तो आपकी बात मान रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह तो गनीमत है कि पार्लियमैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर इस बात को अगर मानें कि सदन की गरिमा को बनाकर रखा जाए। हम तो इस बात के पक्षधर ही है। मैने तो यही कहा था कि अगर कोई भी सदस्य आपकी अनुमति से बोल रहा है तो उस समय दूसरे किसी सदस्य को

इंटरवीन नही करना चाहिए और अगर वह इंटरवीन करें तो उसे आपकी इजाजत लेनी चाहिए। पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर एवं सांगवान साहब को यह अधिकार नहीं कि वे बीच में ऐसे ही बोलने लगें। ये हमें अपने अधिकार की उल्लंधना करते हुए धमकाने की कोि ा ा करते है। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवानः अध्यक्ष महोदय, आप इनसे पूछिए कि इनको कौन धमका सकता है इन्होंने तो सारी उम्र और लोगों को धमकाया ही है। (विघ्न)

श्री ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप इनको एक बात दें कि लंका में सभी 52 गज के है। इस सदन में सभी सम्मनित सदस्य है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अब आप सभी बैठिए और श्री भागीराम जी को बोलने दें।

डॉ0 वीरेन्द्र पाल अहलावतः सर, मेरी एक सबमि ान है कि किसी भी सदस्य को बोलने से पहले आपको ऐड्रस करना ही जरूरी नहीं बल्कि आपसे परमि ान लेना भी जरूरी है।

श्री अध्यक्षः यह बात आप पर भी लागू होती है।

श्री सतपाल सांगवानः अध्यक्ष महोदय, क्या अब इन्होंने आपसे परमि ान ली है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप सभी बैठे और भागी राम जी को बोलने दें।

श्री भागीरामः अध्यक्ष महोदय, काम की एक बात नहीं हो रही है। मै आपके द्वारा सदन की बताना चाहता हूं कि जोहतड़, सुल्तानपुरिया, ऐलनाबाद, रानिया, गीदड़वाली, बेहरवाला, तरीवाला इत्यादि गांवों में जो कि सिरसा जिले में पड़ते है, के गांवो के आदमी पीलिया की बीमारी की वजह से मर रहे है और सैकड़ों आदमी अभी भी अस्पतालों में पड़े हुए है। मंत्री जी तो सरकारी अस्पतालों का रिकार्ड वहां रहे है जबकि प्राईवेट अस्पतालों में जो बीमार लोग दाखिला है उनका इनको पता ही नहीं है। आज वहां पर इस बिमारी के कारण बहुत बुरा हाल है। अध्यक्ष महोदय, वहां के एक गांव मं जब इनका एक वजीर जाता है तो उसने गांव में जाकर लोगों से इस बीमारी की बात पूछने के बजाए यह पूछा कि दारू बंद हुई है या नहीं। गांव वाले मंत्री से बोले कि हम तो मर रहे है और आपको दारू की लगी हुई है। आज वहां पर लोग अपना–अपना काम छोड़ने का मजबूर है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले को आप यहां पर जल्दी ही डिसक ान करवाएं। इसमें किसी को क्या आफत आ रही है।

श्री अध्यक्षः माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि कुछ भावनाएं अभी यहां पर इस बारे में वक्त की गयी हैं और चूंकि यह बहुत ही सीरियस मैंटर हैं इसलिए इस मामले पर

डिसक ान के लिए दस तारीख निि चत की गयी हैं अतः आप उस दिन पूरी जानकारी इस मामले में सदन को दें।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा महाजन): ठीक है जी।

गैर सरकारी प्रस्ताव आगर कैनाल का प्र ासनिक नियंत्रण अपने अधिकार में लेने तथा हरियाणा राज्य का पानी का हिस्सा बढ़ाने संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a non-official resolution regarding taking overn the administrative control of the Agra Canal passing through the Haryana Territory and also to increase the share of water of Haryana State Now. Shri Jagdish Nayar may move this resolution.

श्री जगदी ा नैयरः अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि–

यह सदन राज्य सरकार से सिफारि ा करता कि वह हरियाणा क्षेत्र से गुजरने वाली आगरा नहर का प्र ाासनिक नियंत्रण अपने अधिकार में लेने तथा हरियाणा राज्य का पानी का हिस्सा बढ़ाने संबंधी मामला उतर प्रदे ा सरकार के साथ उठाएं।

Mr. Speaker: Motion moved-

This House recommends to the State Government to take up with the Uttar Pradesh Government the matter regarding taking over the administrative control of the Agra

Canal passing through the Haryana Teritory and also to increase the share of water to Haryana State.

11.00 बजे

श्री जगदी ा नैयर (हसनपुर अनुसूचित जाति): स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से आगरा कैनाल के बारे में जानना भी चाहता हूं और अपनी बात भी कहना चाहता हूं। यह हरियाणा प्रदे ा के किसानों के दु:ख दर्द का मसला है। आगरा कैनाल का सवाल तब का है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से यह मसला उठ रहा है। लेकिन आज तक किसी सरकार ने इस पर कब्जा नही किया। मैं ह्रदय से मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने अपने सात महीने के कार्यकाल में हमारे सात रजवाहों को उतर प्रदे ा सरकार से अपने कब्जे में ले लिया है जिसका फायदा हमारे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के किसानों को होगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो किसान है आज सी0 एम0 साहब के लिए आंखें बिछाये बैठे है जो काम पिछले 20 सालों में नही हुआ था वह काम इस इस सरकार ने सात महीनें में कर दिखाया हैं। अगर कोई विपक्षी भाई इसे गलत कहते हैं या समझते है तो वे मेरे सरकार ने सात महीने में कर दिखाया है। अगर कोई विपक्षी भाई इसे गलत कहते है या समझते है तो वे मेरे साथ चलें मे उनको वहां जाकर दिखा सकता हूं कि वहां पानी टेल–टू–टेल पहुंचा हुआ है। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) कि

हमारी सरकार ने सात रजवाहो को तो अपने कब्जे में ले लिया है लेकिन कुछ रजवाहे और भी जिनको कब्जे में लिया जाना जरूरी है जिससे हमारे हरियाणा प्रदे ा के मेवात क्षेत्र के लोगों का हित जुड़ा हुआ है। अभी मेरे हसनपुर क्षेत्र के रजवाहे भी रह गए है वे रजवाहे भी इसमें जुडवाने का कश्ट करें। यह किसानों के दु:ख दर्द का अहम मसला है। पिछले 20 सालों से प्रदे ा के लोगों का बहकाया जा रहा था। आज जब किसानों को कुछ सुख की सांस मिली है तो उन्हें थोड़ा अहसास हो रहा है कि सरकार हमारे साथ है। मै आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आगरा कैनाल की सफाई के लिए क्वै चन उठाया जाता था लेकिन आज तक उस नहर की कभी पूर्ण रूप से सफाई के लिए क्वैच न उठाया जाता था लेकिन आज तक उस नहर की कभी पूर्ण रूप से सफाई नही करवाई गई। हम देखते है कि उसमें खुण्डियां, गन्दा पानी और घास उग गई है और उनकी बहुत बुरी हालत है उनकी सफाई की बहुत आव यकता है। मै आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध कंरूगा कि इस बारे में इस सदन में प्रस्ताव पारित कर इनकी सफाई के लिए कुछ पैसा नि चत किया जाए जिससे किसानों को पूरा पानी मिल सके। इसके अलावा हरियाणा के किसानों को जो आगरा कैनाल के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते है उनको हरियाणा के आबियाना से तीन गुना ज्यादा आबियाना उतर प्रदे ा सरकार को देना पड़ता हैं। यह पैसा उतर प्रदे ा के खजाने की बजाया हरियाणा के खजाने में आए। अब किसानों को अपनी ि ाकायत लेकर उतर प्रदे ा सरकार के

अफसरों के पास आगरा जाना पड़ता है मै चाहता हूं कि वे अफसर फ्लवल या फरीदाबाद में बैंठे और रिकार्ड वहां रखा जाए ताकि किसानों को आने–जाने में दिक्कत न हो। मै एक बात की ओर वि ोश ध्यान दिलाना चाहूंगा कि रजवाहों पर जो पुल बने हुए है वह उतर प्रदे ा सरकार ने बनाए हुए है आज तक किसी सरकार ने यह नही सोचा कि यह काफी पुराने हो चुके है और कभी टूटेंगी भी। मेरे क्षेत्र हसन पुर में एक घसेड़ा गांव है वहां पर रजवाहे पर जो पुल है उस पुल से ट्रैक्टर गुजर रहा था वह उसके अंदर चला गया और उस पर सवार तीन लोगों में से एक की मृत्यु हो गई। तो मै मुख्या मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार रजवाहों के निर्माण का काम अपने हाथ में लिया है इसी प्रकार पुल निर्माण का कार्य भी अपने हाथ में लिया जाए। मै रजवाहे पक्के करवाने के लिए भी अनुरोध करूंगा। इनसे किसानों का हित जुड़ा हुआ है हम किसान पर आधारित है किसान के पीछे चलने वाले है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हसनपुर, हथीन होडल के रजवाहों की खुदाई के लिए सदन में प्रस्ताव पारित जाए। पिछली सरकार ने तो इस क्षेत्र का भठ्ठा ही बैठा दिया। आज वहां के लोग किसी भी एम0 एल0 ए0 पर वि वास नहीं करते। आज मै आपके माध्यम से एक अहम मुद्दा सदन में उठा रहा हूं। आज हसनपुर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मै आपसे अनुरोध करूंगा कि भिवानी, हिसार रोहतक जिलों की तरह फरीदाबाद जिले के लिए भी सदन में एक प्रस्ताव पास किया जाये क्योंकि फरीदाबाद जिला कभी भी सरकार बनाने में पिछे नही रहा

है। एक और अह्म मुद्दा मै आपके माध्यम से इस सदन में लाना चाहता हूं और वह है आगरा नहर का नियंत्रण हरियाणा प्रदे ा के हाथ में लेना। आज आगरा नहर के कुछ रजावाहों को हरियाणा सरकार ने अपने हाथ में लिया है। मै इस सदन में आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आगरा नहर के सभी रजवाहों को हरियाणा प्रदे ा के कंट्रोल में लाने के लिए एक प्रस्ताव सदन में पे ा किया जाये। क्योंकि सरकार को तो किसान प्रति सहानुभूति है किसान के लिए तो हरेक सरकार एक जैसी है आज किसान के अंदर एक दुख दर्द बसा हुआ है। अगर किसान के साथ अन्याय किया गया तो वे सरकार के प्रतिनिधियों को गांव में घुसने नहीं देगे। मै मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आज तो उन्होंने चालिस हजार रूपये नहरों की सफाई के लिए दिए थे उनसे आज फरीदाबाद की सभी नहरों में सफाई का काम चल रहा है। स्पीकर सर, एस0 वाई0 एल0 का एक अहम मसला है यह मसला तब से चल रहा है जब मेरा जन्म भी नही हुआ था। स्पीकर सर, मै आपके माध्यम सें मंत्री जी और इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि एस0 वाई0 एल0 के पानी के हिस्से में हमारे क्षेत्र फरीदाबाद का कहीं भी हिस्सा नहीं है मेरी आपसे प्रार्थना है कि फरीबाद को भी एस0 वाई0 एल0 के पानी के हिस्से में भाामिल किया जाये।

श्री अध्यक्षः बैठिए। हर्श कुमार जी आप बेलिए।

श्री हर्श कुमार (हथीन): अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से इस सदन में अभी जो आगरा नहर का नियंत्रण उतर

प्रदे ा से हरियाणा में लेने का प्र ान चल रहा है उसके बारे में कहना चाहता हूं। उसका एक अहम कारण यह है कि 1961 से जब हमारा हरियाणा प्रदे ा पंजाब प्रदे ा के साथ था और पंजाब विधान सभा का हाउस था तब से आगरा कैनाल का मसला उतर प्रदे ा सरकार से हम अपने हाथ में लेने के लिए उठाते आ रहे हैं परन्तु उतर प्रदे ा सरकार कभी कोई बहाना बनाकर कभी कोई बहाना बनाकर इसको टालती आ रही थी। अब हमारी यह सरकार बनी है और चौधरी बंसी लाल की सरकार बनने के बाद सुभ घड़ी आई। हमारे नेता ने चुनावों में ही इस बात का वायदा किया था कि आगर नहर का नियन्त्रण हम अपने हाथों में लेगें वह अब पूरा करने की दि ाा में यह एक कदम है। आगरा नहर से 147000 एकड़ जमीन हमारे फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों की है जोकि इस आगरा नहर से सिंचित होती है और जिसमें 782 क्यूसिक पानी हमारे हिस्से को मिलता है और इन 11 दृचैनल्ज की लम्बाई 380 किलोमीटर बनती है। लेकिन पिछले 30 सालों से इस चैनल की खुदाई नहीं हुई है इस वजह से जो हमारा 782 क्यूसिक पानी का हिस्सा था वह मुि कल से 300 क्यूसिक ही मिल पर रहा था और टेल तक पूरा पानी नहीं पहुंच पर रहा था। आज हमारी सरकार ने चालिस लाख रूपये मन्जूर करके आगरा कैनाल के कुछ चैनल्ज की मरम्मत अपने हाथ में ली है। उनसे फरीदाबाद व गुड़गांव जो मेवात का इलाका है, वहां पर पानी खारा है, ये चैनल्ज इन एरिया को कवर करते है। इस प्रकार से इस सरकार द्वारा आगरा कैनाल के चैनल्ज की मरम्त अपने हाथ में लेने से

मेवात के गांवों में आगरा कैनाल चैनल्ज की जो टेलज वहा आज पानी पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, मै अपने क्षेत्र की तरफ से तथा उन किसानों की तरफ से जो इस आगरा कैनाल से सिंचाई करते है, उनकी तरफ से इस सदन में आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जा वायदे चुनावों से पहले किए थे, उनको बड़ी नेकनीयती से पूरा किया है तथा जो किसानों की दुर्द ाा थी उसमें सुधार हुआ है। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि आज तक हमारे क्षेत्र की सिचाई के लिए किसी भी मुख्य मंत्री ने ध्यान नही दिया था। मै इस साहसिक कदम के लिए एक बार फिर आभार प्रकट करता हूं चाहे इस कार्य को करने में किसी पालिसी को बदलना पड़ा हो या किसी दखलंदाजी की वजह से हुआ हो। मै बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके में दो ड्रैन्ज अजीना और गोची से गुजरती है तथा हमारे इलाकों का वाटर लेबल 50–60 फुट नीचे तक पहुंच गया था। मुख्य मंत्री जी के आने से बाढ का पानी निकाले जाने के बाद वहां पर जो बंध लगाए गए, उससे हमारे यहां 30 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हुई जो कभी न नहर से होती थी और न ही टयूबवैल्ज से क्योंकि उस इलाके में खारा पानी है। इस स्कीम से वहां का वाटर लेवल 20–25 फुट तक लोकप्रिय सरकार नहीं है, फिर भी उन अधिकारियों ने जिन्होंने इस कार्य को करने में हमारा सहयोग किया और वह साहसिक कदम उठाकर के आगरा कैनाल के चैनल्ज की मरम्मत हमारी सरकार को सौपी उनका भी मै धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

श्री सतपाल सांगवान (दादरी): अध्यक्ष महोदय, आगरा कैनाल के संबंध में मुख्य समस्या वहां के किसानों की है। मथुरा और आगरा में उनके एक्सीयन और एस0 ई0 बैठते है और वहां पर किसानों की सबसे ज्यादा समस्या यह होती है कि जो भी रैवन्यू का केस होता है उसके लिए यू0 पी0 में जाना पड़ता है। मै तो यह चाहता हूं कि आगरा पास होना चाहिए। इसमें ओखला से जो 4 कि0 मी0 का एरिया है, जहां से अलग–अलग डिस्ट्रिब्यू ान होती है, वहां का प्रबंध यू0 पी0 के पास है। जैसे कि भाई हर्श कुमार जी ने कहा इसके एरिया में वहां पर 11 चैनल्ज है और उनमें से 9 चैनल्ज की सफाई बहुत बढ़िया हुई है। पहली बार हरियाणा में इतनी बढ़िया सफाई हुई है इस बारे में पहले बहुत किल्लत थी और ठेकेदारों ने कभी अच्छा काम नहीं किया था। हमें इस बात का गर्व है और इसके लिए मै मुख्य हमने हरियाणा में टेल तक पानी नहीं देखा है। (थंपिंग) दूसरी बात मै यह कहना चाहता हूं कि यह कैनाल हरियाणा के कंट्रोल में आए। मै तो मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से यू0 पी0 में कोई सरकार बन जाए तो इस केस को जरूर टेकअप करें। आज वहां आबियाना हमें इक्ट्रा करना पड़ता है। फरीदाबाद के डी0 सी0 को वहां आबियाना इक्ठ्टा करना पड़ता है। वहां के फारमर्ज को एक और सबसे ज्यादा प्रोब्लम है जिसके बारे में हर्श कुमार जी ने भी बताया है कि वहां के फारमर्ज से हरियाणा प्रदे ा के दूसरे फारमर्ज से अढ़ाई गुणा ज्यादा आबियाना लिया जा रहा है जोकि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इस बारे में सरकार को विचार

करना चाहिए और वहां के फारमर्ज से भी वही आबियाना लिया जाना चाहिए जो आबियाना हरियाणा प्रदे ा के दूसरे फारमर्ज से लिया जा रहा है। (धन्यवाद)।

श्री सोमवीर सिंहः (लोहारू): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आगरा कैनाल जी कि पलवन और होडल के एरिया को पानी देती है उसके मेनली 11 चैनल्ज है जिसके बारे में मेंरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्या हर्श कुमार जी ने बताया था। उन चैनल्ज की 380 किलोमीटर की लम्बाई हैं उनकी सबसे ज्यादा जो समस्या है जो इन एरियाज के जमीदारों के सामने आती है वे 3–4 समस्याएं है। पहली समस्या तो यह है कि आगरा कैनाल का कंट्रोल यू0 पी0 गवर्नमैंट के पास है। दूसरी समस्या वह है कि वहां पर समय पर पानी नही आता है। जो पानी पहले आता था वह बहुत कम आता था। तीसरी समस्या यह कि उन एरियाज के किसानों से आबियाना बाकी हरियाणा प्रदे ा के दूसरे किसानों से अढ़ाई गुण ज्यादा लिया जाता है इसलिए उन एरियाज के किसानों से भी दूसरी किसानों के बराबर ही आबियाना लिया जाना चाहिए। उस कैनाल के बारे में पानी की चौरी का या कोई दूसरा केस हो जाता है तो वहां के किसानों को मधुरा या आगरा की कोर्ट्स में जाना पड़ता है और उनको वहां की समस्याएं झेलनी पड़ती है। इन समस्याओं को हल करने के लिए हरियाणा प्रदे ा की वर्तमान सरकार ने यू0 पी0 गवर्नमैंट को जहां पर इस समय गवर्नर भाासन, है से बातचीत की और जून, 1996 के अन्दर मुख्य मंत्री जी की

तरफ से यू0 पी0 सरकार के पास एक पत्र गया। उसके बाद वहां पर औफिसर्ज लैवल पर यह बात हुई है कि जो हरियाणा प्रदे ा के अन्दर चैनल्ज जाते है उसकी सफाई करने काम का काम हरियाणा सरकार को दे दिया जाए, उनकी सफाई का काम हरियाणा सरकार कर सकती है। उनकी सफाई काम पर हरियाणा प्रदे ा सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा। श्री हर्श कुमार और जगदी ा जी ने बोलते हुए बताया था कि पिछले करीब 20 साल से उस कैनाल की टेल पर पानी नही आया था। अब लोगों को उस कैनाल की टैल पर पूरा पानी मिल रहा है। हरियाणा सरकार ने उन चैनल्ज की मैटींनैस के लिए करीब 40 लाख रूपए मंजूर किए है। यू0 पी0 सरकार ने 19 चैनल्ज की सफाई करने का काम की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार को दी है। उन एरियाज के किसान जो काफी सालों से पानी के बारे में तकलीफ उठा रहे थे अब उनको काफी राहत मिलेगी। हम चाहते है कि जो बाकी की समस्याएं है उनको इस सदन की मार्फत उनकी सरकार के राहत मिलेगी। हम चाहते है कि जो बाकी की समस्याएं है उनको इस सदन की मार्फत उनकी सरकार के साथ उठाया जाए ताकि उन एरियाज के किसानों को जो तकलीफ है उनका कोई हल निकाला जा सके।

श्री खुर ीद अहमद (नूंह): डिप्टी स्पीकर साहब, आज सदन के सामने हमारे माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव पे ा पे ा किया है। मै समझता हूं कि इस प्रस्ताव को बहुत दिन पहले पे ा

करने की जरूरत थी। इसमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है यह अच्छी बात है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है उसका समाधान भी होना चाहिए। मेरे साथी जगदी ा जी, सांगवान जी और हर्श कुमार जी और सोमवीर जी ने जो अपने ख्यालात पे ा किए है मै उनसे सहमत हूं।

इस रैज्योल्यू ान की जो कापी है उसमें लिखा है–

This house recommends to the State Government to take up with the Uttar Pradesh Government the matter regarding taking over the administrative control of the Agra Canl, passing through the Haryana Territory.....

तो इसकी सख्त जरूरत है ऐडमिनिस्ट्रे ान भी हमारे हाथ में आना चाहिए। इसका जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में मै ज्यादा टाईम लेना चाहूंगा और बहुत है। इसमें लिखा है–

and also to increase the share of water of Haryana State.

यमुना में से और पानी ले लेना हमारे लिए बहुत जरूरी हे और खासकर गुडगांव और फरीदाबाद जिले के लिए यह पानी लेना बहुत जरूरी है हमारे साथ वहां जो हमे ाा होता रहा है वह इस वक्त यानि इस सीजन में भी हो रहा है। रबी की फसल के लिए दिल्ली से इतना पानी तकसीम होता था और उनको हमने जमुना में दिल्ली से पहले मुनक से लेकर पानीपत के पास यमुना में डालते है और इसके बदले 600 क्यूरिक्स वहां डालते है। 300

क्यूसिक्स इन्टाईलमैंट दिल्ली से आगे गुड़गांव कैनाल के लिए बनता है लेकिन इस रबी सीजन में जो हुआ है बहुत से दिनों तक एक क्यूसिक्स भी पानी नही मिल पाया और उसके बाद जो रिकार्ड मैने वहां से पता किया है कुछ दिनों तक तो बिलकुल ही नही मिला बाकी दिनों में 75 क्यूसिक्स से लेकर 175 क्यूसिक्स तक पानी चला है। अभी भी मालूम नहीं आज इस हफ्ते में क्या पोजी ान है। यह एक बड़ी भारी टिक्सलस क्वै चन है और इसके बाद आगे यमुना में पाली लेने में जो दिक्कत हमें आ रही है उसमें हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें यह डिसाईड किया है। 29–2–96 को यह डिसाईड किया है, जिसमें तकरीबन हमारे राईटस को कम किया है यह केस दिल्ली सिवरेज बोर्ड वार्सिज स्टेट ऑफ हरियाणा ए0 आई0 आर0, 1996 सुप्रीम कोर्ट 2992 है। इसमें फाईनल आर्डर करते वक्त उन्होंने बड़े सख्त लफ्ज हरियाणा के लिए इस्तेमाल किए है। और उनसे आईन्दा यमूना से पानी लेने के लिए जहां तक मै समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई अपील नही है, सिर्फ रिव्यू की बात रह जाती है। लेकिन रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट में मानी जाये या न मानी जाये क्योंकि लैग्वेज जो है उसमें बड़े जोर से लिखा है कि

That drinking is the most beneficial use of water and this need is so paramount that it cannot be made sub-sevient to any other use of water like irrigation.

तो हमें इरीगे ान के लिए पानी चाहिए तो हमे ाा यह तलवार हमारे ऊपर खड़ी रहेगी। इस केस को जो हमारे आफिसर्ज फेस कर रहे थे वे सुप्रीम कोर्ट कन्टैम्पट आफ कोर्ट से बाल–बाल बचे है क्योंकि जो पहले डिसिजन आया था उसमें विवाद रह गया था जिस कारण हमारे अधिकारी पानी नही दे पाये थे जिस कारण सारी स्थिति बिगड़ गई थी। इस बारे में मै पैरा 9 पढ़ कर सुनाता हूं।

Despite the aforesaid being the position, we are refraining from using our contempt jurisdiction in as much as the learned Advocate General has assured that Haryana would see that Delhli gets as much of water which it is presently recciving through Jamuna, if so directed by us. It is because of this statement that Shri Jaitley submitted that the Water Supply Undetaking is not keen to pursure the contempt proceedigs.Commodore Sinha too has taken the same stand. It is this gesture alongwith the statement made by Learned Advocate General, which has let us to close this proceeding, despite the highly objectionable conduct of the concened persons.

यानी वह ड्राप कर रहे है। इसका जो दूसरा पार्ट है वह हाईली ओब्जैक ान हमारे आफिसर्ज पर है। यानि हमारे आफिसर्ज का कैन्डैक्ट हाईली औब्जैक ानेबल बताया है। हमारे आफिसर्ज पर और इस मामले में जो उन्होने आखिरी राईडर दिया है, वह अपने आर्डर में जस्टिस आफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, वह इस प्रकार है–

We, therefore, close the proceeding by requiring Haryana to make available the aforesaid quantity of water to Dehli theroughout the year. let it be made clear that any violation of this derection would be viewed seriously and the gutliy person would be deait with appropriately. This order of ours would bind not only the parties to this proceeding, but also the Upper Jamuna Rever Board.

इससे आप अन्दाजा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लैग्वेज इस्तेमाल की है उससे भारी हमारी ऑफिसर्ज की क्या पोजी ान रह जाती है। स्पीकर साहब, सरकार से मेरी प्रर्थाना है इस फैसले पर रिव्यू फाईल किया जाए ताकि हमारे ऑफिसर्ज के सिर पर जो बोझ है वह कुछ कम हो सके। यू0 पी0 से दिल्ली को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली की प्यास इतनी ज्यादा है कि वह बुझने का नाम नही ले रही है। प्यासे को पानी पिलाया चाहिए यह हयूमन बात है लेकिन कितनी प्यास है, दिल्ली को कितना पानी चाहिए,यह भी तय होना चाहिए। अगर हम अपना पानी दिल्ली को देते रहेगे तो हमारे लोगों के लिए पानी की कमी होगी इसमें कोई भाक नही है। पानी की उम्मीद हमें आगे ही नही कि हमैं ओखला बांध से पानी मिल जाएगा। एक और समस्या मेवात ऐरिया को पानी देने की भी है। उनको पानी पीने के लिए भी चाहिए और आवपा ाी के लिए भी पानी की जरूरत उनको है। मेवात में पानी की समस्या के लिए प्रधान मंत्री जी से नूह की बात हुई। उन्होंने जो बात कही और आ वासन दिया उसके लिए

सरकार का भाुक्रिया। डिप्टी स्पीकर साहब, इसी के साथ गवर्नर एड्रैस में लिखा है–

A new scheme for construction of Mewat Canal costing Rs. 207 crore has been conceived after the Prime Minister.s visit to benifit the Mewat region. It well soon be posed to the Government of India and the Planning Commission for approval and Central assistance,

तो इसके बारे में हमारे लोगों की अप्रिहैस ान रही है कि ओखला ब्रान्च से नीचे जा कर इसको भाुरू किया जा रहा है। यह स्कीम पहले ही 1997–80 से चली आ रही है इसका परपज पहले कुछ और था लेकिन बाद में बाद में गुड़गाव कैनाल वाटर स्कीम काकरोई से भाुरू कर रही है ताकि हरियाणा के बाकी सिस्टम से यमुना के अलावा भी पानी मिल सके। दिल्ली को कितना दिया जाए। मुनक से दिल्ली को पानी दिया जा रहा है। इस प्रकार से जो इन्वैस्टमैंट किया जाएगा वह वेस्ट होग और हमं पानी नही मिल पाएगा इसलिए मेरी सरकार से यह दरख्वास्त है कि कि मेवात कैनाल की जो स्कीम है उससे फारूख नगर, पटौदी और गुड़गांव तहसील का ऐरिया है, का कहा गया है इसमें तावडू तहसील का ऐरिया और सोहना तहसील का एरिया कवर होना चाहिए। अगर यह स्कीम उधर से जाती है तो इससे तीनों तहसील कवर हो जाती है और इसके साथ ही दिल्ली को पीने का पानी तो मिल रहा है लेकिन जो दिल्ली का युजड पानी है इस्तेमाल करने के लिए कोई बांध ही नही (विघ्न) अगर अभी इन चीजों को

सोचें और मैसिव इन्वैस्टमैंट करे तभी हमें कुछ पानी मिल पाएगा अन्यथा हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साउथ हरियाणा में पानी का विवाद छिड़ा हुआ है। पिछली बार ऐस्टिमेंटस कमेटी के चेयरमैन बेरी साहब ने यह मुद्दा तफसील से उठाया था कि 18 लाख एकड़ फुट पानी था और एस0 वाई0 एल0 तो साउथ हरियाणा के लिए है उसमें अम्बाला तक का ऐरिया कवर होना चाहिए लेकिन वह इसमें नही हुआ है। अगर उससे पानी मिल जाता है तो वह पीने के लिए भी इस्तेमाल होगा। मेवात के खेतों के लिए भी पानी चाहिए और पीने का पानी। और जो नीचे का पानी है वह नमकीन है। इसके लिए जरूरी है कि जो मेवात कैनाल की पुरानी स्कीम है उसको उसी तरह से लेकर आगे चलाया जाए ताकि जिनके बारे में मैने जिकर किया है उनको भी पानी मिले। हमारे ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है उसको रिव्यू करें। अगर यह नही होगा तो ओखला से आगे हम पानी नहीं दे पाएंगे। वहां पर मेरे ख्याल से कोई प्रौब्लम वाली बात नहीं है, वहां पर थोड़ी सी प्रैक्टीकल डिफिकल्टी है जो कि दूर हो सकती है। जिन जगहौं की मैने पहले भी बात कही है वहां से यह कैनाल निकले ताकि वहां के लोगों को पीने का पानी मिल सके। गुड़गांव कैनाल में जो पानी है यह हमारे लिए बहुत जरूरी है इस बारे में इरिगे ान डिपार्टमैंट ध्यान दे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू करवाएं। अगर कोई गुंजाइ ा निकले तो साउथ हरियाणा, फरीदाबाद और गुड़गांव जिले को पानी दिलाने के बारे में पूरी कोि ा ा की जाए। धन्यवाद।

श्री रामजी लाल (सढ़ौरा अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो चर्चा चल रही है, आपने मुझे इस बारे में बोलने का समय दिया इसके लिए मै आपका धन्यवाद करता हूं। आज यहां पर आगरा कैनाल का प्र न जारी है। मेरे आदरणीय खु र्शीद अहमद जी ने बताया की यमुना नहर डिस्ट्रिक्ट यमुना नगर से होकर गुजरती है लेकिन वहां पर इसका किसी फायदा नही है। उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके इलाके से है हमारी खेती का जरिया एच0 एस0 एम0 आई0 टी0 सी0 है लेकिन इनके टयूबवैल खराब पड़े रहते हे, किसी की मोटर जल जाती है तो किसी का कुछ खराब हो जाता है और वे खराब ही पड़े रहते है। अब वहां पर सारे कनैक ान ही काट दिये गए है। हमारे यहां ओला वृश्टि हुई थी और मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम राहत देंगे। मै इनका आभारी हूं कि इन्होंने कुछ मुआवजा दिलवाया। लेकिन यह मुअलावजा काट कर दिया जा रहा है इनमें यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह पैसा नही कटना चाहिए। हमारे पास इरीगे ान का एम0 आई0 टी0 सी0 के अलावा कोई और चारा नही है। उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते है कि क्या हमें भी यमुना नहर से कोई नहर दी जाएगी ताकि हमारा इस एम0 आई0 टी0 सी0 से पीछा छूटे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इस बारे में कदम उठाएं और हमारे ऐरिया में भी एक नहर दें ताकि हमें भी खेती करने के लिए यह सुविधा मिले। धन्यवाद।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, आपका मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। आगरा कैनाल का जो इ ा है या जो कैनाल है यह ब्रिटि ा टाईम की है। उस समय जब इसको बनाया गया था तब ऐसी दिक्कत नहीं थी क्योंकि उस समय न तो उस समय हरियाणा था लेकिन पार्टी ान के बाद इस कैनाल को लेकर मुख्य समस्या यही आ रही है कि हमारे यहां के लोगों को पानी के लिए यह नहर बनाई गयी थी। पार्टी ान के बाद इस कैनाल का कंट्रोल यू0 पी0 गवर्नमैंट को दे दिया गया जिसके बाद से ही दिक्कत आनी भाुरू हुई। इस कैनाल का कमांड ऐंरिया तकरीबन डेढ़ लाख एकड़ है जो खास तौर से आगरा कैनाल के अंडर आता है लेकिन इसमें केवल चालीस इसमें से केवल चालीस हजार एकड़ एरिये की ही सिंचाई हो पाती है साथ ही पानी जरूरत के समय पर आता भी नहीं है। जब पानी की उतनी जरूरत नहीं होती तब इस कैनाल जब तक आगरा कैनाल का कंट्रोल हमारी सरकार के हाथ में नही आएगा या फिर इसका ज्वाइंट कंट्रोल नही होगा तब तक हमें दिक्कते आती रहेगी। (इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि वर्तमान सरकार ने 6 रजवाहों को कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। आप वहां इनकी सफाई कर सकते है लेकिन किसानों की तो मुख्यतः समस्या यही रही है कि जब उनको अपनी फसलों के लिए पानी की जरूरत होती है तब उनको पानी मिलता ही नही है। कई बार देखा गया है कि वहां के जितने भी इलाके है जैसे हथीन, बल्लभगढ़ या पलवल आदि तो वहां के एरिया के किसान

हमे ाा पानी मिलने से वंचित रहे है। मै आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार को इस मामले में यू0 पी0 गवर्नमैंट के साथ या सैट्रल गवर्नमैट के साथ बातचीत करके इस कैनाल का पूरा कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि वहां के किसानों को इस कैनाल से समय पर पानी मिल सके। अध्यक्ष महोदय, केवल पानी न मिलने की बात यहां पर ही नही है बल्कि एस0 वाई0 एल0 के अलावा हमारे यहां पर जो दूसरे पानी देने के सिस्टम है उनमें भी हमारे दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हो रहा है और हमारे दक्षिणी हरियाणा को उसका हिस्सा नही मिल रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आप कम से कम अपने हाउस को तो कंट्रोल कर लें। जो महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी या गुड़गांव के हिस्से का पानी है वह भी उनको नही मिलता। इसलिए जब तक सरकार इस कैनाल का कंट्रोल अपने हाथ में नही लेगी तब तक कुछ नही हो सकता। बजट में भी कहा गया है कि सरकार मेवात कैनाल वाली है लेकिन ये उस कैनाल के लिए पानी कहां से लाएंगे? इन्होंने यह भी कहा है कि इसको बनाने के लिए सैट्रल गवर्नमैट से पैसा लेकर आए है। लेकिन जब आपके पास पानी नही होगा तो आप क्या करेगे? हमारे पास आज तो ऐग्जिसटिग वाटर है तो जब अभी वहां के रजवाहों ने पानी नही आ रहा है तो फिर आप दूसरे जो रहवाहें बनाएंगे उनमें पानी कहां से लाएंगे? पहले हमारी सरकार ने भी खासतौर से महेन्द्रगढ़ एवं रेवाड़ी में रजवाहे बनाएं थे लेकिन पानी न मिलने की वजह से वे सूखे पड़े हुये ही खराब हो रहे है इसलिए अगर आप और बना

देंगे और उनमें पानी नही मिलेगा और वे सुखे ही पड़े हुये रहेगे तो फिर उनको मेनटेन करना भी मु कल हो जाएगा। आपने जिस छः रजवाहों का कंट्रोल भी आने हाथ में लिया है तो इनके लेने से भी कोई फर्क नही पड़ेगा। अगर आपकी गुड़गांव और फरीदाबाद के एरिये को खु ाहाल बनाना है तो इस मामले में आपकी पूरी को ा ा करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, राज्यस्थान गवर्नमैंट भी ऐसा करती है जब उनको पानी की जरूरत नही होती तो ये साहबी नदी में पानी छोड़ देते है जो कि तबाही मचाता है। पिछले दिनों भी अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि राजस्थान सरकार ने ऐसा ही किया था जिसके कारण धारूहेड़ा आदि के एरिये में बहुत नुकसान हुआ था। वहां पर मसानी बैराज में भाटर नही लगे थे इसलिए वहां नुकसान हुआ। जब तक मेन कैनाल का कंट्रोल अपने हाथ में नही होगा तब तक बात नहीं बनेगी। यह बात ठीक है कि आपने छह रजवाहे अपने कंट्रोल में लिए है लेकिन जब तक आपका ज्वांइट कंट्रोल न हो या फिर सारा कंट्रोल आपके हाथ में न हो तब तक हरियाणा प्रदे ा के किसान खु ाहाल नही हो सकते है। धन्यवाद।

श्री रमे ा कुमार (बड़ौदा, अनुचित जाति): अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के हित में पानी के लिए चर्चा चल रही है और आगरा कैनाल के बारे में सभी साथियों ने अपने–अपने सुझाव रखे है। जो यह आगरा कैनाल है यह ओखला से निकलती है और इसका टोटल कंट्रोल उत्तर प्रदे ा सरकार के हाथ में है। इनकी

मेन्टीनैंस, रिपेयर का काम, मागे आदि तथा और प्रबन्ध करने का काम उतर प्रदे ा सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है। हरियाणा सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जब तक हरियाणा के हाथ में यह काम नहीं आएगा तब तक हरियाणा के किसानों का भला नही हो सकता हैं। इस कैनाल में 11 चैनल्ज और तीन डिस्ट्रीब्यूटरीज है इनके बारे में भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा इस सरकार ने नारा दिया था कि हम एस0 वाई0 एल0 को पूरा करेंगे और गंगा का पानी लेकर आएगे और दादूपुर नलवी नहर को भी पूरा करवाएंगे। आज हरियाणा प्रदे ा के लोग इस सरकार की तरफ उम्मीद से देख रहे है कि इस सरकार ने जो वायदा किया था उसे पूरा करेगी। इन्होंने एस0 वाई0 एल0 का मुद्दा लेकर विधान सभा में प्रवे ा किया था लेकिन आज न तो हरियाणा में एस0 वाई0 एल0 का पानी आया है और न ही दादूपुर नलवी नहर को पूरा किया गया है। गंगा के पानी के बारे में इन्होंने कहा था कि ऋशिके ा से लेकर करनाल तक नहर के काम को पूरा किया जाएगा लेकिन आज तक इसको पूरा न किया गया। यह हरियाणा प्रदे ा के लोगों के साथ सरासर अन्याय है। दक्षिणी हरियाणा के किसानों को अपनी फसल को पानी देने मके लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि आज पानी जमीन के अन्दंर नही है और जब तक पानी नही मिलेगा तब तक किसान अपनी फसल के उत्पादन को नही बढ़ा सकता है। मै खासकर सोनीपत जिले की और से आपसे यह अनुरोध करता हूं कि सोनीपत जिला भी एक ऐसा एरिया है जहां

पानी खारा है और वहां नहरों में पानी अच्छी तरह से नही आता है। जब तक हरियाणा सरकार उतर प्रदे ा सरकार से आगरा कैनाल का नियंत्रण अपने हाथ से नही लेगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। पिछली दिनों कुछ दूसरी स्टेटों को हरियाणा का पानी दिया गया था लेकिन सरकार ने उनकी ओर कोई तवज्जों नहीं दी थी। हरियाणा सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। रजवाहों में जो सफाई का काम चला हुआ था वह बंद है। रजवाहों की कोई सफाई नही हो रही है। मेरे हल्के में बुटाना डिस्ट्रीब्यूटरी है वहां कोई सफाई नहीं है। वहां ट्यूबवेल भी नहीं चलते क्योंकि बिजली ही नहीं आती है। इसलिए किसानों के लिए जो बुटाना डिस्ट्रीब्यूटरी है उस नहर की सफाई की जाये ताकि किसानों को पानी मिल सके और आगरा कैनाल का कंट्रोल अपने हाथ मे लेना चाहिए। जय हिन्द धन्यवाद।

श्री आध्यक्षः जसविन्द्र सिंह जी बोलिए।

श्री जसविन्द्र सिंह संघु (पेहवा): अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथियों ने आगारा कैनाल का कंट्रोल हरियाणा सरकार के हाथ में लेने के बारे में जो रैजोल्यू ान दिया है यह एक इच्छा प्रयास है जैसा कि पहले बताया गया है कि 6 चैनल्ज का कांट्रोल हमारे हाथ में आ गया है माननीय साथी श्री हर्श कुमार जी ने बताया कि आगरा नहर का कंट्रोल हरियाणा सरकार के हाथ में आ जाने बाद उस नहर की सफाई हुई और उसके बाद उनके क्षेत्र का वाटर टेबल ऊंचा हो गया है। स्पीकर सर, आज जो पानी की

चिन्ता है वह सभी हरियाणा वासियों की चिन्ता है और यह जब से हरियाणा प्रदे ा अलहदा हुआ है यह समस्या चल रही है क्योंकि पंजाब से हमें एस0 वाई0 एल0 का पानी मिलना था परन्तु उस पानी को लाने में हम कामयाब नहीं हुए है। पिछली सरकार ने तो हरियाणा प्रदे ा का पानी का हिस्सा का हिस्सा घटाकर दूसरे प्रदे ाों को दे दिया और इसके बारे में चौधरी बंसीलाल भी विरोध करते रहे थे। आज वैसी बात नहीं होनी चाहिए। जैसा की माननीय साथी श्री रमे ा खटक जी ने बताया कि चौधरी बंसी लाल जी ने तो चुनाव प्रचार किया था कि अगर हमारी सरकार आ गई तो एस0 वाई0 एल0 का पानी लेकर आएंगे। परन्तु इस सरकार ने कभी भी इस बारे विपक्षी दलों के साथ विचारविम र्ा नहीं किया। माननीय साथी कैप्टन अजय सिंह ने ध्यानकर्शण प्रस्ताव के जारिये नारनौल और रिवाड़ी में बिजली के बिल बढ़ने का कारण पानी की कमी की वजह से बताया है। मै आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहाना चाहूंगा कि पहले पंजाब और हरियाणा इकट्ठे थे और कुछ साल ही हुये है जब ये अलग हुए है। आज पंजाब के मुख्य मंत्री ने वहां की जनता के लिए पानी और बिजली बिल्कुल फ्री कर दिये है। मै मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे भी बिजली और पानी को बिल्कुल फ्री कर दे। स्पीकर सर, आगरा केनाल का कंट्रोल हमारे स्टेट के पास आ गया है तो एक अच्छा प्रयास है। इससे हमें फायदा भी होगा। आगरा कैनाल का कंट्रोल हमारी स्टेट के हाथ आने से फरीदाबाद और गुड़गांव के यानि दक्षिणा हरियाणा को ज्यादा फायदा होगा। यदि

मुख्य मंत्री जी के मन में दया आ जाए तो इसका इंडायरेक्ट फायदा अम्बाला, कुरूक्षेत्र और कैथल जिलों को भी हो सकता है। जब चौधरी बंसी लाल जी पहले मुख्य मंत्री बने थे तो हमारे अम्बाला, कुरूक्षेत्र और कैथल जिसकी सिंचाई नरवाना बांच से होती थी, उससे एम0 आई0 टी0 सी0 के टयूबवैलों द्वारा पानी आगे ले गए थे। उस समय वजह कुछ और थी लेकिन उस कारण आज कारण हमारे इलाको का वाटर टेबल 100 फीट से ज्यादा नीचे चला गया है उस पानी को निकालने के लिए हमें मीटर को 90 100 फीट नीचे लगाना पड़ता है। पहले 5 हार्स पावर की मोटर से काम चल सकता था परन्तु आज 20–25 हार्स की मोटर लगानी पड़ रही है। मेरा आपके जरिए मानीनय मुख्यमंत्री जी से पुरजोर अनुरोध है कि हमारे वाटर लेबल को उपर लाने के लिए प्रयास अव य किये जायें बरना हमारा क्षेत्र राजस्थान बनने वाला है। मै माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात और कहूंगा कि आगरा कैनाल का कंट्रोल जल्दी से जल्दी से अपने हाथ में ले। इसके साथ ही यमुना कैनाल का समझौता है और एस0 वाई0 एल0 का मसला है उसके बारे मी भी सीरियस होकर प्रयास करें। इसके साथ ही मै अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः चौधरी बीरेन्द्र सिंह, आप बोलियें।

श्री बीरेन्द्र सिंह (उचाना कला): स्पीकर महोदय, यह जो आफिसियल रेजोल्यू ान हमारे कुछ माननीय विधायक श्री जगदी ा जी ने दिया है कि आगरा कैनाल जो बैसिकली एरिया

है, वह यू0 पी0 को ही सिंचित करती है और कुछ हिस्सा हरियाणा राज्य का भी उस नहर से सिंचित होता है। उसके कंट्रोल के बारे में ये प्रस्ताव लेकर आए है। यहां पर जो हमारे माननीय साथी है ये उसी इलाके से संबंध रखते है और हर चुनाव में यहां के लोगों से वायदा किया जाता है। खासतौर में 4–5 विधान सभा क्षेत्रों की मै बात कर सकता हूं जैसे कि बल्लभगढ़, हसनपुर, हथीन, पलवल और कुछ इलाका फिरोजपुर झिरका और नूंह का जोकि इस नहर से सिंचित होता है और इसके साथ ही आगरा कैनाल के अप–स्ट्रीम वहां से गुड़गांव कैनाल भी निकलती है। जब भी चुनाव होते है तो हरियाणा में दो ही मुख्य मुद्दे हर राजनैतिक दल अपने–अपने तरीके से किसानों के पास, देहात के लोगों के पास, हरियाणा की जनता के पास लेकर के जाता है कि हमें वोट दो। वे कहते है कि अब की बार अगर हमें सता लेकर के आओगे तो हम आगरा कैनाल का कंट्रोल हासिल करेंगे तथा जहां तक हरियाणा का क्षेत्र है वहां पर यू0 पी0 सरकार का कोई दखल नहीं होगा और हम वह नहर चलाएंगे हमारा उस पर पूरा कब्जा होगा। इसके अतिरिक्त, दूसरा मुद्दा हर बार हर राजनीतिक दल यह लेकर के आता है कि हमें सता सौप दो तो हम आपको एस0 वाई0 एल0 नहर का पानी लाकर के देंगे। आज स्थिति यह है कि यह बात सुनते–सुनते अब हरियाणा के लोगों ने यह नि वास कर लिया है कि यह बात सिर्फ चुनावी वायदे तक ही सीमित है तथा इन बातों पर किसी मुख्यमंत्री ने किसी सरकार ने कोई सीरियनैस से कभी इस पर अमल करने की कोि ा ा नही की। पिछले 26

साल से एस0 वाई0 एल0 का मुद्दा भी इस प्रकार लटका पड़ा रहा। लेकिन क्लेम यह किया जाता है कि 85 प्रति ात काम हो गया। बंसी लाल जी आएंगे तो कहेगे कि ज्यादातर काम उन्होंने करवाया है, चौ0 भजन लाल जी कहेंगे कि उनके राज में नही मेरे राज में यह कार्य हुआ है तथा चौटाला साहब को तो समय नही मिला। 6 महीने तक ये मुख्य मंत्री रहे तथा इस दौरान 3 बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन चौ0 देवी लाल जी का समय मिला था, उन्होंने तो 4 साल हरियाणा पर राज किया है। उन्होंने वायदा किया था कि हम एस0 वाई0 एल0 कैनाल लेकर के आएंगे। लेकिन मेरा अपना आगरा कैनाल के बारे मे नजरिया है। मै मानता हूं कि अगर हम कोि ा ा करते रहे है कि आगरा कैनाल का हरियाणा के क्षेत्र से गुजरने तक का कंट्रोल हम यू0 पी0 सरकार से ले सकेंगे तो मुझे इसके बारे में कुछ नही पूछना है। लेकिन मै यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह यही समाधान है कि यू0 पी0 सरकार से उसका कंट्रोल हासिल करें या कोई दूसरा समाधान भी है जिससे यू0 पी0 सरकार का दखल ही खत्म हो जाए। मेरा अपना यह मानना है कि पिछे कितनी मिटिगे हुई। 1973 से लगातार कैनाल के कंट्रोल के बारे में बार–बार मीटिगें हुई है। सचिव लैवल पर भी, मंत्री लैवल पर भी और दोनो सरकारों की आपस में भी मिटिंग हुई है लेकिन कोई निश्कर्श या परियणाम नही निकाल सके हैं और इसकी वजह यही है कि उतर प्रदे ा की सरकार जिस ने इस दे ा 6–7 प्रधानमंत्री दिए हो और जो अपने आप में एक वि ााल दे ा है। वह प्रदे ा नहीं है। उसकी आबादी

को अगर देखा जाए तो यह दुनिया का छठा दे ा है। दुनिया में ऐसे 5 दे ा है जिसकी आबादी उतर प्रदे ा से ज्यादा है और फिर उतर प्रदे ा का नंबर आता है। 16 करोड़ की आबादी का जो प्रांत हो उसे हरियाणा सरकार वन–टू–वन डील करे। केन्द्रीय सरकार को भी अगर तकलीफ हुई तो उसको यू0 पी0 की तरफ सहानुभूति रही है। मै मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि क्या हम इसका कोई दूसरा औ ान तला ा कर सकते है। एक बार पहले एक स्कीम बनी थी। जहां से यह कैनाल टेकऑप करती है और टैकऑप करने की जगह से लेकर जहां पर हरियाणा प्रान्त की सीमा समाप्त होती है वहां तक इसके साथ–साथ एक पैरलल चैनल हम तैयार करेंगे। उस समय के एस्टिमेंट के मुताबिक उस पर लगभग 6 करोड़ रूपये खर्च होने थे। जब हम उसके साथ–साथ एक पैरनल चैनल तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे तो उस पर किसी के कंट्रोल की जरूरत नही होगी उस पर हमारा ही कंट्रोल होगा जहां से यह नहर टेक आफ करेगी। औखला से जहां से यह नहर टेक आफ करेगी और हरियाणा प्रदे ा की सीमा तक जितनी डिस्ट्रीबयूटरीज है जितनी माइनर है, उनको पूरा पानी मिल जाएगा। आगरा कैनाल 780 क्यूसिक की हो सकती है। जैसे हमारे मानीय मंत्री श्री कर्ण सिंह दलाल ने बताया था कि 780 क्यूसिक्स पानी का हरियाणा का हिस्सा हैं। मेरा अपना यह मानना है कि अगर हम इस तरह का प्रावधान कर सके तो यू0 पी0 सरकार से हमारा कुछ लेना देना नही होगा। हम अपने किसानों

को यही तौर पर फायदा पहुंचा सकेंगे। क्यों जगदी ा नायर जी मेरी बात ठीक है।

श्री जगदी ा नैयरः जी हां। आपकी बात ठीक है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः हमारे माननीय सदस्य श्री खुर ाीद अहमद जी ने भी एक बात की तरफ इ ाारा किया कि 1994 में राजस्थान, दिल्ली, यू0 पी0 हरियाणा प्रदे ा और हिमाचल प्रदे ा सरकारों का जो जल समझौता हुआ उसमें भी हरियाणा प्रदे ा की सरकार ने प्वायंट लूज किया। हम उस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे उस समय हमने यमुना अकोई को नही माना था। उस समझौते गलत माना था। इस सदन के और भी बहुत से दूसरे सदस्य है जो उस समय भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नही सकते। दिल्ली डेढ़ करोड़ की आबादी का भाहर है। वह दे ा की राजधानी है। जो भाहर अपना एक अन्तर्राश्ट्रीय महत्व रखता हो उसको हम प्यासा छोड़ दें तो यह बात भी ठीक नही है। मै यह देख रहा था यह दलौल सुप्रिम कोर्ट की जजमैंट में भी दी गई है। मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि उस यमुना अकोर्ड की सार्थकता तभी हो सकती है जब उस अकोर्ड मैं अपर रीचीज पर किसाउ और रेणुका डैम्ज को बनाने के लिए प्राथमिकता दें। केन्द्रीय सरकार को हम इस बात के लिए सहमत कराएं कि किसाउ और रेणुका डैम को बनाया जाए क्यौंकि जो यमुना रीवर है अगर उसको हम पैरनियल रीवन की संज्ञा देते है तो घग्गर रीवर की तरह बरसात के मौसम में भरकर चलती है और बाकी

8–9 महीने रहती है उसकी वजह यह है कि उधर से इस्टर्न यमुना कैनाल और वैस्टर्न यमुना कैनाल अपना हिस्सा ले लेती हैं जिसके कारण ताजेवाला हैड के नीचे पानी नहीं जाता है। यमुना रीवर में पानी कम होने के कारण दिल्ली को पानी देने के लिए भाखड़ा नहर का पानी मुणक हैड वर्कस से यमुना रीवर में डाल कर दिया जा रहा है। मेरा अपना यह कहना है कि वैस्टर्न यमुना कैनाल सिस्टम से जो सिंचाई के लिए पानी मिलता है उसमें 14 जिलों का हिस्सा है, उस पानी से हमारे 14 सिंचित हो जाते हैं लेकिन 14 जिलों पानी के लिए तरस रहे है। एक तरफ हम एस0 वाई0 एल0 कैनाल की बात करते है। मै कहता हूं कि आप एस0 वाई0 एल0 नहर की बात तो एक तरफ रखिए, वह पता नही, कब पूरी तरह से नुकम्मल होगी, वह एक अलग स्थिति बनती लेकिन उससे पहले अगर हम अपनी प्राथमिकता देखते तो किसाउ डैम से यमुना के पानी को रैगूलेट किया जा सकता है जो 3 महीने फल्ड वाटर है जो बारि ा का पानी है उसको अगर वहां से रैगूलेट किया जाये तो सारा डब्ल्यू0 जे0 सी0 सिस्टम है उसके पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और जो आगरा कैनाल है, उस में पर्याप्त मात्रा में पानी जा सकता है। यह बात बिल्कुल सही है अगर आप गुड़गांव नहर और आगरा कैनाल का पानी देखें तो ऐसा लगता है जैसे गन्दे नाले का पानी है। वह पानी सिंचाई के लिए भी ठीक है और वह अगर वह पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है तो इससे भयानक स्थिति हो ही नही सकती। जैसे काला तेल होता है, इस तरहह से वह पानी है और उसमें दिल्ली का सारा गन्दा पानी वहां

जाता है और पता नही एनावायरनमैंट के लोग कहां सोए हुए है। मेवात के अन्दर अगर 83 प्रति ात जनता का हिमोगलोबिन 6 प्रति ात से नीचे है, मेवात के अन्दर, अगर गरीबी है मेवात के अन्दर अगर लोग पूरा भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस चीज को हम स्वास्थ्य के लिए अच्छा मानते हे वह है पोर्टेबल वाटर, हम अगर वही पानी आंख से देखते से पता लगता है कि इससे गन्दा पानी हो ही नही कसता उसको पीने की स्थिति में क्या होल होता होगा। स्वास्थ्य की स्थिति में क्या हाल होता होगा। उस मै मानता हूं कि अगर सबसे बड़ी जो महमारी वहां पर फैली थी, डेगू के नाम से उसमें यह भी एक कारण होगा। मै उसको डेगू की बिमारी नहीं मानता क्योंकि डेंगू तो अमीर आदमियों के घरों में होता है, मच्छर वहीं होते है जहां पर अमीर लोगों के पास एयर कन्डी ान्ड और कूलर है वही मच्छर आकर बैठ जाता है, वे गन्दे पानी पर आकर नहीं बैठते। बीमारी की जगह तो है वह पोल्यूटिड वाटर है जो ओखला हैड वर्कस से गुड़गांव कैनाल का और आगरा कैनाल में जाता है। मेरे ऐसा कहने से अभिप्राय यह है कि डब्ल्यू0 जे0 सी0 सिस्टम को स्ट्रैन्थन करने के लिए और इस गन्दे पानी से बचने के लिए एक ही समाधान है कि हम कि ााउ डैम की प्राथमिकता को समझे। कि ााउ डैम आज से 65 साल पहले कन्सीव किया गया था। इस डैम कीवही इम्पोर्टेन्स थी जो आज भाखड़ा डैम की है। भाखड़ा डैम जिसमें सतलुज, में रावी से पानी मिलेगा। अगर ये न होती तो भाखड़ा डैम भी नही होता तो फिर इन नहरों की सज्ञा भी

बदल दी जाती और कह सकते हैं कि जैसे यमुना रीवर है, वह ताजेवाला हैडवर्कस कहा रहा हूं कि आपने इस बात को कंसीव किया कि गंगा का पानी हरियाणा को मिले जब आप इलैक ान लड़ रहे थे। आपने अपने भाशणों में 1100 क्यूसिक नहर की बात कही थी। वह हो सकता है, फिलहाल वह अपने में एक स्वप्र नजर आता है, हो सकता है कि वह एक ड्रीम हो लेकिन पोसीबल है उसकी पोसिबिलिटी को एक्सपोयलयट किया जाना चाहिए। कई बार ऐसा प्रतीत होता है। यह बड़ी अजीब स्थिति है। कई बार जो इन्जीनियर्ज है, ब्यूरोक्रेटस है, इकोनिमिस्ट्स है, वह यह कहकर उस प्रोजैक्ट को नकार देते है कि इसकी कोस्ट बढ़ेगी। कोस्ट के हिसाब से इससे कोई फायदा नही है। मुख्यमंत्री जी आपको याद होगा, 1968 से पहले जब आप पहले मुख्य मंत्री बने थे उस वक्त आपने घग्गर, भाखड़ा, टांगरी इन तीनों नदियों पर बैराज बनाने का एक प्रौजैक्ट तैयार करवाया था और इस बैराज बनने की स्थिति में यह कहा गया था यह बैराज बन कर तैयार हो जाएगा तो हरियाणा में सारे साल में से 3 नहरों में दो महीने के लिये पानी मिल सकता है और कॉस्ट ऑफ बैनिफिट रे ाो के आधार पर उन बैराज को भौल्च कर दिया है ठण्डे बस्ते में रखा दिया गया है। मै आज भी मानता हूं कि हम कब तक हरियाणा की जनता को राजनैतिक तौर पर एस0 वाई0 एल0 के नाम पर गलतफहमी में डालते रहेगे या गंगा के नाम पर या यमुना के नाम पर उन्हें सपने दिखाते रहेगे। स्पीकर साहब, किसाऊ डैम का मैने जिक्र किया if with all seriousness it is taken up, then there is

a possiblity that Yamuna river can be called as perrnial river, otherwise it is no more a perrenial river.

लेकिन मै कहता हूं कि यह बैराज भी आप बनाएं। हरियाणा सरकार के मन में एक बात कॉस्ट ऑफ बैनिफिट रे ाो की हो सकती है इससे इसको कुछ भी लेना देना नही है। I want to find out different sources of water than SYL and Yamuna. जो एक सीरियस इ ू बचा हुआ है जिसके बारे में हम कुछ कर सकते है। अगर यह बैराज बना दिया जाए तो इसमें दो चीजें है। एक चीज तो यह होगी कि जो सरकार ने ि ावालिक डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाया हुआ है उसके बारे में मैने न्यूज पढ़ी है कि 5 साल में 31 करोड़ का प्रावधान किय गया है, यह इस बोर्ड के साथ एक प्रकार का मजाक है। चाहे मेवात बोर्ड हो या ि ावालिक डिवैल्पमैट बोर्ड हो उसके लिए ज्यादा पैसे का प्रावधान होना चाहिए। कालका से लेकर पौटा साहब तक जितने फुट हिल्ज है उनमें सोयल इरोजन होता है मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं 14 दिन के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना था तो उस वक्त मुझे इसे देखने का मौका मिला था उस वक्त मैने देखा कि ि ावालिक फुट हिल्ज में एक हजार वाटर मैनेजमैंट भौडज बनाने के लिए प्रावधान किया गया था आज आप जरा गहराई से इस बात की देखिए कि इस बात को 14–15 साल हो गये है। एक हजार प्वांयट्स आईडैटीफाई किये गये थे और उनको बनाने के लिए तीन महकमें लगे हुए थे। फोरेस्ट वाले कह रहे थे कि यह हमारी रीचिज में है इन्हें हम बनाएगे, नहर वाले महकमे के लोग कह रहे

थे कि हम बनाएंगे और पंचायत राज महकमे वाले कहते थे कि हमारे सिस्टम में यह आते है हम बना सकते है लेकिन कहीं पर कोई आडिने ान नजर नही आया। एक हजार में से केवल 26 बना पाए है। जब तक यह सभी भौडंस तैयार कर दिए जाएं और फलोरिक्ल्चर और होर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। जिस प्रकार क मीर में हालात खराब होने के बाद हिमाचल प्रदे ा ने ना ापाती और सेब की मार्किट हथिया ली है हम भी उसी प्रकार से फलोरिकल्चर और होर्टिकल्चर की मार्किट कैप्चर कर सकते है। वहां की हालात और अर्थ व्यवस्था की ओर किसी का ध्यान नही है इस बात की गहराई से नहीह देखा गया है जैसे कि गवर्नर महोदय के एड्रैस में इसका जिक्र आया है और एक सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने भी बताया है कि 1238 या 1307 करोड़ रूपये का राजस्व आ चुका है। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, मै हाउस में बताना चाहूंगा कि सोलह सौ कुछ करोड़ का यह लक्ष्य था जो रियालाईज किया जा चुका है वह तो उन्होंने बता दिया था उसके बाद फरवरी और मार्च का उसमें इन्क्लूड होना है।

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि इनकी टैक्सिज की रियलाइजे ान 13 सौ करोड़ से बढ़ाकर 16 सौ करोड़ हो गई है। (विघ्न) मै तो यह कहता हूं कि आपकी रियलाजे ान 2 हजार करोड़ रूपये भी हो सकती है। इस बारे में मैने कई बार मुख्य मंत्री जी से कहा लेकिन इस द ाा में कुछ

प्रयास नही किया गया। आपकी सरकार ने जहां प्रोहिबि ान को लागू किया, उसी के साथ टैक्सिज का भार भी चार सौ या पांच सौ करोड़ का इस प्रदे ा पर पड़ा। इस वजह से बिजली की दरों को बढ़ाया मानना है और अगर आप चाहें तो इस बारे में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ले सकते है कि हरियाणा में कमर्ि ायल टैक्सिज की कलैक ान जो ऐक्चुल में होनी चाहिए उसकी 30 प्रति ात की होती। उस 30 प्रति ात की भी हिस्सेदारी है यह हिस्सेदारी उन लोगों की है जो मैनेजमैंट में हिस्सेदार है और उन लोगों की जो बिजनैस चलाते है। 50 प्रति ात टैक्स टोटल इवेजन है। मेरा यह मानना नहीं है कि हमारा व्यापारी पर कोई एतवार नहीं है। लेकिन आज एक प्रथा बन गई है कि अगर मेरी 25 लाख की रिटर्न है तो मै 15 लाख के टैक्सिज नहीं दिखाऊंगा। 10 लाख के दिखाऊंगा। 10 लाख की रिटर्न फाईन करूंगा और 5 लाख में भोयर करूंगा। अढाई लाख रूपये खुद बचाऊंगा और अढ़ाई लाख रूपये बचाने वाले को दूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह प्रथा आज है। आधा पैसा रिटर्न में फाइल नहीं करूंगा। स्पीकर साहब, कामर्ि ायल टैक्सिज के मिनिस्टर यहां पर नही बैठे है। मै यह पूछना चाहता हूं कि यह सिस्टम क्या है। असैसी को तकलीफ हो तो वह हाई कोर्ट में जा सकता है। वहां पर उसकी तकलीफ न मिटे तो वह ट्रिब्यूनल में जा सकता है। ट्रिब्यूनल में बड़े–बड़े आई0 ए0 एम आफिसर्ज बैठे हुए है वहां पर उनकी रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जहां पर सरकार से धोखा हुआ है वहां सरकार किस अपील में जाती है, कब जाती है। इस टैक्से ान के स्ट्रूकचर में यह सबसे बड़ी

एनोमली है। सरकार का अगर कोई 10 लाख का चूना लगा जाए उसका कुछ नही। जब में मंत्री था तो मैने अफसरों से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते है, एसैसी को तो अख्तियार है, उसको तो प्रिवलेज है कि अगर उसको कोई तकलीफ है तो यह कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाएगा। वे कहने लगे कि साहब ऐसी बात नही है, हम 10 प्रति ात केसिस को एट–रैडम चैकिंग करते है। जहां हमें कुछ लगता है वहां हम केस को रि–ओपन कर देते है।

अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो यह बात दावे के साथ कर सकता हूं कि इस सरकार ने जो टैक्सिज बसों के भाड़े के रूप मे औ बिजली की दरों के बढ़ाकर लगाए है उसकी कोई जरूरत नही थी। आपकी जो टैक्स कुलैक ा 16 सौ करोड़ रूपये की है हम उससे ऊपर 2 हजार करोड़ रूपये तक या उससे भी ज्यादा जा सकते थे अगर आप उनके थोड़े से नट टाईट कर देते है। अगर ऐसा होता तो किसी गरीब आदमी पर किसी नए टैक्स का भार नही पड़ सकता था। लेकिन इस दि ाा में ये कुछ नही करते। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मै बंसी लाल जी से कहना हूं कि he enjoys a particular reputation as development ariented Chaif Minister and that reputation is getting eroded. (विघ्न) स्पीकर साहब, अगर इनको पूरा पैसा नही मिलेगा तो डिवैल्पमैंट कहां से होगी। किए है। पैसे की कमी की वजह से हमने नाथपा झाखड़ी प्रौजैक्ट से अपना हिस्सा वापिस ले लिया, पैसे की कमी की वजह से थीन डैम से घबरा कर बाहर चले गए और जिसकी वजह से हम पानी के लिए तरसते है। अब हम सोचते है कि चलो

और कुछ नही तो गुड़गांव कैनाल का कंट्रोल अपने हाथ मे लेने से कुछ हमारा काम चल जाए और हमारे पानी में इजाफा हो जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब तक कि ाऊ डैम नही बन जाता तब तक हम वहां पर कोई टैम्परेरी अरेंजमैंट कर सकते है। पता नहीं कि खु र्ीद जी मेरी इन बात का पंसद करेगे या नही लेकिन मेरा अपना विचार है कि मेवात के इलाके चाहता झील है और उसका सारा पानी उजीना डायवर ान ड्रैन के थ्रू निकल जाता है लेकिन मै यह कहना चाहता हूं कि जब यमुना में बारि ा का पानी होता है तो उस पानी को अगर इंजीनियर्ज डायवर्ट करके उन्ही ड्रैन से उन लेक्स में डाल दे अलग अलग जगहो पर तो उस पानी को वहां से मेवात के सारे किसान अपनी दो फसलों पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर करते है। स्पीकर सर, इस हरियाणा का एक तिहाई से ज्यादा 35 परसैट से ज्यादा हिस्सा जी कि रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों में पड़ता है ऐसा है जहां पर किसान को सही तौर पर एक ही फसल मिलती है। ये ऐसे जिले है जहां लोगों को पानी न मिलने की वजह से एक की फसल पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर सरकार वहां के किसानो को भी यह वि वास दिलाए कि उनको पूरा पानी मिलेगा तो उन ऐरियाज के किसान वहां के किसान भी दो फसलों की बजाए तीन फसलें पैदा कर सकते है। स्पीकर सर, मै एक गांव का नाम तो नही लेता लेकिन यह गांव कुरूक्षेत्र जिले में हमारी बिरादरी का है। जब तीस साल पहले वहां पर गेहूं या जीरी पैदा नही होती थी तो वहां के जाट के रि ते दूसरे गांव के

जाट नही लेते थे। (विघ्न) लेकिन जब ग्रीन रैवेल्यू ान आयी तो उस गांव में कोठी उभर आयी है अब लोगों का कहना यह है कि हमारी उन से बात कराओ तो स्पीकर सर, आर्थिक स्थिति आदमी का सारा कुछ बदल देती है। मै यह कहता हूं कि आज अगर मेवात के इलाके में सोनीपत के इलाके में और रोहतक के इलाकों में फर्क है तो फर्क का कारण यही है कि वहां एक फसल पैदा होती है। हम इस बात का नकार नही करते। मेरा आपसे यह कहना है कि यमुना के पानी की और बरसात के पानी की आज जो युटिलाइज करने की पद्धति है, उसका अगर हम सही इस्तेमाल करें तो सारे का सारा मेवात का इलाका ठीक हो सकता है। इस इलाके में मेन क्राप सरसों ही है और इसके अलावा वहां कोई दूसरी क्राप पैदा नही होती। साथ ही वहां पर नीचे का पानी खारा है और पहाड़ों से पानी आता है वह तबही मचाता है। अगर वहां पर भी वाटर भोड का प्रावधान किया जाए तो उस इलाके का भी पूरा दोहन हो सकता है और वे हिल्ज होटीक्चर के लिए दोहन की जा सकती है तथा वहां के लोगों की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। मै यह बात इसलिए, कहना चाहता हूं कि खेती ऐसा धंधा है जिसमें खेत के मजदूर की सारी उम्र की हिस्सेदारी है। किसान अपनी दी ढाई हजार की आमदनी से चार साढ़े चार हजार रूपये की आमदनी से खु ा रहता है लेकिन जो दूसरे धंधे है जैसे व्यापार है, इंड्रस्ट्री है वहां पैसा मल्टीप्लाई होता है यानी चार से आठ, आठ से सोहल और सोलह से बतीस बनता है लेकिन किसान के साथ ऐसा नही होता है। आज जिसको हम

उदारीकारण कहते है और जिसका पदापर्ण पिछले पांच छः सालों में भारत के अन्दर हुआ है। आज प0 जवाहर लाल नेहरू के सौ ालिज्म का पता लगता है कि उस आदमी का उस आदमी का उस समय क्या वीजन था और जिसकी वजह से पिछले 35–40 सालों में भारत के माध्यम वर्ग का ब्रोडगेज हुआ था। आज जब से उदारीकरण की नीति आई है तो हमने इस बात पर ध्यान नही दिया कि किसान की आदमी कैसे बढ़ेगी। आज अगर हम किसान को बिजली एवं पानी देने का प्रबन्ध नही करने जो तो पहले मध्यम वर्ग ऊपर उठकर आया था, वह फिर हटकर पीछे चला जाएगा और उसकी आर्थिक द ाा खराब हो जाएगी। अगर उसकी आर्थिक द ाा खराब हो गयी तो जो किसानों का भाोशण करने की स्थिति में होगे, वह उसका भाोशण कर सकते है। दिल्ली हमारे बीच में है और हरियाणा में दिल्ली साढ़े तीन तरफ से धिरा हुआ है दिल्ली भारत की राजधानी है और सन् 1985 से पहले दिल्ली को हम भारत की राजधानी कहते जरूर थे लेकिन जब कॉमर्ियल कैपिटल की बात आती थी तो बम्बई को कौमर्ियल कैपिटल माना जाता था लेकिन जब कॉर्ियल कैपिटल माना जाता था लेकिन 1985 के बाद कामर्ियल ऐक्टीविटीज भी दिल्ली की तरफ डायवर्ट हुई है। मुख्य मंत्री जी मै आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगले 10–15 सालों में दिल्ली के चारों तरफ सौ–सौ किलोमीटर तक बोने खाने की जमीने नहीं बचेंगी। इस वैल्ट के अंदर टोटली इंडस्ट्रियलाइजे ान होगा। यह इंडस्ट्रिलाइजे ान का फायदा हरियाणा के लोगों उठाते है, या

दिल्ली के लोग उठाते है या बाहर के व्यपारी या उद्योगपति उठाते है या मल्टी ने ानल्ज फर्म उठाती है। इस प्र न का फैसला जो सरकार या पार्टी पावर में है उसने लेना है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 39 हजार के करीब उद्योग घरों में लगे हुए थे उनको वहां से ि ाफ्ट करने की हिदायत हो चुकी है उसमें से कुछ को बे ाक दिल्ली सरकार कही कौम्पलैस बनाकर जमीन भी मुहैया करा दें तो भी हजारों इंडस्ट्री हरियाणा में आकर लगेंगी। अब दिल्ली सरकार के बारे में टिश्पणी करने का मेरा कोई इरादा नही है लेकिन में एक बात आपको अव य कहना चाहता हूं कि जो 39 हजार के करीब इंडस्ट्रीज दिल्ली में लगी हुई है। Most of the industries deal with plastic and most of the peole who deal with these industries are there from Haryana. खुद उन फैक्ट्री वालो के मुंह से सुनी हुई बात मै आपको बता रहा हूं वे कहते है कि अगर हम बिजली की चौरी न करें तो इस इंडस्ट्री में हमें कुछ न मिले। यानी बिजली के बारे में चर्चा के लिए तो अध्यक्ष महोदय, आप या मुख्य मंत्री जी अलाऊ करेंगे तो बिजली के बारे में मै रहस्योदघाटन करूंगा। बिजली के बारे में बहुत सी बाते है (विघ्न) दिल्ली के हरियाणा से घिरा होने की वजह से हमें अपनी सम्पूर्ण उद्योग नीति को नये सिरे से बनाना पड़ेगा। मेरा आपसे कहना है कि अगर इस औद्योगिक नीति को हम सोचकर बनायेगे तो उसके परिणाम पांच साल के बाद हमें मिलने भाुरू हो जायेगे। उसकी एक वजह है। अध्यक्ष महोदय, इण्डस्ट्री तो आयेगी ही उनका तो कोई चारा नही है। बहादुरगढ़ में पिछले 35 सालों से रोहतक तक

सड़क दोनों तरफ एक किला दस लाख रूपय में या 15–20 से कम नही मिल रहा है यह बात मैं इस लिए कह रहा हूं कि ऐसी हालत आज से एक डेढ़ साल पहले नही थी। और ऐसी स्थिति रही तो वहां से किसनों की सारी जमीन बिक जायेगी। क्योंकि जब किसी किसान की एक एकड़ जमीन 15–20 लाख रूपये में बिकेगी लालच तो होगा ही और जो उद्योगपति 5 एकड़ जमीन लेकर स्थापित करेगा तो उस उद्योग में 200 आदमियों को रोजगार मिलेगा और उन 200 आदमियों में 70–80 आदमी टैक्नोक्रेट होते है जोकि स्कील्ड वर्कर होते है। हरियाणा प्रदे ा के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नही है कि हमारे बच्चों को ऐसी ट्रेनिग दी जाए। हमारे बच्चे जो स्कूल जाते है उनको आज दसवी, प्लस टू और बी0 ए0 एम0 के सर्टिफिकेट लेने के बाद नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते आज आई0 टी0 आई0 मे भी इस लिए धक्के खा रहे है कि हमारी कंजरवेटिव अप्रोच होती है कि ट्रेक्टर मकैनिक का कोर्स कर लिया। आज इनकी जरूरत नही है आज हमारे प्रदे ा में नये कोर्स इन्ट्रोडसूस करने की जरूरत है। एम0 बी0 ए की बजाय आज बिजनेस संबंधी कम्पनी सक्रेटरी कोर्स करवाने की जरूरत है या कोई ऐसा कोर्स हो जिसमें एकाउंसटस संबंधी, इलैक्ट्रनिक्स, कम्प्यूटर संबंधी कोर्स हो। आज हमारे यहां ऐसे बहुत कम कोर्स है अगर कही है तो नाम मात्र के है। अगर कही पर इन कोर्सिज की ट्रेनिग दी जाती है और इन संस्थाओं से हमारे बच्चे ट्रेनिग करके आते है उनको इन फैक्ट्रियों तरजीह नही दी रही है। मेरा कहना यह है कि पांच एकड़ जमीन जिस भी किसान की गई और उसमैं

200 आदमियों को रोजगार मिला और उन 200 आदमियों में से उस फैक्ट्री में सिर्फ गेट खोलने वाला और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो एक्स सर्विमैन उस इलाके के होते है उनको रोजगार दिया जाता है लेकिन वहां जे स्कील्ड् वर्कर है जो दफ्तर चलाते है या म ीनरी चलाते है वे हमारे बेटे या भाई नही होते क्योंकि किसी भी सरकार ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। आज जरूरत इस बात की है कि दिल्ली के चारों तरफ 100 किलोमीटर के अंदर जो स्कूल है, कालेज है, हाई स्कूल, है प्लस टू या पौलीटैक्निक कालेज है इनमें जिन कोर्सिज की ट्रैनिंग दी जाती है उनको अनुबंध किया जाए जैसे एम0 बी0 ए0 या आई0 टी0 आई0 वगैरह में को अनुबंध किया जाता है। वहां पर जो बच्चे ट्रैनिंग करते है उनको पहले एक फैक्ट्री वाला ओफर देता है कि हम 15 हजार रूपये देंगे तो दस दिन बाद दूसरी फैक्ट्री वाला आ जाता है कि हम 18 हजार रूपया महीना देंगे ऐसे ही अनुबंध हमारे यहां पर भी होने चाहिए। पांचवे पे कमी ान ने यह बात कही है कि क्लास फोर पोस्टस को खत्म करके कौन्ट्रेक्ट बेसिस पर काम करवाया जाये। इससे तो हमारे बच्चों का और गरीब आदमी का ज्यादा भाोशण होगा। मैं मुख्य मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा कि जब ये सिविल एविये ान और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तब एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स में एक प्रथा चली थी कि वहां जो सिक्यूरिटी स्टाफ है उनको भी कंट्रैक्टच्यूल बेसिस पर नौकरी दी जाये (विघ्न)

श्री बंसी लालः यह विभाग मेरे पास नही था।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, गांवो में से एक ठेकेदार 50—100 बच्चों को पकड़ता है और उनकी ड्रेस सिलवा देता है और फैक्ट्रीयों में उनको 1200, 1400, 1600,1800, या 2000 रूपये मालिक से उनकी चार हजार रूपये मासिक के हिसाब से मासिक के हिसाब से लगवा देता है और फैक्ट्री मालिक से उनकी चार हजार रूपये मासिक से हिसाब से तनख्वाह लेता है। इस तरह से जो बाकी पैसा बचता है वह ठेकेदार अपने पास रख लेता है। यह भाोशण है। अगर हमारे बच्चे इस भाोशण का ि ाकार हो गए तो हमारी हालत भी उन राज्यों जैसी ही जाएगी जहां पर भुख है और भाोशण आज भी है। जहां आज भी फयूडल स्टाइल का कल्चर है। इस लिए अध्यक्ष महोदय, यह बात मै एक नजरिए से इसलिए कहना चाहता हूं कि जो हरियाणा के अन्दर उद्योगों का विकास होगा (विघ्न) उसमें दो तीन इंस्टीटयू ान बहुत महत्वपूर्ण है। एक फिकी, एक चैबर ऑफ कामर्स और एक सी0 आई0 आई0। ये तीनों जो उद्योग की आर्गेनाइजे ान है इसमे सम्पर्क स्थापित करके इनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि आने वाले 5, 7, 10 सालो में वे प्रौजैक ान दे कि फलां ट्रेड में उनको इतने आदमी चाहेंगे, उस सैक्टर में इतने चाहेंगे और फलां सैक्टर में इतने चाहेंगे। ऐसी उनको ऑफर दी जानी चाहिये। अपने एक्सपर्ट भी बनाने के लिए उनको खुद ही इंसट्रक्टर भी भेजने चाहिए और उन बच्चों को बाद में वे नौकरी दे। यह सब एक एग्रीमैंट के द्वारा होना

चाहिए ताकि हमारे बच्चों को धक्के न खाने पड़े तथा दौड़ न लगानी पड़े। हरियाणा में तो जैसे एक प्रथा चल गई है तथा यह सोच नौकरियों में होने लग गई है। इसलिए इससे भी आजादी मिल जाएगी। आज हरियाणा में यह हालत है कि एक एक गांव में सौ दो सौ लड़के कुंवारे बैठे है, कोई लड़की वाला रि ते लेकर के नहीं आता है। आएगा हम आगरा कैनाल को खुद चलाएं मेरा मतलब यह है कि अगर हम अपनी कैनाल बनाकर चलाएं, गुड़गांव कैनाल को बढ़ाए और मेवात कैनाल जिसके लिए 200 करोड़ रूपये को नौवी पंचवर्शीय योजना में प्रावधान किया गया है, उसको स्पीड–अप करें तो अच्छा रहेगा। बड़ा दुख होता है कि यह बात सदन के अंदर कई बार कही जा चुकी है। मै बताना चाहता हूं कि गुड़गांव के अंदर 10–15 मंजिली बिल्डिंगों के लिए रोहतक के गांवो को चीरती हुई नहर आ सकती है लेकिन मेवात के अंदर का पानी आगे बढ़कर नही जा सकता है क्योंकि पानी नही है और उनके लिए पानी की सुविधा नही है। मै चाहता हूं कि इस दृश्टि से कि किसानों की आमदनी बढ़े, एग्रीकल्चर सैक्टर में हमारी पूरी हिस्सेदारी हो, इसके लिए हमारे बच्चों क अंगूठे से ही म ाीन का स्विच दबे तो कल्याण होगा। यह पूने या हैदारबाद में रहने वालो के हाथों में दबेगा तो इसमें हमारा कोई हिस्सा नही है। इसलिए सरकार को औद्योगिक नीति को, कृशि नीति को व वाटर मैनेजमैंट की नीति को बदलने के लिए आज ि ाक्षा की नीति को बदलना पड़ेगा। ि ाक्षा के नए आयाम कायम करने पड़ेगे ताकि हम अपने बच्चों को इस दि ाा में बढ़ते हुए देख सके और वे भी इस तरह

ही हिस्सेदारी कर सके। मेरे को कई लोग कहते है कि यह जात–पात की बात है। यह जात–पात की बात नही है। मै कहना चाहता हूं कि हरियाणा में 22000–26000 कांस्टेबल है इसमें सारे हरियाणा में आप देखे कि कहीं पर भी चैन नही मिलेगा। अगर कहीं पर मिलेगा तो मै राजनीति छोड़ दूंगा। यह एक कल्चर डिवैल्प हो गई है। स्पीकर साहब, हमारे बच्चो तो सिर्फ कांस्टेबल या सिपाही बनें, वे बर्फ की चोटी पर खड़े रहे। इस प्रथा को बदलने के लिए और समाज के अंदर परिवर्तन लाने के लिए यह बात जरूरी है कि आगरा कैनाल को नियंत्रण लेने का जो मुद्दा अपने माननीय साथियों ने रखा है वह सराहनीय है। (विघ्न) मै यह किसान पूरी तरह से आ वस्त हो जाएं कि उनको इंसाफ मिलेगा तथा उनको कोई तकलीफ नही होगी। धन्यवाद।

श्री राम पाल माजरा (पाई): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदे ा की पानी की समस्या पानी के डिसप्यूट इन्टर स्टेटस हे उसी में से आगरा कैनाल का कंट्रोल भी एक डिसप्यूट है। जहां यमुना जल समझौता एक डिसप्यूट है तो वहीं एस0 वाई0 एल0 कैनाल का भी एक डिसप्यूट है। इन सभी डिसप्यूटस के बारे में हरियाणा प्रदे ा की सरकार चिन्तित भी है। पहले की सरकारों के जिस प्रकार के दस्तावेज हमारे सामने आएं है उनमें ऐसा लगता है कि वे सरकारों भी इन डिसप्यूटस के बारे में चिन्तित रही है। आगरा केनाल 150 वर्श पुरानी कैनाल है तब से इसका कंट्रोल यू0 पी0 सरकार के पास है। अनेकों प्रकार के सेक्रेटरीज की मीटिंग्ज

हुई और मुख्यमत्रियों मीटिंग्ज हुई लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि इस बारे में कोई निर्णय नही हो सका कोई फैसला उस जगह पर नही आ सका। आगरा कैनाल के बारे में किसानों की बहुत सी समस्याएं है क्योंकि हरियाणा प्रदे ा के किसानों को अनेकों प्रकार के मुकद्मों के लिए यू0 पी0 में जाना पड़ता है। उनके आगरा और मथुरा में जे0 ई0 एक्सीयन और एस0 डी0 ओ0 बैठते है इसलिए किसानों को वहां पर आने जाने में बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वहां पर उस एरिया के किसानों का कोई भाईचारा या रि तेदार नही रहता जिसके पास वे उनके पास रूक जाएं कयोंकि उनको वहां पर एक दो दिन के लिए रूकना भी पड़ता है। जहां तक उस नहर के पानी की मात्रा का सवाल है जिस चैनल में 150 क्सूसिक पानी छोड़ना चाहिए चूंकि मैनेमैंट उनके हाथ में है जिसकी वजह से वे 20–25 क्यूसिक पानी छोड़कर कह देते है कि उन्होंने पूरा पानी छोड़ दिया। इसलिए उसका कट्रोल हरियाणा प्रदे ा की सरकारें अपने हाथ में लेने के बारे में उस एरिया के किसानों की नहर का एडमिनिसट्रेटिव कंट्रोल हरियाणा सरकार के हाथ में लेने के बारे मे उस एरिया के किसानों की एक आवाज है एक जरूरत है। आगरा कैनाल का पानी बढ़ गया। पहले आगरा कैनाल में जो पानी आता था वह इसलिए बढ़ गया गया क्योंकि फरीदाबाद और दिल्ली भाहरों का सीवरेज का पानी उसमें आता है और कंग नहर का पानी भी उसमें मिल जाता है जिसका वहज से उसका पानी बढ़ गया है पहले हमारा हिस्सा 20 प्रति ात था। हमारी सरकार

को चाहिए कि पानी बढ़ाने के बारे में हमारी सरकार अपनी तरफ से इस केस को यू0 पी0 सरकार के साथ एक समन्वय स्थापित करके केस प्लीड करें और अपने हिस्से को बढ़वाने के यत्न करें ताकि हरियाणा प्रदे ा किसानों की तरक्की हो सके और उनको पूरा पानी मिल सके। किसानों को उसका फायदा हो सके। जहां तक नहरों की डीसिल्टिंग की सवाल है। नहरो की डीसिल्टिंग के बारे में हमारे साथी हर्श कुमार जी ने कहा और हमारे साथी जगदी ा नायर जी ने भी खु ी मनाई कि उनकी डीसिल्टिंग हुई है। हमें भी इस बात की खु ी हुई है कि इनके चैनेल्ज की सफाई तो हो गई क्योंकि नहरों की डीसिल्टिग के लिए 40 लाख रूपये मंजूर किएह गए थे। उन्होंने इसका ब्यौरा भी दे दिया और कह दिया कि पानी टेल तक पहुंचना भाुरू हो गया है। लेकिन मै कहता हूं कि हरियाणा प्रदे ा की हर टेल तक पानी पहुचाने के लिए उनको डीसिल्टिंग की जरूरत है। नहरों कि डीसिल्टिंग के बारे में अनेकों प्रकार के एस्टिमेंट बनाए जाते है और ठेकेदार उन एस्टिमेटस के टैंडर ले लेते है जिसकी बिना पर नहरो की डीसिल्टिंग की जाती है। उनके फर्जी बिल बना दिए जाते है और पेमेंट ले ली जाती है। यह बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है कि हर ठेकेदार को एस0 डी0 ओ0 एक्सीयन, और जे0 ई0 यहा तक कि ऊपर तक तीन परसैंट कमी ान तो देना ही पड़ता है चाहे कोई कितना ही ईमानदार ठेकेदार क्यों न हो फिर भी उनको कमि ान तो देना ही पड़ेगा। अगर हरियाणा सरकार अपने प्रदे ा में हर नहर की डीसिल्टिंग करवाना चाहती है तो सिंचाई विभाग

के पूरे एडमिनिस्ट्रे ान को पुनः ओवरहाल करना पड़ेगा और उनकी पुरानी आदत है मै यह नही कहता कि उनकी यह आज की आदत है मैं कहता हूं कि यह उनकी पुरानी आदत इसलिए इस विभाग का ओवरहाल करना चाहिए ताकि ठेकेदारों को उस से छुटकारा मिल सके। नहरों की सफाई हो सके और पानी टेल तक पहुंच सके। आज के लीडर ऑफ दि हाउस भी भीमगोड़ा से नहर लाने की बात कहा करते थे लेकिन आज भीमगोड़ से नहर लाने की बात का जिक्र नही हो रहा है। वह नहर जरूरी है। यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, और करनाल जिलों का वाटर लैक्स बहुत नीचे चला गया है। दादूपुर नहर के बारे में हाउस के अदंर बार बार जिक्र होता रहा है। दादूपुर नहर 1987 में मजूंर हुई थी और उसके लिए 180 एकड़ जमीन भी एक्वायर की जा चुकी थी। दादुपुर नहर बनाने के लिए उस समय केवल 13 करोड़ रूपये खर्च होने आज इस नहर को बनाना है तो उस पर आज 70 करोड़ रूपये खर्च होगे। मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां पर आगरा कैनाल हरियाणा प्रदे ा की लाइन लाइन है तो वहां पर दादुपुर नहर कुरूक्षेत्र, यमुनानगर और करनाल जिलों के लिए बहुत जरूरी है। मै इस रैजोल्यू ान का समर्थन करता हूं और इतना ही कहूंगा कि हरियाणा प्रदे ा कर सरकार को दिलेरी के साथ, मुख्य मंत्री जी पहले भी ब्यान देते रहै और अपनी जनसभाओं में भी कहते रहते थे कि हरियाणा के साथ अन्याय हुआ है। पहली सरकार ने कुर्सी से चिपके रहने के लिए यह सौदा किया है। हमारा उस समझौते से पहले 70 प्रति ात पानी जो बनता था, वह नही मिल रहा। अध्यक्ष महोदय,

हरियाणा प्रदे ा का, इसी प्रकार से एस0 वाई0 एल0 का प्र न है, हरियाणा प्रदे ा की बहबूदी और किसनों की तरक्की से बंधा हुआ प्र न है, हरियाणा की यह एक लाइफ लाईन है और हम किसानों आर्थिक उन्नति का ढिढौरा पीटते है जबकि हर तरफ से किसान का कुएं मे जाकर पट्टा चढ़ाना होता है तो वही पर ढेर हो जाता है। हमारे इलाके मैं 150 फुट पर जाकर वाटर लैवल है और किसान कुएं के अन्दर ही रह जाता है और किसान का नौजवान अैटा जब कुएं में पट्टा चढ़ाने चढ़ाने के लिए जाता है तो आप ऊपर खड़ा हो रहता है और इंतजार करता रहता है कि बेटा वापस आएगा लेकिन वह वापिस नही आता। मै चोधरी बंसी लाल जी से कहूंगा कि हमारे इलाके में यह बहुत बड़ी समस्या है। आप इसकी तरफ ध्यान देह। जब आगुन्टे ान कैनाल बनाई गई थी तो उस वक्त एम0 आई0 टी0 सी0 ने काफी टयूबवैज आगुमन्टे ा कैनाल के लिए लगाए थे जिस कारण वाटर लैवल चीचे चला गया। वह पानी भिवानी चला गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि खेती करते हुए मरने वाले किसानों को मुवाअजा दिया जाना चाहिए क्योंकि जिसका नौजवान बेटा इस दे ा के लिए आजान पैदा करते कुएं में ही रह जाता है। अध्यक्ष महोदय, गांवों में कई बार लाईन मेंन नहीं होता, इलैक्ट्रीि ायन नहीं होता, कई बार किसान बिजली का तार लगने से मर जाता है क्योंकि उससे उसको करंट लग जाता है और वह वहीं पर ढेर हो जाता है। मै चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार का प्रोविजन बनाएं कि किसान इन परिस्थितियों में मरे तो जरूर मुआवजा दिया जाना चाहिए। मै

इस सरकार का इस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहुत से किसानों का पानी की समस्या इसलिए भी है कि हरियाणा प्रदे ा में वाटर लैबल नीचे चला गया है और बहुत सी जगहों पर पानी खारा है। इस नहरी पानी की इसलिए भी आव यकता है कि ताकि वाटर लैवल ऊपर आ सके और खारे पानी के साथ इसको मिलाकर कुछ खेती की जा सके। धन्यवाद।

श्री करतार सिंह भडाना (संभालख): अध्यक्ष महोदय, आज हमारे हरियाणा में जो नहर का कार्य मुख्यमंत्री जी ने किया है, कैनाल के पानी की जो हमको सहुलियत दी है उसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर हमारे किसान कई बार ट्रैक्टर से नहर से पानी ले लेते है यानि पानी उठा लिया जाता है तो उन पर केस बना दिया जाता है। मै आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अर्ज करता हूं कि उन पर केस न बनाएं जायें। दूसरे जहां तक अभी मेरे सीनियर सांसद और जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके है उन्होंने कई सवाल किए क्योंकि यहां पर राजनीतिक बातें बहुत हो जाती हैं लेंकिन आज सबसे बड़ा समस्या है उसकी तरफ कोई भी ख्याल नहीं करता। पानी हम सबको देना चाहते है। यह जरूरी भी है। हरेक का पानी दिया जाना चाहिए, यह जरूरी है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपना त्याग कोई भी नहीं कर पाते। अभी उन्होंने कहा आज तो सबसे बड़ी कोई नेता हो, उसको ले लें वह गरीबों का साथ देता है क्योंकि हमारे दे ा, प्रदे ा और भाहर में गरीबों की संख्या ज्यादा है। मै आपसे यह कहना चाहूंगा

कि कम से कम हरियाणा में इस चीज को हटा दें क्योंकि अगर रईस और उंचे लोग ज्यादा होंगे तो यहां पर यह कहने वाले नेता कम मिलेंगे कि गरीबों का साथ जाये। गरीबी की रेखा से सब ऊपर होना चाहते हैं लेकिन आज हमारे सामने बड़ी दिक्कत है, वह कहते है कि रईस भी उसी पानी को पीता है और गरीब भी उसी पानी को पीकर जिन्दा रहता है, अगर रईस पानी के बिना जिन्दा रह सकता है तो क्या रईस को पानी नहीं दिया जाएगा? यह कहा गया कि गुड़गांव की बड़ी–बड़ी बिल्डिंगज को पानी दिया जाता है। मै यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि पीने का पानी तो सभी का आव यक है ही और सबको बराबर पीने के पानी की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो बहुत बड़े सीनियर नेता है वे कहते हैं कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए एक तरफ तो वे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे है दूसरी तरफ बंटवारे की बात करते है। वे कांग्रेस का समर्थन करते है लेकिन इस प्रकार वे कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहे है, अगर वे ऐसा चाहते हैं तो उन्हे बी0 जे0 पी0 को स्पोर्ट करना चाहिए जो कि वे नहीं करेगे। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से कह कहना चाहूंगा कि ऐरियावाईज बात को छोड़कर और पार्टीवाईज बातों को भुलाकर सभी साथियों को सरकार द्वारा जो विकास और लोगों के भलाई के कार्य किए जा रहे हैं उनका समर्थन करना चाहिए। मैं अपने ओपजी ान के भाईयों आपके माध्यम से निवेदन कंरूगा कि वे भी अपनी राजनीति चमकने के लिए लोगों की भावनाओं के खिलाफ कोई काम न करें। राजनीतिक बातों को छोड़कर राज्य के भले और विकास की

बातों का समर्थन करें। इन भाब्दौं के साथ मैं अध्यक्ष महोदय, का धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री कैला ा चन्द्र भार्मा (नारनौल): अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में इस विशय पर काफी चर्चा हुई है कि आगरा नहर का कंट्रोल हरियाणा सरकार अपने नियन्त्रण में ले ले। मुझे ऐसा लगता है कि सारा सदन ही इस पक्ष में है और यह प्रस्ताव सर्वसम्सति के पास होने जा रहा है इसके लिए सारा सदन धन्यवाद का पात्र है। बोलते हुए श्री बीरेन्द्र सिंह जी बता रहे थे कि सोनीपत, पानीपत, और सारे मेवात एरिया का भी जिक्र किया है कि यह बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है यहां नहरें जरूरी है। परन्तु जिला महेन्द्रगढ़ जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है और एक फैसला है के लिए भी सभी साथी सोंचे। स्पीकर साहब, आपके जरिए माननीय मुख्यामंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जिला महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी की तरफ थोड़ा इन नहरों को मोड़ दिया जाये तो हमारे किसान का भी गुजारा हो सकता है इसलिए इधर ज्यादा ध्यान रखें। मुझे इस बात की खु ाी है कि महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी जिले ऐसे जिले हैं जहां से भारत वर्श में परसैंटेज के हिसाब से सब से ज्यादा लोग दे ा सवा करते है। यहां के लोगों का सबसे ज्यादा परसैटेज मिलेट्री में है लेकिन फिर भी यह इलाका पिछड़ा हुआ है। महेन्द्रगढ़ औ रिवाड़ी की जल दर सबसे नीचे है। यहां पर 150 और 200 फुट नीचे से बिजली की मोटरों से पानी खींचा जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से

मेरा आग्रह है कि दोहान और कृश्णवती दो नदियां राजस्थान से आती है। उनके अन्दर अगर सिर्फ एक एक किलोमीटर पर सिर्फ 5–5 फुट थोड़ी दीवार बांध के लिए खड़ी कर दी जाए जैसे कि राजस्थान के इलाके में है। एक एक मीटर के फासले पर इस प्रकार से छोटे छोटे बांध बन जाएंगे और जब भी वर्शा आएगी तो इनमें पानी इक्ट्ठा हो जाएगा और जल स्तर ऊॅचा हो जाएगा। इस प्रकार से इन नदियों पर 15–15 या 20–20 बांध बन जाएगे जिनसे साथ लगते गांवों को फायदा हो सकता है। हमीदपुर बांध के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई थी और उसको भरने की योजना थी लेकिन ई वर की कृपा से वर्शा हुई और वह बांध पानी से भर गया। जिससे उसके नजदीक लगते 15–20 गांवों का फायदा हो गया है क्योंकि 20–20 फुट ऊपर आ गया है। जिससे कुछ गांवों का फायदा भी हुआ है। आजकल महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी में पानी का लैवल बहुत नीचे चला गया है। सरकार से मेंरी प्रार्थना है कि दोहन और कृश्णावती नदियों पर छोटे–छोटे बांध बनाएं जाएं उसके लिए सिर्फ 5–5 फुट की दीवार खड़ी करने की जरूरत है। वर्शा आने से इन बांधों में पानी इकट्ठा हो जाएगा और इसके नजदीक लगते 300–400 गांवो का वाटर लैवल ऊंचा आने से दोनो नदियों के आसपास बसे गांवों को फायदा होगा।

इसी तरह से आगरा नहर को हरियाणा सरकार अपने प्र ाासनिक नियन्त्रण में ले तो यह बहुत अच्छी बात है। ऐसा होने

से यह पता रहेगा कि इसमें कितना पानी आता है कितना पानी आगे जाता है इस बारे में सारी रिपोर्ट ठीक मिलेगी। अगर यह नियन्त्रण किसी और के हाथ में होगा तो हमें ठीक रिपोर्ट नही मिल सकती है। मे यह चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को सारे सदन को सर्वसम्मति से पास करना चाहिए।

इस तरह से अभी पानी का हिस्सा बढ़ाने की बात आई थी इसके भी यही बात लागू होती है। यह प्रस्ताव भी सारा सदन एक मत पास करे। धन्यवाद।

श्री अ ाोक कुमार (थानेसर): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में आगरा कैनाल के कंट्रोल को अपने हाथ में लेने की बात चल रही है इसका जो प्रस्ताव आया है यह ठीक है। पानी न मिलने की वजह से किसानों को बहुत दिक्कत होती है। इस प्रस्ताव का करते है। इसी साथ मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब आप हमारे यहां चुनावी जलसे में आए थे तो आपने वहां पर एक लम्बा चौड़ा भाशण दिया था कि आप कुरूक्षेत्र में दादुपुर नलवी नहर बनाने का प्रयन की बहुत जरूरत है। यह बनाने से कुरूक्षेत्र के लोगों को पानी मिल जाएगा और वहां का वाटर लैवल भी ऊॅचा हो जाएगा। जब आप पहले मुख्यमंत्री थे तो आपने नरवाना ब्राचा में बड़े–बड़े ट्यूबवैल्ज लगाकर इस प्रान्त में पानी देने का काम किया था आज याहं पर औहदियां 70–70 फुट नीचे गई है और बरसातों में इसमें गैस बन जाने से लोगों की मौत होती है। मेरा यह कहना है कि यह जो एम0 आई0 टी0 सी0

के ट्यूबवैल्ज लगाए है इनको बंद किया जाए। बीरेन्द्र सिह जी ने कहा था कि पहले इस क्षेत्र में रि ते जल समझौता किया और हरियाणा के हिस्से का पानी करे। (विघ्न) स्पीकर सर, एस0 वाई0 एल0 का जिक्र करना जरूरी है अैर हरियाणा प्रदे ा के लोगों की जरूरत है। इसका बनना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुरूक्षेत्र के छोटे किसानों की 52 एकड़ जमीन एस0 वाई0 एल0 की एक प्रयोग ााल बनना के ली थी। उस समय यह कहकर ली गई थी कि वहां पर एक प्रयोग ााला बनेगी आज उस जमीन के लिए हुए लगभग बीस बाईस साल हो गये परन्तु वह जमीन उसी तरह से बेकार पड़ी हुई है इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि रावगढ़ गांव के किसानों की वह जमीन दिलायी जाए। सर, उस गांव में अरबाड़ी जाति के लोग है और उसके पास एक किल्ला ही जमीन थी लेकिन जब उनसे वह जमीन ले ली गई तो वह आज रिक ाा चलाकर अपना गुजारा कर रहे है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि अगर उन्होंने वहां पर कोई प्रयोग ााला नही बनानी है तो वह जमीन किसानों की वापिस कर देनी चाहिए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मै डीप ट्यूबवैल्ज के बारे में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि या तो सरकार इनको बंद कर दे और अगर सरकार उनको बंद नहीं कर सकती तो जो नहरी पानी के रेट दूसरों लोगों से लिए जाते हैं उसी रेट कुरूक्षेत्र के लोगों को भी इनका पानी मिलना चाहिए। धन्यवाद।

श्री धीरपाल सिंह (बादली): अध्यक्ष महोदय, आज तो हाऊस के सम्मानित साथियों ने यह प्रस्ताव हाउस के सामने रखा है मै भी उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, यह समय की मांग भी है जैसा चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि कई लोग आए और आकर उस इलाके के लोगों की भावनाओं के साथ भाोशण करते हुए चले गए। फरीदाबाद और गुड़गांव क इलाकों में चुनावों से पहले आगरा कैनाल के मुद्दे का बार बार के ा किया गया। आज जो चौधरी बंसी लाल की वर्तमान में सरकार है इन्होंने भी दूसरे लोगों ने भी मुद्दे को कै ा किया। हर्श जी ने जो यह प्रस्ताव आज यहां पर रखाहै तो यह कैनाल एक विधायक या इलाके की भावना नही बल्कि इससे सारा प्रदे ा भी जुड़ा हुआ है क्योंकि पिछले काफी दिनों से आगरा कैनाल की वजह से वह इलाका पीड़ित रहा है वहां के किसान के छोटी–छोटी समस्याओं के लिए उतर प्रदे ा में मथुरा या आगरा में ऐक्सियन या एस0 इज0 के पास दो दो सौ किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। स्पीकर सर, आज भी यह सदेह है जैसा कि अखबारों में इरीगे ान सैक्रैटरी की तरफ से टिश्पणी हुई थी कि हमने बुलन्दबाग फैसला अपने पक्ष में फैसला कर लिया है। सर, अगर वाकई फैसला अपने पक्ष में हो गया है तो यह बहुत अच्छी बात है लेकिन संदेह यह कि हम आज भी मामले में सक्षम नही है। न केवल कंट्रोल की बात बल्कि और भी कई ऐसे मुद्दे है जैसे उस इलाके के किसानों के साथ आबियाने को लेकर भी वेदभाव है। आज जो पूरे प्रदे ा में आबियाना लिया जा रहा है

ठीक उसे विपरीत वहां के किसानों से जो कि आगरा कैनाल से अपना इलाका सिंचित करते है से काफी ज्यादा आबियाना लिया जाता है। आज जो सता पक्ष बैठे हुए लोग हैं और उन्होंने इस बारे में जो आकड़े हाउस सामने रखे थे, वह आंकड़े आज द ार्ा रहे है कि कितना ज्यादा आबियाना वहां के किसानों को बर्दास्त करना पड़ता है। स्पीकर सर, केवल आबियाने में ही भेदभाव की बात नहीं है बाल्कि बाराबंदी की बात है या पानी के ड्रिस्ट्रीब्यू ान की बात है तो अगर एक–एक मुद्दो को देखा जाए तो वह किसान अपने आप को लाचार सा समझा रहा है लेकिन वहां पर किसानों की भावनाओं को समय पर कै ा किया जाता रहा है। उस भावना की कीमती ओट मे इस तरह की बात की जाती है। लेकिन इससे आगे कभी बात नही की गयी इसलिए आज जो यह प्रस्ताव हाउस में आया है उससे सारा हाउस सहमत है और उन इलाकों के किसानों के साथ, उनके अधिकारों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। जहां पर प्रदे ा के हित, किसान के हित और गरीब के हित का मुद्दा आएगा वहां पर होगा वहां कोई पार्टिया नहीं होगी। वहां सभी विधायक और सभी पार्टिया उस किसान के प्रति, गरीब के प्रति अपने आप का उतना ही सहयोगी मानती है जितना दूसरे लोग सहयोगी मानते है। आज फिर मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे को गम्भीरता से उठाया जाये। चाहे उतर प्रदे ा की आजादी ज्यादा हो, वहां सांसदों या विधायकों की सख्या ज्यादा हो लेकिन फिर भी हमारा प्रदे ा कमजोर नही है, यहां का किसान कमजोर नहीं है, वहां की

राजनीति में जो लोग हैं वे कमजोर नही है, और अपने आप को कमजोर नही मानते हैं फिर भी हमारे साथ की अनहोनी बात की जा रही है, यह घाटे का काम किया जा रहा है हमारे वहां के लोगों व किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उनकी खेती को उजाड़ने का काम किया जा रहा है इसमें वर्तमान, भुतकाल और भविश्य सभी इसके लिए दोशी बनते है। इसी प्रकार इस बात से जुड़ती हुई वहां डीसिल्टिंग की बात है भाई हर्शकुमार जी ने इस बात की वकालत की है लोकतंत्र में सीमाएं भी है, मजबूरियां भी है। अभी हमें कंट्रोल मिला नहीं और उस कंट्रोल के लिए हम मुख्य मंत्री जी के साथ है। हमारी पार्टी इनके साथ है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि वहां डीसिल्टिंग कैसे हो गई। डीसिल्टिंग का अधिकार हमें नहीं है। हम चाहते है कि डीसिल्टिंग का अधिकार हमें मिलें, वाराबंदी का अधिकार हमें हो। पानी का कंट्रोल हमारे पास हो, नहर के रख–रखाव का कंट्रोल हमारे पास हो। जैसा अभी बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि इस पर कितनी लागत आती है। आज विशय लागत का नहीं है आज विशय नैतिकता का है आप पैसे के अभाव को कहीं और दूर कर लीजिए। प्रदे ा के लेवल पर या सरकार के लेवल पर इस समझौते में कोई रूकवाट आती है या उतर प्रदे ा की सरकार का पक्ष केन्द्र सरकार रखती है तो आपका यह दायित्व बनता है कि आप उसके साथ–साथ अलग कैनाल बनाकर उस इलाके को जो महरूम रह गया है, वंचित रह गया है उस इलाके को पानी दीजिए और यह उनका हक बनता है। इसी तरह में से

और इलाके भी है। मसानी बैराज पर चर्चा होती रही। हवां राजस्थान मे भारतीय जनता पार्टी का राज है। अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे सामने परे ानिया आई है। राजस्थान में साहिबी, दोहान और कृश्णवती यह जो नदियों बरसात के समय में वहां से आती थी तो उनके साथ वहां की फर्टाइल मिट्टी भी आती थी और पानी भी फर्टाईल आता था और अब राजस्थान सरकार ने उन जगह पर जगह छोटे छोटे बांध बनाये हुए है। आज चौधरी भजन लाल जो बैठे हुए नही है जब सता में थे तब आपकी ओर हमारी पार्टी उन पर इस काम के लिए दवाब डालती थी लेकिन उन्होंने भी इसे अनदेखा किया। इस बारे में प्रयास किया गया होता तो परिणाम अव य हमारे पक्ष में आते। अब अगर साहिबी में ज्यादा पानी आता है तो दिल्ली तक तबाही झेलनी पड़ती है अगर पानी मात्रा कम रह जाती है तो पानी राजस्थान के इलाके में ही रह जाता है। आज मुख्य मंत्री जी के सामने यह भी प्र न है। छोटे–छोटे बांध बने हुए है और उनकी वजह से इलाका खु ाक रह गया है वहां पर भी पानी का स्तर नीचे जा रहा है। यह जो महेन्द्रगढ़, नारनौल और रिवाड़ी का इलाका है वहां पर भी पानी का स्तर नीचे चला गया है। वह बहुत सोचने का विशय है। इसी तरह पानी का स्तर चीने चला गया तो पीने का पानी की वहां पर कठिनाई पैदा हो सकती है। और पता नहीं कि जमीन सिंचित हो पाएगी या नहीं। इस पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए यह आव यक हो गया है कि हम राजस्थान सरकार से यह मामला उठायें कि जो उनके छोटे छोटे बांध बने

हुए है पानी को रोकने के लिए और जो बरसाती पानी हमारे यहां आता है उसके बारे मे कुछ कदम उठाए जाएं ताकि यह जो पानी का स्तर गिरता जा रहा है उस समस्या का हल निकाला जा सके। मै मुख्य मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करूंगा कि वे इसमें व्यक्तिगत रूचि लें और पानी को यहां पर लाने का प्रयास करें ताकि किसानों को पानी की सुविधा प्रदान की जाये। इसके साथ में मेवात क्षेत्र के बारे में बात कहना चाहूंगा। मेवात क्षेत्र में जो कोटला झील है उस झील में बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है और जब पानी की जरूरत होती है तो उसमें से किसानों को पानी दिया जाता है आज उस झील की हालत खस्ता हो गई है। वह कभी भी टूट सकती है और ओवरफ्लो होकर किसानों का भारी नुकसान कर सकती है। क्योंकि जो पानी बरसात में कोटला झील इकट्ठा किया जाता है वह मौसम ठीक होने के बाद खालों में छोड़ दिया जाता है उसको इस हिसाब से बनाया जाये ताकि जरूरत पड़ने पर यह पानी किसानों को दिया जा सके। चाहे पम्प लगाकर ऐसा किया जाये।

श्री बंसीलालः इस बार हमने इस पानी को इरीगे ान के लिए इस्तेमाल किया है।

श्री धीरपाल सिंहः अगर इरीगे ान के लिए इस्तेमाल किया है तो अच्छी बात है लेकिन यह पानी अभी भी छोडा गया है (विघ्न)।

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से अपने साथी को बताना चाहूंगा कि उजीणा और गोच्छी में पहली दफा हरियाणा के इतिहास में हमारे मुख्य मंत्री जी के आदे ाों से हथीन के पास आप स्वयं जाकर देख सकते हैं कि 14 बान्धों को दोनों नालों पर बनाया गया है। (विघ्न)

श्री धीर पाल सिंहः क्या इस पानी को रोककर बनाया गया है? (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलालः पहली दफा इस नाले का पानी खेती में सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। इसके अलावा स्पीकर सर जो सबसे ज्यादा इस इलाके के लोगों की फायदा हुआ है वह यह है कि धरती के पानी का जल स्तर 5–6 फीट ऊपर आ गया है।

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर सर, अगर चौधरी बंसी लाल जी ने उजीणा डैम से सिंचाई के लिए पानी रोककर किसानों को यह सुविधा दी है तो यह एक अच्छी बात है। मैं एक दूसरे विशय के बारे मं बताना चाहता हूं कि वह यह है कि कोटला झील में से एक नहर बनाकर पानी किसानों को दिया जाये क्योकि आज डीजल मंहगा हो गया है बिजली की कमी है, बिजली न आने पर किसानों को बड़ी परे ाानी होती है।

श्री बंसी लालः आगे हम दोनों काम ले लेंगे, ड्रेन आउट करने का और आबपासी के पानी को लेने के लिए भी। अब की बार केवल बांध लगाये है आगे से दोनों को कर लेंगे।

श्री धीर पाल सिंहः हम चाहते है कि आगरा कैनाल का नियन्त्रण हरियाणा के पास हो। वाकई अगर मुख्य मंत्री जी वहां पर गये होगे और चौधरी कर्ण सिंह जी बड़े योग्य है। हमने उनकी योग्यता पर कोई प्र न चिन्ह नही लगया हैं। लेकिन पानी के मामले में हम अव य कहेंगे कि आगरा कैलान में जो पानी छोड़ा जा रहा है वह पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त नही है लेकिन मजबूरी की वजह से भाायद किसान उस पानी का प्रयोग करते होंगे। मरता हुआ किसान क्या नहीं करेगा। लेकिन अगर वही पानी कही पीने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा तो उस इलाके के लिए इससे बहुत दुखदायी बात कोई और नहीं हो सकती है। मेरा भी कई बार वास्ता हुआ है। मै भी वहां पर गोवर्धन जी की परिक्रमा करने गया था। (विघ्न) मै पानी की चर्चा पर ही बोल रहा हूं। (विघ्न)

ि ाक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): स्पीकर सर, परिक्रमा करना भी कोई बुरी बात नही है। अच्छी बात है, ये चैन पाएंगे। (हंसी)

श्री धीर पाल सिंहः मै भगवान में वि वास रखता हूं मालिक की इच्छा के बगैर कुछ भी नही होता है। (विघ्न) जैसा

मालिक चाहता है वैसा ही होता है। अध्यक्ष महोदय, मै कहना चाहता हूं कि उस पानी में जो गंद आ गई, वह या तो नजफगढ़ नाले की है या सारी दिल्ली की है। आज जो मैं एकऊरेसी के आधार पर नही कह सकता लेकिन मैने 15–20 दिन पहले अखबार में एक पढ़ी थी जिसको मैं मुख्य मंत्री जी के नोटिस में भी लाना चाहता हूं। डबल्यू जे0 सी0 कैनाल जो यमुनानगर, जगाधरी के आपपास से निकालती हे, उसमें तेजाबी पानी डाला जाता है। उसके बारे में स्पीकर साहब, चौंकने वाले तथ्य सामने आए हैं। करनाल की रिसर्च डेयरी के अंदर उस इलाके के किसानों की दूध की जांच की गई तो उस दूध में बी0 एच0 सी0 और एल्ड्रिन और दूसरे इतने घातक तत्व पाए गए कि दूध का पानी भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया। अगर इस तरह की चीजें उन नालों में या नहरों में डाली जाती है तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। यह तो एक छोटा सा परीक्षण ही हुआ है।

श्री बंसी लालः इसी 31 मार्च तक इन समस्याओं का समाधान यमुना एक ान प्लान में हो जाएगा। बाकी जो रह जाएंगी, उनको आगे कर देंगे।

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै कहना चाहता हूं कि एन0 डी0 आर0 आई0 करनाल में केन्द्र ने यह परीक्षण किया और दूध भी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया। मेरी मुख्य मंत्री जी से गुजारि ा है कि इन नहरों अथवा नालों में गन्दा पानी डाला जा रहा है कारखानों में ट्रीटमैंट प्लांट्स

जानबुझ कर नहीं लगाए हुए है तथा इस प्रकार से पैसा बचाने के उद्दे य से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे है। ऐसे व्यक्तियों को बख्भाा नही जाना चाहिए। इसी तरह से आगरा कैनाल व गुड़गांव कैनाल भी बनी हुई है और इनको भी अगर देखा जाए तो वह भी अपने आप में एक मजाक है। वह नहर केवल नाममात्र की एक नहर है। स्पीकर साहब, वहां पर जब एस्टीमैट्स कमेटी गई तो उसने रिपोर्ट दी कि उसमें तीन चौथाई से ज्यादा गाद भरी हुई है, वह किसी ने नहीं निकाती है जो कि निकाली जानी चाहिए थी। स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि पीछे जो हुआ सो हुआ, लेकिन वर्तमान में जिम्मेवारी आपकी सरकार की बनती है और आगरा कैनाल में जो तीन चौथाई से भी ज्यादा गदा भरी हुई है, वह केवल नाम की नहर दिखाई देती है, आज मेवात के लोगों की मांग है तथा मेवात के खेतों की आव यकता है कि उस नहर की गाद निकलवाकर के उस इलाके को पूरा पानी पहुंचाया जाए। इसलिए यह जो प्रस्ताव लाया गया है मै एक बार फिर इसका समर्थन करते हुए यह चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, हरियाणा की जनता की आव यकताओं से संबंधित जो भी मुद्दे है, उनको उतर प्रदे ा की सरकार वहां के सांसदों या वहां के विधायकों के साथ प्र ाासन किसी भी बात में कही कमजोर नही है। इसलिए अपने हक को लेने के लिए, अपने दावे को मजबूत बनाने के लिए, अपना पक्ष रखे और पानी का फैसला कराएं जो

आम जनता की आव यकता का मुद्दा है। इसकों अमली–जामा पएनाएं। धन्यवाद।

डॉ0 वीरेन्द्र पाल अहलावत (बेरी): अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ माननीय सदस्यों के माध्यम से यह गैर सरकारी प्रस्ताव सदन में लाया गया है। मै भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। इस विशय में एक बहुत बढ़िया प्वांयट है कि कुछ चैनल्ज और डिस्ट्रीबयूटरीज की गाद निकाल कर सफाई की गई है जिसके कारण हरियाणा प्रदे ा की सिचाई की क्षमता बढ़ी है लेकिन साथ–साथ मेरी अपनी कुछ रिजर्वे ान है जो मै सदन के समाने रखना चाहूंगा। सबसे पहली रिजार्वे ान तो यह है कि बहुत पुराना मुद्दा है भाायद यह 35 या 40 साल पुराना मुद्दा हो लेकिन उस समय मुद्दा यह नही था कि आगरा कैनाल की सफाई की जाए मुद्दा यह था कि आगरा कैनाल हैड वर्कस पर हरियाणा सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। इस प्रस्ताव में उस मुद्दे को कहीं पर भी टच नही किया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आगरा कैनाल के हैड वर्कस को अछूता बना दिया क्योंकि उसके एक किलोमीटर नजदीक तक हम चैनल्ज और डिस्ट्रीब्यूटरीय की सफाई भी नही कर सकते। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने एक सुझाव भी दिया था कि हम आगरा कैनाल के हैड वर्कस का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की बजाय कुछ अलग बात सोचे और वह यह कि उस नहर के पैरलल एक और नहर बनाई जाए और उस नहर के जरिए पानी लेकर आएं। उस मामले में मै उतना जरूर कहना चाहूंगा कि

उस समय मैं भी यहां पर बैठा था मुख्य मंत्री महोदय, ने उनकी इस बात को बड़ी उत्सुजक से सुना और भाायद मुख्यमंत्री जी उनकी इस बात को मामने के लिए ललायित भी हो लेकिन मै यह कहना चाहूंगा कि उसे दूसरी एस0 वाई0 एल0 नहर न बना दें क्योंकि हरियाणा प्रदे ा के हिस्सा में एस0 वाई0 एल0 नहर बना दो लेकिन पंजाब के हिस्से में एस0 वाई0 एल0 नहर तैयार नही हो पाई। आप आगरा कैनाल के पैरनाल कैनाल तो बना दे लेकिन यदि उसमें हमें पानी नही मिला तो उसके खर्चे का अन–नैसेसरी बर्डन प्रदे ा पर पड़ेगा क्योंकि हमें आगरा कैनाल के हैड वर्कस के पास तक नही पहुंचने दिया जाता है। हैड वर्कस से एक किलोमीटर दूर तक हमें गाद भी नहीं निकालने दी जाती। अगर हम वहां पर उसके पैरलल कैनाल बनाएंगे तो उससे स्टेट एक्सचैकर पर खामखां बर्डन डालेंगे। एक बात में यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने यू0 पी0 सरकार के साथ बातचीत करके उनको सिर्फ इन बात के लिए राजी किया है कि हरियाणा प्रदे ा की टैरीटरी के अन्दर जो चैनल्ज है या हरियाणो प्रदे ा जिन चैनल्ज और जिन डिस्ट्रीब्यूटरीज के द्वारा पानी लेता है उनकी सफाई का काम हम अपने पैसे से कराएंगे जबकि उन डिस्ट्रीब्यूटरीज और चैनल्ज से जिस एरिया के अन्दर आबपा ाी होती है उस एरिया का सारा का सारा आबियाना हमें यू0 पी0 सरकार का देना पड़ता है। यह समझौता भी गलत किया गया है। उन डिस्ट्रीब्यूटरीज और चैनल्ज की सफाई हम कराएंगे और उनसे सिंचित एरिया से जो आबियाना आएगा वह हम यू0 पी0 सरकार

को दे तो यह बहुत बड़ी गलत बात है। अगर आबियाना यू0 पी0 सरकार को दें और उनकी सफाई हम अपने पैसे से कराएं तो यह प्रदे ा के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। यह ठीक है कि एफीसिएंसी बढी है सारी बात हुई लेकिन यह सारे का सारा खर्चे का वर्डन हम अपने क्यों ले। हरियाणा सरकार को यू0 पी0 सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालना चाहिए कि या तो आबियाना हम लेंगे या आप उन डिस्ट्रीब्यूटरीज और चैनल्ज की सफाई कराएं।

श्री बंसी लालः अब आबियाना कोई भी ले रहा है। आबियाना न यू0 पी0 वाले ले रहे है और न हम ले रहे है।

डॉ0 बीरेन्द्र पाल अहलावतः अगर आप नहीं ले रहे तो अच्छी बात है लेकिन अभी तक उसका प्रोविजन नही हटाया गया है। यों तो कई लोग बिजली का बिल भी नहीं दे रहे हैं। आपने इस बारे में उनके साथ डिस्कस करके इस प्रोविजन को नही हटाया है। सरकार ने इस मुद्दे को उनके साथ टेकअप नही किया है। आप इस प्रोविजन को हटवाते। मै तो यह कहना चाहता हूं कि या तो उन एरियाज के किसानों का आबियाना माफ किया जाए या उन चैनल्ज और डिस्ट्रीब्यूटरीज की सफाई का पैसा यू0 पी0 सरकार से लिया जाए। इस प्रस्ताव में यह इ यू भी होना चाहिए था। इसके अलावा कुछ और बातें भी सदन में आई। उन के मामले में मै यह कहना चाहूंगा, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने भी बताया और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी बताया कुछ एरिया के

अन्दर पेरलल चैनल बनाई है और हमने पानी की आव यकता को देखते हुए उनकी गाद निकाली है ताकि पानी की एफि ाएंसी बढ़ सके। हमारा पानी की सप्लाई का मेन मुद्दा है। हमारा यू0 पी0 सरकार के साथ काफी दिनों से इस नहर के पानी बारे डिफरेंस ऑफ ओपीनियन रहा है, हमारा मतभेद रहा है। हमारा मतभेद यह रहा ै कि इस नहर नियंत्रण हमारा न होने करण यू0 पी0 की सरकार हमं टाईमली पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे रहे इसलिए हम इसका नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहते है। ताकि इस चैनल से जिस एरिया मे पानी जाना है छोड़ा जा सके और उस एरिया को आव यकतानुसार पानी मिल सके। यह हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। मेन बात तो पानी की रैगूले ान की है। इसी प्रकार से यह बात केवल इस इलाके के लिए ही नही बल्कि पूरे प्रदे ा के अन्दर पानी का रैगूले ान परोपरली होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जिस एरिया में किसी मौके पर पानी आव यकता नही होती तो उस वक्त वहां पर यानी बहुतायत में होना है और जब पानी को आव यकता होती है तो पानी नही मिलता। जैसे हमे बताया गया कि रोहतक, सोनीपत, महेन्द्रगढ, रिवाड़ी, नारनौल आदि कई जिले मु कल से एक ही सफल ले पाते है। इसका कारण यह है कि इन एरियाज में पानी की एवेलिबिलिटी न होना है। क्योंकि जब पानी की जरूरत होती है तो पानी मिलता नही है। हमारे प्रदे ा में ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। और अधिकार जगहों पर हमारे यहां नीचे खारा पानी है। अन्डर ग्राइंड वाटर खारी होने कारण एक फसल भी हमको इस कीमत

पर लेनी पड़ती है कि हम अपनी जमीन को रेह के अन्दर कन्वर्ट कर रहे है, जो हमारी इच्छी खासी जमीन है उसके अन्दर हमें ब्रैकि ा वाटर से इरीरो ान करनी पड़ती है। पानी की कमी में एक फसल लेने के लिए हमारा अच्छी खासी उपजाऊ भूमि बर्बाद हो जाती है। इसलिए, इस बात का वि ोश तौर से ध्यान रखा जाए कि बरसात के मौसम में जब पानी की जरूरत न हो तो तब इतना पानी दे दिया आता है जिसकी कोई हद नही और उस वक्त हरेक किसान अपने खेत में मोधा छोड़ देता ताकि उसके खेत में खड़ा ना रहे। इस प्रकार से वह पानी एक दूसरे खेतों में जाकर खड़ा हो जाता है जिस कारण पानी की निकासी न होने के कारण वहां पर खरपवार भी खड़ी हो जाती है। इसलिए मै चाहता हूं कि जो पानी का रैगूले ान है उसको ठीक किया जाये चाहे इसके लिए सरकार को हमारी कुछ कैनाल्ज की ड्रेनज के साथ कनैक्ट करना पड़े। हमें इस कैनाल का पानी ड्रैन्ज में डालकर उन इलाकों में पहुंचाना चाहिए जिन इलाकों में बारि ा कम होती है, जहां इरीगे ान वाटर की फैसीलिटीज नही है, वहां पर ऐसे पानी की खपत की जा सकती है, लेकिन हमारी खेती का इसके लिए बर्वाद न होने दिया जाये यह भी एक अहम मुद्दा है सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर सारे इलाके के अन्दर पीने के पानी की भी दिक्कत रहती है, जिस कारण लोग एक फसल ले पाते है। एक फसल ले

पाने के कारण यही है कि पानी की पूरी अवेलेबिलिटी नही है। पिछली सरकार ने जो यमुना जल समझौता किया उसके तहत हमें जो पानी पहले मिलता था, उसको घटाया गया और हमारे हिस्से का पानी दूसरो प्रदे ाों को दिया गया। उस वक्त हमारे मौजूद मुख्य मंत्री जो अपोजी ान बैचिज पर बैठते थे बड़े जोर भाोर से इस इ यू को उठाया था और कहते थे कि इस फैसले में कमी है, इसको ठीक कर देंगे। अब मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वे पहले वाले फैसले को न माने, या फिर से उस प्वायंट को उठाया जाये और नए सिरे से बातचीत की जाये, य हभी एक बहुत जरूरी प्वायंट है। इस को दूबारा टैकअप किया जाना चाहिए और युमना जल समझौते को रद्द किया जाना चाहिए इसके अलावा एक बात और है, हमारा महेन्द्रगढ़ और गुड़गांव इलाका, जिन इलाकों के अन्दर आगरा कैनाल में सिंचाई होती है, यहा के किसान गरीब है और इन इलाकों के अन्दर चौधरी देवी लाल की सरकार के वक्त बिजली के फ्लैट रेट् से रखे थे क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवार्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा हर फसल की इकोनामी निकाली गई है, उसकी आर्थिक दृश्टि यह पाई गई है कि किसान जितनी भी फसलें उगाता है अगर उसकी सब चीजों का हिसाब किताब लगाकर देखे तो किसान हर फसल के अन्दर घाटे में रहता है। इसलिए किसानों को सस्ती बिजली फ्लैट रेट पर देने की बात होनी चाहिए। अगर उससे बिजली की कोई कीमत बसूल नही की जाए तब भी किसान को घाटा रहता है। मै सरकार से प्रार्थना करूगा कि किसानों को जो जो बिजली फ्लैट

रेट पर दी जाती थी उस नीति को दोबारा से लागू किया जाना चाहिए। मै तो यहां तक कहूंगा कि अगर किसानों को पंजाब सरकार की तरह बिजली फ्री भी कर दी जाए तब भी उसको बहुत ज्यादा ज्यादा फायदा नही होगा लेकिन उसको थोड़ी सी राहत जरूर मिल कसती है हमारा प्रदे ा एक कृशि प्रधान प्रदे ा और यहां के 80 प्रति ात लोग डायरैक्टलीऔर इनडायैक्टली कृशि से जुड़े हुए है। यदि प्रदे ा औ किसान का हित चाहते है उसका विकास चाहते है तो आर्थिक रूप से किसान को ऊपर उठाया जाना चाहिए और उसको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिएं और इसके साथ ही किसान का आबियाना भी माफ किया जाना चाहिए और फसलों के अच्छे भाव भी उनको मुहैया करवाये जाने चाहिए लेकिन यह ज्यादातर हमारे कंट्रोल में नही है। अगर किसानों को अधिक भाव सरकार नही दे सकती है तो कम से कम आबियाना और बिजली की सुविधा तो प्रदान कर ही सकती है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा निवेदन है कि हरियाणा के अन्दर कुछ एरिया मे बिजली के फ्लैट रेट्स रखे गए थे उन इलाको में पानी ज्यादा गहरा है और पानी को खीचने के लिए ज्यादा बिजली की खपत होती है। इसका रेतीला होने के कारण भी पानी की खपत भी ज्यादा होती है इसलिए सरकार द्वारा वहां पर सलैब्स बनाए हुए थे और फ्लैट रेट्स का बिजली दी जा रही थी लेकिन उस सलैब प्रणाली को खत्म कर दिया है। उस एरिया के कश्टों और लोगों की आर्थिक द ाा को देखते हुए इसको दोबारा से लागू करें। अगर हरियाणा सरकार बिजली

चार्जिज और आबियाना को माफ कर देती है तो उससे भी उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार तो नहीं होगा लेकिन उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिलेगी इसलिए सरकार से मेरा निनेदन है कि वह इस बारे सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। इन्हे भाब्दों के साथ में अपनी बात कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री बलवंत सिंह (हसनगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। यह जो प्रस्ताव आया है मैं इसका समर्थन करता हूं। अगर कैनाल का कंट्रोल हरियाणा सरकार के पास आए मैं इसका समर्थन करता हूं और इससे सहमत हूं। हरियाणा प्रदे ा को एक कृशि प्रधान प्रदे ा के रूप में जाना जाता है और यह प्रदे ा कृशि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं यह बात कहूंगा कि आगरा कैनाल का कंट्रोल और रख रखाव यू0 पी0 सरकार के पास है और इसके रख–रखाव और पानी के डिस्ट्रीब्यू ान का काम हरियाणा सरकार को स्वयं अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि हरियाणा प्रदे ा के मेवात और दूसरे इलाको की पूरी तरह से सिंचाई हो सके। इसी प्रकार से मै आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को इस सदन में कहना चाहूंगा यह बात हरियाणा के हित की बात है इसलिए इसका कंट्रोल हरियाणा सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। स्पीकर साहब, इसी प्रकार से एस0 वाई0 एल0 नहर की चर्चा बहुत पुरानी चलती आ रही है। चौधरी बंसी लाल जी जब पहले मुख्य मंत्री थे तब भी और उसके बाद भी जितने भी नेता आते है तभी है सभी हरियाणा प्रदे ा के

लिए एस0 वाई0 एल0 नहर की चर्चा बहुत पुरानी चलती आ रही है। चौधरी बंसी लाल जी जब पहले मुख्य मंत्री थे तब भी और उसके बाद भी जितने भी नेता आते है सभी हरियाणा प्रदे ा के लिए एस0 वाई0 एल0 की चर्चा जरूर करते है और उसे हल करने का आ वासन भी देते है। चौधरी बंसी लाल जी की वर्तमान सरकार को बने हुए करीब 9 मास का समय हो गया है लेकिन उन्होंने अभी तक इस नहर का कोई भी कार्य नही किया है। हरियाणा प्रदे ा की अगर इस नहर का पानी मिल जाएगा तो हरियाणा प्रदे ा खु ाहाल हो जाएगा। अगर यह पानी नहीं आया तो किसानों में खु ाहाली नहीं आएगी। जब तक किसान खु ाहाल नहीं किया है। तब तक हरियाणा में कोई उद्योग धन्धे भी नही लगेगे न पूरी बिजली मिल पाएगी और न ही दूसरी सुविधाएं ही मिल पाएंगी। कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में काफी कुछ कहा है इस सिलसिले में उपयोगिता इसलिए भी जरूरी है ताकि किसानों के खेत में पूरा पानी मिलता रहे। एक खु ाहाल राज्य मे उद्योग लगाए जाते है। हरियाणा का काफी एरिया दिल्ली के नजदीक लगता है। सैंट्रल गवर्नमैंट ने बाहर के उद्योगपतियों को भारतवर्श में उद्योग लगाने के लिए कहां है। मिसाल के तौर पर दिल्ली बाहर चाहे मेरा हल्का ले लो वहां पर कुछ फैक्टरियां लगी हुई है। और फैक्ट्रीयां किसानों की जमीन पर लगी हुई है। लेकिन जिन किसानों की फैक्टरियों लग हुई है और किसानों कोई फायदा नही हुआ उन फैक्ट्रियां का गन्दा तेजाब वाला पानी निकलता है। सापंली में वह पानी खेतों में जाता है और वह खेतों

का बर्बाद करता है। हमने कई बार उनको कहा कि इस पानी को बंद करे लेकिन वे उस पानी को बंद नही करते है। इसके अलावा जिन किसानों की जमीन है उनको कोई फायदा नही मिल रहा है उनके बच्चों को उन फक्ट्रियों मे नही लगाया जा रहा है। जब तक कहते है तो वे कहते है कि इन म ीनों को नही चला पाते है। जिस वहज से आज हरियाणा के बच्चों को पर काम नही मिल पा रहा है। मैने पिछली बार भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि आज हरियाणा के अन्दर जो भी नई म ीनों आ रही है चाहे वे कम्यूटर चलाने के बारे में है ऐसे इन्स्टीच्यूट खोलने चाहिएं ताकि हमारे बच्चे वहां पर लेटेस्ट म ीनों को चलाना सीख सकें और उनको इन फैक्ट्रियों में कम मिल सके।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से बलवन्त सिंह जी को बताना चाहूंगा कि गुरू जम्भे वर यूनिवर्सिटी के अन्दर 62 नए, टैक्नीकल कोर्सिज भाुरू किए है। हमने गुरू जम्भे वर के पूरे स्वरूप को टैक्नीकल कोर्सिज में बदल दिया है। (विघ्न)

श्री बलवन्त सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन दे ा की इक्नौमी कृशि पर टीकी हुई है इसलिए मैने इस बारे में चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय, मै मुख्य मंत्री जी से यह कह रहा था कि फैक्ट्रियों द्वारा जो प्रदूशण फैलाया जा रहा है इसकी रोकथाम के लिए कुछ करें।

श्री बंसी लाल: इस बारे में बहुत तेजी से कार्य चल रहा है।

श्री बलवन्त सिंह: अध्यक्ष महोदय, पिछली सै ान मै भी मैने यही बात उठाई थी कि यह सरकार फैक्टरी वालों की हिदायत दे कि वे वहां पर वही के लड़कों को लगाए। उन्ही को अपनी फैक्ट्री मे नौकरी दें।

Mr. Speaker: Now the House is adjourned till 2.00 p.m. on Monday the 10th March, 1997.

13.30 hours

(The Sabha then adjorned till 2.00 p.m. on Monday, the 10th Macrh,1997).